भारतीय रेल

दिसम्बर – 2019 ₹10

हीरक जयंती वर्ष



कश्मीर की लाइफ लाइन

हीरक विशेषांक के साथ

प्रिय विज्ञापनदाता

रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक मात्र मासिक हिन्दी पत्रिका

भारतीय रेल

में अपना विज्ञापन देकर लाखों उपभोक्ताओं तक अपने उत्पादों की पहुंच बनाएं

भारतीय रेल की विज्ञापन दरें (रुपये में)

विवरण	सामान्य दरें	अनुबंधित दरें
सेकण्ड कवर	10,450/-	9500/-
थर्ड कवर	9500/-	8550/-
पूरा पृष्ठ (विशेष स्थिति जैसे टेक्स्ट से पूर्व व बाद में)	8550/-	7600/-
पूरा पृष्ठ (सामान्य)	7600/-	6650/-
आधा पृष्ठ	5130/-	4180/-
सेन्टर स्प्रेड	15,000/-	13,300/-
सेन्टर स्प्रेड (स्पेशल पोजिशन)	16,500/-	14,700/-

(विज्ञापन चार कलर में)

तीन महीने या ज्यादा समय के लिए लगातार अथवा बारी–बारी विज्ञापन देने पर ही अनुबंधित दरें लागू होंगी

तकनीकी विवरण

पत्रिका का आकार 28 से.मी. x 20.5 से.मी.

छपाई क्षेत्र 23 से.मी. x 16.5 से.मी.

★ पत्रिका का प्रसार समग्र देश में ★

विज्ञापन सामग्री – ई–मेल, आर्टपुल, सीडी

संपर्क करें : व्यापार प्रबंधकः प्रशांत कुमार पट्टनायक, मोबाइल : 9717647367

310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली–110001

टेलीफोन : 011–23382531, 23303665, 23304456

Email : bmpr310rb@gmail.com

भारतीय रेल

रेल मंत्रालय की एकमात्र हिन्दी मासिक पत्रिका

दिसम्बर - 2019 | आरंभ : 1960 | वर्ष : 60 | अंक : 5 | मूल्य : ₹10

संपादक मंडल

विनोद कुमार यादव
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड

मंजुला रंगराजन
वित्त आयुक्त (रेलवे)

सुशांत कुमार मिश्रा
सचिव, रेलवे बोर्ड

राजेश दत्त बाजपेई
कार्यकारी निदेशक, सूचना एवं प्रचार

योगेश अवस्थी
संपादक

संपादकीय कार्यालय
सम्पादक, भारतीय रेल,
कमरा नं. 337-बी, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001
रेलवे टेली - 44519, 9666
editorbhartiyarailrb@gmail.com
editorbhartiyarail@gmail.com

विज्ञापन व सदस्यता हेतु संपर्क
प्रशान्त कुमार पट्टनायक
व्यापार प्रबंधक
कमरा नं. 310, रेल भवन
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001
टेलीफोन : 011-23303665, 23382531
रेलवे टेली. : 43665/9669
bmpr310rb@gmail.com

सदस्यता शुल्क

सर्वसाधारण	₹ 100
रेलकर्मियों के लिए	₹ 90

संपादन सहयोग
रणमत सिंह, पुष्पा देवी

आवरण
श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन पर दौड़ती भारतीय रेल (पढ़ें पेज नं. 10)

फॉलो करें

Twitter	:	@bhartiyarailrb @RailMinIndia
Facebook	:	bhartiyarailpatrika RailMinIndia
Instagram	:	bhartiyarailpatrika railminindia

© भारतीय रेल

भविष्य में वाई-फाई वाले रेलवे स्टेशन डिजिटल बदलाव का केन्द्र बनेंगे : रेल मंत्री



पृष्ठ 6

आईआरसीटीसी का 'गोल्डन चैरियट' ट्रेन चलाने के लिए केएसटीडीसी के संग समझौता 9



रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बना राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का प्रशासनिक कार्यालय 15



प्रमुख खबरें 6-13
नई पहल 14-15



संसद में भारतीय रेल - 16

कोहरे के दौरान रेल परिचालन सुचारु करने की योजना 26
पुरट्चि तलैवर डॉ. एम.जी.आर. सेंट्रल स्टेशन भवन... 28
दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे : विश्व विरासत स्थल... 30
रेलों के अंचल से 32
स्टेशन सौंदर्यीकरण 38
सतर्कता से इस साल सौ से अधिक हाथियों की जान बची 40



डीजल रेल इंजन कारखाना विशेषांक 41

MATRIX SECURITY AND TELECOM SOLUTIONS



PEOPLE MOBILITY MANAGEMENT SOLUTIONS FOR RAILWAYS:

Right People in Right Place at Right Time

- Access Control & Time-Attendance
- Aadhaar Enabled Biometric Attendance System
- Contract Workers Management
- Ethernet, PoE, Wi-Fi and 4G/3G Mobile Broadband
- IP65, BIS, CE, FCC, RoHS and IK08 Certified Terminals
- Seamless Third Party Integration

Multiple Credentials

Face Recognition | Palm Vein | Fingerprint | RF Card | Mobile | PIN (****)

Available on:

On-Premise with **COSEC CENTRA**

On Cloud with **COSEC VYOM**

www.MatrixAccessControl.com

TELECOM

Communication Solutions for Modern Enterprises



- Unified Communication Solutions for Modern Enterprises
- IP PBX with In-Built Support for PRI, CO, GSM and VoIP Trunks
- Video Conference with IP Deskphone
- Universal Media Gateways – PRI, CO, GSM, VoIP
- 4G VoLTE-SIM Compatible FCT with Battery Backup New Launch

www.MatrixTeleSol.com

IP VIDEO SURVEILLANCE

The 3-Dimensional Video Surveillance Security: Persistent, Proficient, Proactive



- Video Management System (VMS)
- Intelligent Video Analytics (IVA)
- Network Video Recorders (NVR)
- IP Cameras
- Mobile Applications

www.MatrixVideoSurveillance.com

MATRIX
TELECOM | SECURITY

MATRIX COMSEC
394-GIDC, Makarpura, Vadodara-390 010, India.
Call: **(+91) 1800-258-7747**
E-mail: **Govt@MatrixComsec.com**

Designed, Developed and Manufactured in INDIA

Available on GeM

www.MatrixComSec.com

संपादकीय

विषम परिस्थितियों में भी सरपट दौड़ती भारतीय रेल

भारतीय रेल के पहिये चौबीसों घंटे चलते ही रहते हैं। विषम परिस्थितियों में भी हमारे रेलकर्मी हमारे यात्रियों को गंतव्य तक पहुँचाने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसी ही एक परिस्थिति है, कोहरा। देश के उत्तरी भागों के सर्दी के महीनों में कोहरा छाया रहता है। ऐसे में, ट्रेनों का परिचालन काफी कठिन कार्य होता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे कर्मठ रेलकर्मियों ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर कोहरे में ट्रेन परिचालन को नियमित करने में सफलता प्राप्त की है। निश्चित रूप से इसका सीधा फायदा सर्दियों के दिनों में ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को हो रहा है।

हर वर्ष सर्दियों के दिनों में कोहरे के कारण ट्रेनों का सही समय पर परिचालन करना मुश्किल हो जाता था। कोहरे के कारण लोको पायलट को सिग्नल तथा पटरियाँ नजर नहीं आती हैं। यात्रियों की संरक्षा के चलते हजारों की संख्या में ट्रेनों की गति कम की जाती हैं अथवा रद्द भी कर दी जाती थीं, जिसके कारण हमारे लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। भारतीय रेल ने इस विषम परिस्थिति में भी ट्रेनों का संचालन सही एवं सुरक्षित ढंग से हो, इसके लिए सतत् प्रयास किए हैं, जिनका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है।

भारतीय रेल ने एक एक्शन प्लान तैयार कर इस पर कार्य किया, जिसके कारण पिछले तीन सालों में कोहरे से विलंबित हुई गाड़ियों के प्रतिशत में काफी गिरावट दर्ज की गई है। 2016 में यह 20 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19 में घट कर मात्र 5.38 प्रतिशत रह गया है। आशा है कि चालू वर्ष में यह प्रतिशत बहुत ही कम रह जाएगा।

एक्शन प्लान के तहत लोको पायलटों को कोहरे के मौसम के दौरान गाड़ी चलाने में सहायता देने के लिए 'फॉग पास डिवाइस' दिया गया है। यह एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) आधारित एक ऐसा हैंड हेल्ड पोर्टेबल उपकरण है, जिसे रेल इंजन में संस्थापित नहीं किया जाता बल्कि कोहरा प्रभावित खंडों में गाड़ी चलाने वाले लोको पायलटों को दिया जाता है। जब कभी जियो-फेन्स रेंज के भीतर कोई लैंडमार्क आता है, तब यह उपकरण कोहरे के मौसम के दौरान श्रव्य-दृश्य अलार्म के माध्यम से क्रू की सहायता करने का कार्य करता है। इस उपकरण के खंड में आने वाले स्टेशनों की लोकेशन, चेतावनी बोर्ड, सिग्नल, समपार फाटक और समपार के लिए सीटी बोर्ड फीड किए जाते हैं। इसमें इंजन की गति, दूरी और लैंडमार्क तक पहुँचने में लगने वाला समय दर्शाया जाता है। अभी तक भारतीय रेलों में 12,205 फॉग पास उपकरण मुहैया कराए गए हैं।

साथ ही, जब ट्रेन स्वचालित ब्लॉक सिग्नल खंडों में चल रही होती है, तब संरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे में एक आशोधित स्वचालित सिग्नल प्रणाली को शुरू किया गया है, जो कोहरे के मौसम के दौरान दो स्टेशनों के बीच गाड़ियों की संख्या को सीमित करती है। लोको पायलटों के सिग्नलों की दृश्यता बढ़ाने हेतु सिग्नल दर्शाने वाले बोर्डों को ल्यूमिनस पेंट किया जा रहा है।

ऐसी ही एक विषम परिस्थिति कश्मीर में भारी बर्फबारी के समय निर्मित होती है। वहाँ पर ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी परिवहन के साधन बंद हो जाते हैं तब भी भारतीय रेल की सेवाएँ चलती रहती हैं, जो स्थानीय यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

भारतीय रेल हमेशा से अभिनव प्रयोगों के लिए जानी जाती है। ऐसे ही एक प्रयोग के तहत राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ने कंडम हुए दो कोच का बेहतरीन उपयोग करते हुए उनको प्रशासनिक खंड में बदल दिया है। साथ ही, दोनों कोच के बीच के भाग को पुराने समय के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तर्ज पर तैयार किया है, जो संग्रहालय देखने आने वाले लोगों के आकर्षण का एक अन्य केन्द्र बन गया है। आप भी एक बार जरूर देखने जाएँ।

इस अंक में हम डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। बेहद कम समय में डीरेका ने डीजल रेल इंजन को विद्युत रेल इंजन में परिवर्तित कर अद्भुत सिद्धि हासिल की है।

आपको यह अंक कैसा लगा, हमें जरूर बताएँ। आपके सुझाव ही हमारे मार्गदर्शक होंगे। ■

भविष्य में वाई-फाई वाले रेलवे स्टेशन डिजिटल बदलाव का केन्द्र बनेंगे : रेल मंत्री

रेलटेल को आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूने और 10,000 करोड़ रूपये की कंपनी बनने का लक्ष्य तय करने की आवश्यकता है : रेल मंत्री



रेलटेल के 20वें स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को सम्बोधित करते हुए रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल। मंच पर उपस्थित हैं, रेल राज्यमंत्री श्री सुरेश अँगडी

भारतीय रेल के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रेलटेल ने 25 नवम्बर, 2019 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल इस अवसर पर मुख्य अतिथि तथा रेल राज्यमंत्री श्री सुरेश अँगडी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, श्री विनोद कुमार यादव, रेलवे बोर्ड के सदस्य (सिग्नल एवं दूरसंचार) श्री प्रदीप कुमार, रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य तथा रेलवे, दूरसंचार विभाग (डॉट) एवं रेलवे के पीएसयू के वरिष्ठ अधिकारी और दूरसंचार क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

रेल मंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलटेल की अभूतपूर्व यात्रा के लिए उसे बधाई देते हुए कहा कि रेलटेल सही मायनों में नई सदी का पीएसयू है, जिसका इतिहास तो संक्षिप्त है, लेकिन उज्ज्वल भविष्य काफी लंबा है। उन्होंने कहा कि रेलटेल ने 5,400 से भी अधिक रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सेवा के जरिए देश के हर कोने में वाई-फाई उपलब्ध करा कर उल्लेखनीय काम किया है। ये स्टेशन आने वाले समय में डिजिटल बदलाव का केन्द्र बनाने में मदद करेंगे।

श्री अँगडी ने इस अवसर पर कहा कि रेलटेल ने अपनी शुरुआत 15 करोड़ रुपये से की थी और अब यह 1,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कंपनी है। उन्होंने छोटी-सी अवधि में ही 5,400 से भी अधिक स्टेशनों को वाई-फाई से कनेक्ट करने के लिए रेलटेल को बधाई दी। श्री अँगडी ने रेलटेल के सीएमडी को 'भारतनेट' के तहत ग्राम पंचायतों को आपस में तेजी से कनेक्ट करने की सलाह दी, ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को भी वाई-फाई सेवा मिल सके।

रेलटेल के सीएमडी श्री पुनीत चावला ने बताया कि रेलटेल बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद दूरसंचार क्षेत्र के उन चुनिंदा पीएसयू में शामिल है जो लगातार मुनाफा कमा रहे हैं, लाभांश का भुगतान कर रहे हैं और कर्ज मुक्त हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में रेलटेल का कारोबार 1,017 करोड़ रुपये का रहा और उसका परिचालन मार्जिन 184 करोड़ रुपये आंका गया। ■



रेल मंत्रालय ने संभावित निवेशकों के लिए समान उद्देश्य वैगन निवेश योजना को और अधिक उदार बनाया

रेल मंत्रालय ने संभावित निवेशकों के लिए समान उद्देश्य वैगन निवेश योजना (जीपीडब्ल्यूआईएस) को और अधिक उदार बनाया है। रेलवे ने यह कदम निवेशकों तथा एंड यूजरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उठाया है। योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

एंड यूजरों (लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के अलावा) को भी वैगन के खाली लौटने की दिशा में अपनी रेकों में तीसरे पक्ष के कार्गो लदान की अनुमति दी गई है। इससे न केवल जीपीडब्ल्यूआईएस रेकों के खाली खड़े रहने के समय में कमी आएगी, बल्कि माल भाड़ा रियायत से एंड यूजर निवेशकों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

सामान्य उद्देश्य के वैगनों पर डिजाइन ऋण शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गयाहै। इससे वैगन खरीदने के लिए प्रारंभिक आवश्यकता में काफी कमी आएगी।

माल ढुलाई वैगन का उपयोग करने वालों, उद्योग जगत तथा अन्य हितधारकों से सामान्य उद्देश्य के वैगनों (जीपीडब्ल्यू) की बेहतर और समय से उपलब्धता की पुरानी मांग को पूरा करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में सामान्य उद्देश्य के वैगनों में निवेश के लिए योजना लागू की गई।

योजना लांच किए जाने के बाद से 163 रेक मंजूर किए गए हैं और 20 रेक पहले से ही काम में लगाए गए हैं। इन रियायतों के फलस्वरूप आशा की जाती है कि यह योजना संभावित निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक होगी। ■

रेल मंत्री व रेल राज्यमंत्री की महाप्रबंधकों संग उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

- **नए यातायात को आकर्षित कर माल ढुलाई में वृद्धि के लिए उद्योग जगत के साथ संवाद पर जोर**

रेल एवं वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेल राज्यमंत्री श्री सुरेश अँगडी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव, रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्यों और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने 20 नवम्बर को रेल भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों (यूनिट) के सभी महाप्रबंधकों (जीएम) तथा मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।



रेल भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी महाप्रबंधकों तथा मंडल रेल प्रबंधकों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए रेल एवं वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल

बैठक के एजेंडे में अक्टूबर, 2019 तक के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा की गई, जिसमें सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन, समय की पाबंदी, माल ढुलाई, आय-व्यय, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का सृजन और रोलिंग स्टॉक का उत्पादन शामिल थे।

श्री गोयल ने भारतीय रेल की समय-पाबंदी को बेहतर करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे की सराहना की। उन्होंने मंडल रेलवे से जुड़े महत्त्वपूर्ण कार्य-प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की समीक्षा करते समय विभिन्न क्षेत्रों में कार्य-प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए मंडल द्वारा किये गये प्रयासों की प्रशंसा की। श्री गोयल ने महाप्रबंधकों से विभिन्न पहल करने को कहा और नए यातायात को आकर्षित कर माल ढुलाई में वृद्धि के लिए उद्योग जगत् के साथ संवाद करने की सलाह दी। साथ ही, श्री गोयल ने महाप्रबंधकों को गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) और अन्य कोचिंग मदों, जैसे कि पार्सल के जरिये आय बढ़ाने हेतु नए अभिनव विचारों की तलाश करने के निर्देश दिये। श्री गोयल ने महत्त्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किये, ताकि रेलवे के कार्य प्रदर्शन एवं दक्षता को और बेहतर किया जा सके। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि व्यय में कमी के लिए हरसंभव प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे के कामकाज से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की जरूरत है।

रेल राज्य मंत्री श्री अँगडी ने विशेष बल देते हुए कहा कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और भारतीय रेल में 'शून्य दुर्घटना' सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया जाना चाहिए। श्री अँगडी ने समय की पाबंदी को बेहतर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और मंडलों की सराहना की। उन्होंने ट्रेनों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता के साथ क्षेत्रीय रेलवे को पैसेंजर ट्रेनों में 'फर्स्ट एड बॉक्स' की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, यह भी निर्देश दिया कि सभी क्षेत्रीय रेलों एवं मंडलों को आय बढ़ाने और व्यय घटाने के लिए हरसंभव प्रयास करने चाहिए।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव ने चालू वर्ष के दौरान अब तक क्षेत्रीय रेलवे के कार्य-प्रदर्शन की विस्तार से समीक्षा करते हुए महाप्रबंधकों को रेलगाड़ियों के परिचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। श्री यादव ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सभी दुर्घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया जाना चाहिए और इस दिशा में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। श्री यादव ने मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की समय-पाबंदी में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की, जो पिछले वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर) के 67 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने महाप्रबंधकों को माल ढुलाई में वृद्धि के लिए विभिन्न पहल करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नई लाइनों को चालू करने, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजनाओं को तय समय के भीतर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर फोकस होना चाहिए, ताकि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के साथ-साथ गतिशीलता (मोबिलिटी) भी बेहतर हो सके। श्री यादव ने उत्पादन इकाइयों से लोकोमोटिव एवं रेल डिब्बों का उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध किया, ताकि भारतीय रेल में रोलिंग स्टॉक की बढ़ी हुई जरूरत को पूरा किया जा सके। ■

यूरोपीय यूनियन के शिष्ट मंडल के साथ रेल मंत्री की बैठक

- **भारतीय रेल बड़ी आधारभूत परियोजनाओं, नए उत्पाद और टेक्नोलॉजी के लिए 'मेक इन इंडिया' पर फोकस के साथ तेजी से प्रगति कर रही है : रेल मंत्री**

यूरोपीय यूनियन में मोबिलिटी तथा परिवहन आयुक्त सुश्री वायोलेटा बल्क के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल रेल भवन में रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव से मिला। बैठक में सुश्री वायोलेटा बल्क ने पिछले दो वर्षों में भारतीय रेल और यूरोपीय यूनियन की सक्रियता की प्रशंसा की और डिजिटलीकरण, हरित परिवहन, यूरोपीय यूनियन-एशिया रेल संपर्क और साझा नवाचार पर फोकस के साथ भारतीय रेल-यूरोपीय यूनियन साझेदारी को और अधिक सक्रियता से मजबूत बनाने को कहा।

श्री गोयल ने आयुक्त और उसके शिष्टमंडल को धन्यवाद दिया और कहा कि भारतीय रेल बड़ी आधारभूत परियोजनाओं, नए उत्पादों और टेक्नोलॉजी के लिए 'मेक इन इंडिया' पर फोकस के साथ तेजी से प्रगति कर रही है। दोनों पक्षों ने भारतीय रेल तथा यूरोपीय यूनियन के बीच आयोजित संगोष्ठी के परिणामों पर काम करने पर सहमति व्यक्त की।



यूरोपीय यूनियन के शिष्ट मंडल के साथ बैठक करते हुए रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल

रेल के समान विषयों पर भारत-यूरोपीय यूनियन संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें यूरोपीय यूनियन के मोबिलिटी तथा परिवहन प्रभाग तथा मानकीकरण प्रभाग का शिष्टमंडल और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसमें रेल सुधारों, रेल सुरक्षा और टेक्नोलॉजी (सिग्नल ईआरटीएमएस सहित) खरीद मानकीकरण डिजिटिलीकरण तथा नवाचार पर विचार-विमर्श किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव ने भारतीय रेल की क्षमता बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत कार्यों में तेजी लाने के उपायों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता है।

यूरोपीय यूनियन शिष्टमंडल का नेतृत्व यूरोपीयन यूनियन मोबिलिटी और परिवहन प्रभाग में निदेशक भू-परिवहन सुश्री एजिलाबेथ वर्नर ने किया। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व रेल मंत्रालय में प्रधान कार्यकारी निदेशक/आधाभूत संरचना श्री आर.एन. सिंह ने किया। ■

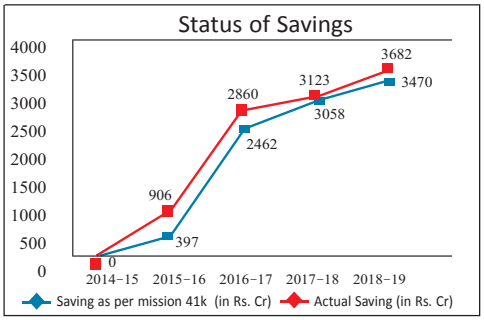
भारतीय रेल ने मुक्त पहुंच के तहत मान्य लाइसेंसशुदा के रूप में उत्तर रेलवे के लिए पंजाब में बिजली की खरीद शुरू की

भारतीय रेल अपने परिचालन की लागत को घटाने के उद्देश्य से अनेक उपाय कर रही है। उपभोक्ता के स्थान पर मान्य लाइसेंसशुदा के रूप में बिजली की सीधी खरीद करना इन उपायों में प्रमुख है।

'मिशन 41के' दस्तावेज का लक्ष्य समन्वित रेल ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 2025 तक 41,000 करोड़ रुपये की बचत करना है। रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आरईएमसीएल) और राइट्स लिमिटेड की ओर से धीरे-धीरे उपभोक्ता के स्थान पर मान्य लाइसेंसशुदा के रूप में इस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, मान्य लाइसेंसशुदा दर्जे के कारण, भारतीय रेल मुक्त पहुंच के तहत केन्द्रीय एवं राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए ह्वीलिंग शुल्कों का भुगतान करके किसी बिजली उत्पादक कंपनी से सीधे तौर पर बिजली खरीदने के लिए अधिकृत है।

इस क्रम में, भारतीय रेल ने 24 नवंबर, 2019 से 11 ट्रैक्शन उप-स्टेशनों के लिए पंजाब में 35 मेगावॉट बिजली की खरीद शुरू की है, जिसके परिणामस्वरूप 56 करोड़ रुपये की सालाना अनुमानित बचत होगी। मुक्त पहुंच की श्रेणी में पंजाब के जुड़ने से, भारतीय रेल अब 11 राज्यों में मान्य लाइसेंसशुदा के रूप में मुक्त पहुंच के तहत लगभग 1,400 मेगावॉट (70%) बिजली प्राप्त कर रही है। इन प्रयासों से प्रतिवर्ष 3,500 करोड़ रुपये की बचत हो रही है और नवंबर, 2015 में मुक्त पहुंच के तहत बिजली की आपूर्ति शुरू होने के बाद 12,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

इन प्रयासों से भारतीय रेल का वित्तीय बोझ घटने का रास्ता साफ होगा। इन प्रयासों से भारतीय रेल के लिए वर्ष 2015 से लगातार बिजली की सबसे सस्ती दर बनाए रखने में मदद मिली है। ■



आईआरसीटीसी का 'गोल्डन चैरियट' ट्रेन चलाने के लिए केएसटीडीसी के संग समझौता

• **यह रेलगाड़ी दक्षिण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देगी : रेल राज्यमंत्री**

भारतीय रेल की पर्यटन इकाई 'भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड' (आईआरसीटीसी) ने 'गोल्डन चैरियट' ट्रेन के संचालन और प्रचार के लिए 19 नवम्बर को नई दिल्ली में रेल राज्यमंत्री श्री सुरेश अँगडी और कर्नाटक के पर्यटन मंत्री श्री सी. टी. रवि की मौजूदगी में कर्नाटक राज्य पर्यटन निगम (केएसटीडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव के अलावा बोर्ड के अन्य सदस्य तथा आईआरसीटीसी और केएसटीडीसी के अधिकारी भी मौजूद थे।



'गोल्डन चैरियट' ट्रेन के संचालन और प्रचार के लिए भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड और कर्नाटक राज्य पर्यटन निगम के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह का एक दृश्य

केएसटीडीसी जल्दी ही रेलगाड़ी का परिचालन आईआरसीटीसी को सौंपने जा रहा है। आईआरसीटीसी केरल के पर्यटन स्थलों के अनुरूप 'गोल्डन चैरियट' ट्रेन के परिचालन समय और ठहराव वाले स्थानों में बदलाव करने जा रहा है। ट्रेन की समय-सारिणी में यह बदलाव राज्य के इतिहास, संस्कृति, वन्य जीव और प्राकृतिक आकर्षणों के अनुरूप होगा। इसमें बांदीपुर, मैसूर, हालीबीड, चिकमंगलूर, हम्पी, बीजापुर और गोवा जैसे पर्यटन स्थलों को जोड़ने का प्रस्ताव भी है। आईआरसीटीसी रेलगाड़ी की आंतरिक साज-सज्जा में बदलाव करने के बाद मार्च, 2020 से इसका परिचालन शुरू कर देगा।

इस अवसर पर रेल राज्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और देश में कम-से-कम पांच पर्यटन स्थलों को देखने जाने के देशवासियों से उनके स्पष्ट आह्वान की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। श्री अँगडी ने आईआरसीटीसी और केएसडीटीसी को टिकटों की कीमतें प्रतिस्पर्धात्मक रखने का निर्देश दिया ताकि आम लोग भी इस ट्रेन की सुविधा का लाभ उठा सकें।

श्री अँगडी ने कहा कि यह ट्रेन दक्षिण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर कर्नाटक के पर्यटन मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार और केएसटीडीसी 2008 से ही 'गोल्डन चैरियट' ट्रेन का संचालन और रखरखाव देख रही है। यह पूरे दक्षिण भारत की पहली और एकमात्र लक्जरी रेलगाड़ी है। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और धरोहरों का दर्शन कराती है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आईआरसीटीसी और केएसटीडीसी के बीच आज हुआ समझौता दोनों के लिए लाभदायी होगा और इस साझेदारी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि आईआरसीटीसी और केएसटीडीसी, दोनों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए 'गोल्डन चैरियट' ट्रेन का सफल संचालन और प्रचार करेंगे। उन्होंने इस परियोजना के लिए हरसंभव जरूरी मदद और सहयोग का आश्वासन दिया।



'गोल्डन चैरियट' रेलगाड़ी का परिचालन वर्ष 2008 में शुरू हुआ था। यह कर्नाटक सरकार और भारतीय रेल का संयुक्त उपक्रम है। अठारह डिब्बों वाली इस रेलगाड़ी में यात्रियों के लिए 44 कमरे हैं जिसमें एक बार में 84 यात्री सफर कर सकते हैं। यह रेलगाड़ी कर्नाटक तथा दक्षिण भारत के अन्य राज्यों के महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की यात्रा कराती है।

आईआरसीटीसी को देशभर में कई पर्यटन रेल परियोजनाओं को संचालित करने की विशेषज्ञता और अनुभव है। यह बेहद लोकप्रिय 'महाराजा एक्सप्रेस' लक्जरी रेलगाड़ी का भी संचालन करती है। इसका परिचालन वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। ■

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया

30 नवम्बर को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, उनके साथ पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री ए. के. गुप्ता, मध्य रेल के अपर महाप्रबंधक डॉ. आर. बद्री नारायण, मंडल रेल प्रबंधक, मुंबई मंडल, श्री शलभ गोयल, मध्य रेल तथा आईआरएसडीसीएल, एमआरवीसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

अध्यक्ष रेलवे बोर्ड ने अपने निरीक्षण के दौरान, श्री एस. के. लोहिया, एमडी और सीईओ, आईआरएसडीसीएल ने सीएसएमटी स्टेशन पुनर्विकास योजना की व्याख्या की। बाद में, उन्होंने सीएसएमटी उपनगरीय कॉनकोर्स, स्टार चैंबर, सेल्फ टिकटिंग जोन, डीआरएम के एनेक्सी भवन के समीपस्थ क्षेत्र, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 18 तक नए विकसित यात्री गलियारे का निरीक्षण किया। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड ने प्लेटफॉर्म नंबर 18 से सटे हेरिटेज गली तक प्रस्तावित हार्बर लाइन लैंडिंग की भी समीक्षा की।



छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए अधयक्ष, रेलवे बोर्ड

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने रेल अधिकारियों के साथ यात्रियों की बढ़ती मांगों जैसे मुंबई से अतिरिक्त ट्रेनों को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि के लिए भविष्य की कार्य योजना पर भी चर्चा की और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जल्द पूरा करने की बात कही। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की अच्छी साफ-सफाई एवं रख-रखाव के लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया। ■

भारतीय रेल ने कश्मीर घाटी में रेल सेवाएं बहाल कीं

सर्दी के मौसम में कश्मीर घाटी में बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही अक्सर थम जाती है। इस स्थिति में कश्मीर घाटी में ट्रेन परिचालन को परिवहन का श्रेष्ठ माध्यम समझा जाता है। बारामूला से बनिहाल तक (138 किलोमीटर) क्षेत्र के बीच स्थानीय यात्री रेलगाड़ी से सफर करते हैं। इनके लाभ के लिए भारतीय रेल ने ट्रेन सेवाओं की बहाली की है। सरकार तथा रेल पुलिस द्वारा सुरक्षा का जायजा लेने और उनके आश्वासनों के बाद कश्मीर घाटी में रेल सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया।

हाल में 7 नवम्बर को भारी बर्फबारी के कारण रेल पटरियों पर 20 से 45 सेंटीमीटर बर्फ जम गई थी। बर्फ हटाने वाली मशीनें रेल पटरियों पर लगाई गई। रेल पटरियों पर सुरक्षित परिचालन की अनुमति से पहले श्रीनगर-बारामूला तथा श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन को ठीक किया गया। 10 नम्बर को श्रीनगर-बारामूला सेक्शन के बीच निरीक्षण तथा ट्रायल का काम किया गया। यही कार्य 16 नवम्बर को श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन पर किया गया।



12 नवम्बर, 2019 से सवेरे 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से श्रीनगर-बारामूला के बीच रेलगाड़ियों की दो जोड़ियां चलाई गईं। इसी तरह 17 नवम्बर को श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल सेवाएं प्रारंभ की गईं। अब सेवाओं के समय में वृद्धि कर दी गई है और सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक रेल परिचालन हो रहा है। सेक्शन की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति भी बहाल कर दी गई है। अभी कुल 16 रेलगाड़ियां चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी सवेरे 8 बजकर 5 मिनट पर चलती है और सभी ट्रेन सेवाएं शाम 5 बजे समाप्त हो जाती हैं। ■

भारतीय रेल ने भर्तियों के एक चरण का सफलतापूर्वक आयोजन किया

- **विश्व में भर्तियों का एक सबसे बड़ा आयोजन है**

रेल मंत्रालय ने महत्त्वपूर्ण सुरक्षा और परिचालन पदों को भरने के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसे दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया में से एक कहा जा सकता है।

सहायक लोको पायलटों (एएलपी) और तकनीशियन (सीईएन 01/2018) तथा अन्य लेवल-I (पूर्ववर्ती ग्रुप-डी) पदों (सीईएन 02/2018) के लिए दो अधिसूचनाएं 1.27 लाख रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 2018 में जारी की गई थी।

सहायक लोको पायलट (एएलपी) और तकनीशियनों के कुल 64,371 पद के लिए लगभग 47.45 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। लेवल-I पदों (पूर्ववर्ती ग्रुप-डी) के लिए 63,202 रिक्तियां थीं, जिनके लिए लगभग 1.9 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। कुल मिलाकर 2.4 करोड़ आवेदकों ने आवेदन किया, जिससे यह सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया बन गई।

एएलपी एंड टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) 9 अगस्त से 4 सितंबर, 2018 तक देश के 166 शहरों में स्थित 440 परीक्षा केंद्रों पर 11 दिन तक आयोजित किए गए। इनमें 36.42 लाख आवेदक हाजिर हुए। इस भर्ती के लिए दूसरे चरण की सीबीटी का आयोजन 21 से 23 जनवरी, 2019 तक 9 शिफ्टों में किया गया, जिसमें लगभग 88 प्रतिशत उपस्थिति रही।

कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट 10 मई, 2019 को केवल एएलपी के लिए आयोजित किया गया था। जिसमें उपस्थिति लगभग 84 प्रतिशत रही थी। इसके बाद कागजात सत्यापन और चिकित्सा जांच हुई।

एएलपी और तकनीशियन (सीईएन 01/2018) के लगभग 17,500 पदों के लिए पैनल तैयार किया गया। मेडिकल अपील मामलों के कारण बाकी के पैनलों की प्रक्रिया चल रही है। बाकी पैनलों के बारे में क्षेत्रीय रेलवे को जल्दी ही सलाह दी जाएगी।

सहायक लोको पायलट और तकनीशियनों के 64,000 से अधिक पदों के लिए अप्रत्याशित रूप से 47.45 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए।

लेवल-I (पूर्ववर्ती ग्रुप-डी) के 63,000 से अधिक पदों के लिए लगभग 1.17 करोड़ उम्मीदवार उपस्थित हुए।

जूनियर इंजीनियर (जेई), डिपो मैटेरियल सुपरिटेंडेंट (डीएमएस) और केमिकल मेटेलर्जी असिस्टेंट (सीएमए) के 13,500 से अधिक पदों के लिए 24.75 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और जांच के अधिकतम संभावित स्तर सुनिश्चित किए गए।

परीक्षा प्रक्रिया में आईटी से जुड़ी विशेषताओं को शामिल किया गया। कोई भी दो प्रश्नपत्र एक जैसे नहीं थे।

लेवल-1 पदों (पूर्ववर्ती ग्रुप-डी) के लिए बड़ी सीबीटी 17 सितंबर, 2018 को शुरू हुई थी और इसका 17 दिसंबर, 2018 को सफलतापूर्वक समापन हुआ। परीक्षा 16 शहरों के 405 परीक्षा केंद्रों पर 51 दिन तक 152 पारियों में आयोजित की गई थी। योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या 1,89,82,719 (लगभग 1.90 करोड़) थी, जिसमें से 1,17,14,754 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इस प्रकार उपस्थिति लगभग 61.71% रही। इसके बाद शारीरिक दक्षता टेस्ट (पीईटी), कागजात सत्यापन और चिकित्सा जांच का आयोजन हुआ।

लेवल-1 (सीईएन 02/2018) के पदों के लिए, रेलवे को लगभग 53,000 पदों के पैनल प्रस्तुत किए गए हैं। मेडिकल अपील मामलों के कारण बाकी के पैनल प्रक्रियाधीन हैं। बाकी पैनलों के बारे में जल्द ही क्षेत्रीय रेलवे को सलाह दी जाएगी।

जेई/डीएमएस/सीएमए पदों के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 22 मई से 2 जून, 2019 तक और 26 से 28 जून, 2019 तक 24.75 लाख उम्मीदवारों के लिए प्रथम चरण का कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित किया। यह परीक्षा पूरे भारत के 109 शहरों में स्थित 356 परीक्षा केंद्रों पर 12 दिनों में 35 पारियों में आयोजित की गई। इसमें उपस्थिति लगभग 62.5% रही।

इस भर्ती के लिए दूसरे चरण के सीबीटी का 28 अगस्त से 1 सितंबर, 2019 तक 10 शिफ्टों में आयोजन किया गया। उपस्थिति लगभग 88% थी। दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शीघ्र ही सूचित किया जाएगा।

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) वेब-साइट, व्यक्तिगत एसएमएस और ईमेल पर नियमित अपडेट के माध्यम से उम्मीदवारों के साथ सीधे और तात्कालिक बातचीत की प्रक्रिया का पालन करता है। उम्मीदवारों से अपील की जाती है कि वे केवल इन आधिकारिक संचारों पर ही ध्यान दें। सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे झूठे प्रचार और अफवाहों पर ध्यान न दें। इनमें से कई का उद्देश्य वास्तविक उम्मीदवारों को भ्रमित करना और परीक्षा के लिए उनकी तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालना है। ■

भारतीय रेल पत्रिका की सदस्यता एवं प्राप्ति हेतु संपर्क करें

011-47845381

सोमवार से शुक्रवार (सुबह 10 से 1 एवं दोपहर 2 से 5 बजे तक)
editorbhartiyarailrb@gmail.com | bmpr310rb@gmail.com

भारतीय रेल ने आईआसीटीसी के जरिए राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेनों में खानपान शुल्क और व्यंजन सूची को युक्तिसंगत बनाया

रेल यात्रियों के लिए विविधता, स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने व्यंजन सूची को युक्तिसंगत बनाया है और खान-पान सेवाओं के लिए शुल्क में संशोधन किया है। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेनों में संशोधन 6 वर्ष बाद किया गया है। पिछला संशोधन वर्ष 2013 में किया गया था, जबकि मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनों के मानक भोजन के शुल्क में परिवर्तन 7 वर्ष के बाद किया गया है।

इसमें पिछला संशोधन वर्ष 2012 में किया गया था। उचित कीमतों पर पहुंचने के लिए, इन सेवाओं के व्यंजन सूची और शुल्क के पुनरीक्षण और सिफारिश के लिए रेलवे बोर्ड ने एक समिति मनोनीत की थी। समिति ने भारतीय रेल के यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता और स्वच्छ भोजन प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लागत के सभी पहलुओं की वैज्ञानिक रूप से जांच की। समिति की रिपोर्टों के आधार पर, संशोधित व्यंजन और शुल्क अधिसूचित किया गया है। ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता कच्चे माल की लागत को ध्यान में रखते हुए थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदि पर निर्भर है, जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं।

भारतीय रेल की ट्रेनों में खान-पान सेवाएं आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और इसकी दो श्रेणियां हैं यानी राजधानी/शताब्दी/दुरंतो ट्रेनों में पूर्व भुगतान सेवाएं, जिसमें टिकट में खान-पान शुल्क (ऑप्ट-इन आधार पर) और अन्य मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनों में भुगतान के बाद खान-पान सेवा शुल्क शामिल हैं, जिसमें मानक भोजन और अन्य खाद्य पदार्थ बिक्री पर उपलब्ध कराए जाते हैं। किफायती, क्षेत्रीय भोजन की उपलब्धता और यात्रियों को मानक भोजन में विविधता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया गया है। मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनों की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:-

- जनता भोजन की 20 रुपये की दर में कोई बदलाव नहीं

भारतीय रेल का भोजन और सम्पूर्ण सेवाओं की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार पर जोर

खान-पान शुल्क में संशोधन केवल उन यात्रियों पर लागू होगा जो ट्रेनों में खान-पान का विकल्प चुनेंगे

जनता भोजन की 20 रुपये की दर में कोई बदलाव नहीं

क्षेत्रीय वस्तुओं/व्यंजनों/स्वाद के साथ जलपान 50 रुपये की दर से विविध रूप में शुरू

किफायती, क्षेत्रीय भोजन की उपलब्धता और यात्रियों को मानक भोजन में विविधता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान

व्यंजन सूची के नाम पर अतिरिक्त शुल्क रोकने के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में बिक्री के लिए अलग-अलग व्यंजन सूची की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि समोसे, पकोड़े आदि जलपान जैसी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

- अब यात्रियों के लिए क्षेत्रीय भोजन की अधिक वैरायटी उपलब्ध होगी। क्षेत्रीय वस्तुओं/व्यंजनों/ स्वाद के साथ जलपान 50 रुपये की दर से शुरू किया जा रहा है। इसकी मात्रा 350 ग्राम होगी और व्यंजन सूची आईआरसीटीसी द्वारा तय की जाएगी।
- इसकी लोकप्रियता को देखते हुए बिरयानी को एक मानक भोजन के रूप में पेश करने का निर्णय किया गया है। आईआरसीटीसी तीन प्रकार की बिरयानी (सब्जी, अंडा और चिकन) क्रमश: 80 रुपये, 90 रुपये और 110 रुपये की दर से उपलब्ध कराएगा।
- अंडा करी और मानक शाकाहारी के साथ मौजूदा मानक गैर-शाकाहारी भोजन के अलावा चिकन करी को मानक गैर- शाकाहारी भोजन के विकल्प के रूप में शुरू करने का भी निर्णय किया गया है। मानक भोजन की तीन श्रेणियां होंगी - मौजूदा दो के मुकाबले मानक शाकाहारी भोजन, मानक गैर-शाकाहारी भोजन (2 अंडे की करी के साथ) और मानक गैर-शाकाहारी भोजन (चिकन करी के साथ)।

भारतीय रेल अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उपरोक्त युक्तिकरण के साथ सेवाओं की गुणवत्ता और वैरायटी में और सुधार की उम्मीद है। सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी पहले से ही निम्नलिखित कदम उठा रहा है : -

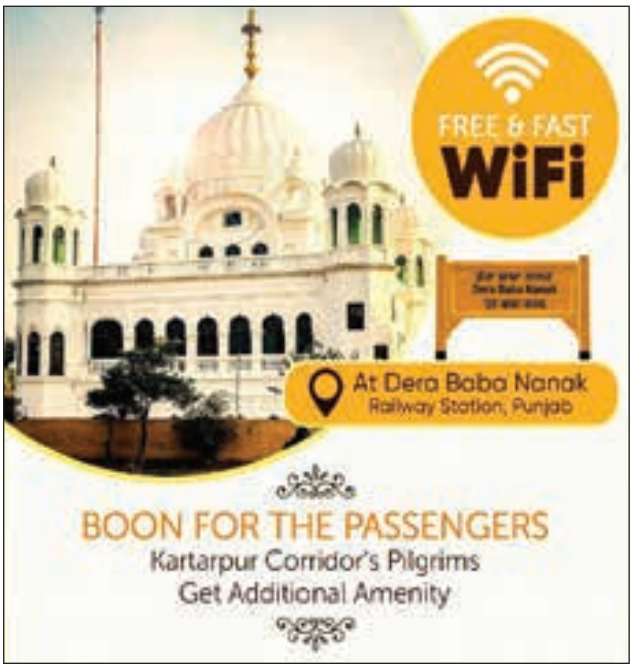
- ट्रेनों में भोजन तैयार करने और उसकी आपूर्ति आईआरसीटीसी प्रबंधित रसोई से किया जाएगा।
- रसोई में खाद्य उत्पादन और स्वच्छता की वास्तविक समय निगरानी रखने के लिए, आईआरसीटीसी ने रेल दृष्टि और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर सीधे निगरानी की सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।
- स्वच्छता की स्थिति और खाद्य सुरक्षा तथा भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) में उच्च गुणवत्ता वाले मानकों को शामिल किया गया है।
- सेवाओं की गुणवत्ता का लेखा परीक्षण करने के लिए अनिवार्य बाह्य लेखा परीक्षा प्रतिष्ठित और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाएगी।
- आईआरसीटीसी अपने भोजन की अच्छी गुणवत्ता वाली बॉयोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और उसकी क्यूआर कोडिंग शुरू करेगा।

पूर्व भुगतान वाली ट्रेनों के टिकट के कुल किराए में उन यात्रियों के लिए दर में 3% से 9% की वृद्धि होगी, जो भोजन का विकल्प चुनेंगे। संशोधित खान-पान शुल्क राजधानी/ शताब्दी/दुरंतो ट्रेनों पर 29 मार्च, 2020 से और अन्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ■

भारतीय रेल ने डेरा बाबा नानक स्टेशन पर वाई-फाई एवं करतारपुर कॉरिडोर परियोजना के लिए आईसीपी कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई

भारतीय रेल के आदेशानुसार, रेलवे का मिनीरत्न सार्वजनिक का क्षेत्र उपक्रम रेलटेल ने पंजाब के ऐतिहासिक डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन पर रेलवायर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे तीर्थयात्री एक त्वरित वाई-फाई सेवा का उपयोग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'करतारपुर कॉरिडोर परियोजना' का 9 नवंबर, 2019 को उद्घाटन किया था। इससे अधिक से अधिक लोगों को आवागमन में स्टेशन का उपयोग करने में मदद मिलेगी। इस स्टेशन पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस मुफ्त रेलवायर वाई-फाई का कोई भी यात्री रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर उपयोग कर सकता है। सुल्तानपुर लोधी स्टेशन पर भी वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस स्टेशन पर डेरा बाबा नानक के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ है।

रेलटेल ने देश के 5,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई है। जल्दी ही सभी व्यवहार्य रेलवे स्टेशनों (हाल्ट को छोड़कर) में मुफ्त वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रियों को वाई-फाई की सुविधा रेलटेल की खुदरा ब्रॉडबैंड पहल रेलवायर के तहत उपलब्ध कराई जा रही है। वाई-फाई का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को स्मार्टफोन के वाई-फाई मोड पर स्विच ऑन करके रेलवायर वाई-फाई नेटवर्क का चयन करना होगा।



उपयोगकर्ता को इस होमपेज पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उपयोगकर्ता को संदेश बॉक्स में एसएमएस के रूप में वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिलेगा जो रेलवायर के होम पेज में दर्ज किया जाना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद उपयोगकर्ता हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग तथा इंटरनेट ब्राउजिंग शुरुआत कर सकता है।



रेलटेल को गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक स्टेशन पर एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) में 8 एमबीपीएस बीडब्ल्यू उपलब्ध कराने का दायित्व एनआईसी को सौंपा गया है। भारत सरकार की प्रतिष्ठित 'करतारपुर कॉरिडोर परियोजना' के तहत ऐसा किया गया है। इस कनेक्टिविटी से इमीग्रेशन चेक पोस्ट (आईसीपी) और विदेशियों के पंजीकरण कार्यालयों (एफआरओ) पर यात्री की पहचान के सत्यापन में आईसीपी समर्थ होगी।

इस लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी कार्य को 15 दिन के रिकार्ड समय के भीतर पूरा किया गया है। इसमें अमृतसर से डेरा बाबा नानक के बीच 45 किलोमीटर लम्बी बैकबोन/ एकीकरण में रेडियो कनेक्टिविटी तथा डेरा बाबा नानक स्टेशन से 5 किलोमीटर की अंतिम छोर तक भूमिगत ओएफसी कनेक्टिविटी शामिल है। रेलटेल के लिए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण परियोजना थी क्योंकि इसे पूरा करने के लिए बहुत कम समय दिया गया था। इसके अलावा खराब मौसम के कारण कई दिनों तक काम में बाधा भी आई। रेलटेल को 49 किलोमीटर की दूरी तक डेरा बाबा नानक स्टेशन में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 30-मीटर ऊंचे दो टॉवरों को भी खड़ा करना पड़ा। इसके लिए पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास तेजी से सबसे दूरदराज के बिंदु पर कनेक्टिविटी के लिए रिपीटर उपलब्ध कराया जाना था। ■

मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रा.लि. – भारत-फ्रांस सहयोग की अनूठी मिसाल

- रेलवे की सबसे बड़ी एफडीआई परियोजना



भारतीय रेल ने मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लि. के साथ खरीद-सह-रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय रेल और मैसर्स अल्सटॉम का एक संयुक्त उद्यम है। भारतीय रेल की सबसे बड़ी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) परियोजना के तहत रेल मंत्रालय और अल्सटॉम ने भारत में भारी माल की ढुलाई से जुड़े परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने के लिए गठबंधन किया था। माल ढुलाई तथा इससे संबंधित रखरखाव हेतु 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के निर्माण के लिए 3.5 अरब यूरो के एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मैसर्स अल्सटॉम ने मार्च, 2018 में लोकोमोटिव का प्रारूप पेश किया। इसके परीक्षण से जुड़े परिणामों के आधार पर अल्सटॉम ने नए सिरे से डिब्बे सहित संपूर्ण लोकोमोटिव की डिजाइनिंग की है। अल्सटॉम योजना के तहत वित्त वर्ष 2019- 20 में 10 लोकोमोटिव्स, वित्त वर्ष 2020- 21 में 90 लोकोमोटिव्स और फिर मार्च, 2021 के बाद हर वर्ष 100 लोकोमोटिव की सप्लाई करेगी। किसी भी रेलवे द्वारा दुनिया में पहली बार बड़ी लाइनों के नेटवर्क पर इतनी अधिक हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव का परीक्षण किया जा रहा है।

इस परियोजना के तहत बिहार के मधेपुरा में टाउनशिप के साथ यह फैक्ट्री स्थापित की गई है, जहाँ प्रति वर्ष 120 लोकोमोटिव्स का निर्माण करने की क्षमता है। इस परियोजना से देश में 10,000 से भी अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। कंपनी द्वारा इस परियोजना में 2,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि पहले ही निवेश की जा चुकी है। एक रखरखाव डिपो भी पहले ही सहारनपुर में स्थापित किया जा चुका है। नागपुर में दूसरे डिपो की स्थापना का काम शुरू हो चुका है। भारत और फ्रांस के 300 से भी अधिक अभियंता इस परियोजना पर बेंगलुरू, मधेपुरा और फ्रांस में काम कर रहे हैं। यह सही मायनों में 'मेक इन इंडिया' परियोजना है और यहां तक कि पहले लोकोमोटिव की असेम्बलिंग भी मधेपुरा फैक्ट्री में हुई है। दो वर्षों की अवधि में 90 प्रतिशत से भी अधिक कलपुर्जों को भारत में निर्मित किया जाएगा।

इस परियोजना से मधेपुरा में सामाजिक-आर्थिक विकास में भी तेजी आ रही है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत मधेपुरा में कौशल केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके। इस फैक्ट्री में 50 प्रतिशत से भी अधिक स्थानीय लोगों की भर्ती की गई है।

परियोजना के लाभ : भारतीय रेल ने 22.5 टन के एक्सल लोड से युक्त और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली 12,000 हॉर्स पावर के ट्विन बो-बो डिजाइन वाले लोकोमोटिव को हासिल करने का निर्णय लिया है, जिसे बढ़ाकर 25 टन तक किया जा सकता है। यह लोकोमोटिव समर्पित माल-ढुलाई गलियारे के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस परियोजना के सफल होने पर 'मेक इन इंडिया' को काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे लोकोमोटिव के कलपुर्जों के लिए सहायक इकाइयों का और भी तेजी से विकास होगा। इस परियोजना से भारी माल वाली रेलगाड़ियों की त्वरित एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से 6,000टी ट्रेनें चलाएगा। शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होने से नया लोकोमोटिव न केवल रेलवे की परिचालन लागत कम करेगा, बल्कि भारतीय रेल को भीड़-भाड़ से भी मुक्ति दिलाएगा। इसका उपयोग कोयला एवं लौह अयस्क जैसी वस्तुओं से युक्त भारी रेलगाड़ियों को चलाने में किया जाएगा। ■



मधेपुरा रेल इंजन कारखाना

रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बना राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का प्रशासनिक कार्यालय


कार्यालय का आंतरिक दृश्य

भारतीय रेल 166 वर्षों का सुनहरा इतिहास समेटे हुए है। भारतीय रेल अपने 34 संग्रहालयों के माध्यम से अपने समृद्ध एवं अनोखे अनुभवों को आगंतुकों के साथ बांट रही है। इन सबमें राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम), नई दिल्ली पर्यटकों में सर्वाधिक पसंद किया जाता है। संग्रहालय का एक खंड, जो कि सर्वाधिक आवश्यक माना जाता है, वह प्रशासनिक ब्लॉक है। पूरा प्रशासनिक ब्लॉक भारतीय रेल को प्रतिबिंबित करता है। इसको रेलवे स्टेशन के रूप में तब्दील कर दिया गया है। एनआरएम में रद्द हो चुकी रेलगाड़ी के दो डिब्बों को निदेशक के कार्यालय एवं प्रशासनिक ब्लॉक में बदल दिया गया है। पूरा कार्य दिल्ली मंडल द्वारा किया गया है।

आरंभ में एक डिब्बे को नवंबर, 2017 में निदेशक के कार्यालय में बदला गया था। रेलवे के प्रति उत्साही, गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य आगंतुकों द्वारा रेल के डिब्बे में कार्यालय की अवधारणा को बेहद सराहा गया। इस प्रकार प्राप्त प्रशंसा से उत्साहित होकर निदेशक के कार्यालय के सामने एक दूसरे डिब्बे को स्टेशन की थीम पर नवीकृत करके उसमें प्रशासनिक कार्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया। यह लागत की दृष्टि से भी किफायती रहा है, क्योंकि नए कार्यालय के निर्माण पर खर्च इससे ज्यादा आता। इसका बाह्य रूप स्टेशन की तरह दिया जाना था, जिसमें सभी कर्मचारी साथ बैठकर काम कर सकें।

स्टेशन निर्माण की पूरी अवधारणा भारतीय रेल की धरोहर के अनुरूप थी। स्टेशन थीम के आधार पर विकसित करते समय ध्यान रखा गया कि इसकी विभिन्न विशेषताएँ धरोहर के अनुरूप हों। मंगलौर टाइल्स के साथ लहरदार गैल्वेनाइज्ड शीट्स से बनी छतें पुराने स्टेशन की तरह दिखती हैं, जो धरोहर पैटर्न मानी जाती हैं। गोलाकार खंभे बनाए गए जबकि फर्श को कॉब्बल पत्थरों से बनाया गया। नाम पट्टिका भी रेलवे स्टेशनों की तरह पीले और काले रंग की बनाई गई। शंट सिग्नल, धरोहर लालटेनें, बेंच, घड़ियां एवं पुराने पंखे रेलवे स्टेशन का वातावरण निर्मित करते हैं। प्रशासनिक डिब्बे को नए फर्श, विभाजन, आधुनिक प्रणाली, विद्युत एवं उपयुक्त साज-सामान के साथ एक शौचालय से सुसज्जित किया गया है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की पेंटिंग करने वाले अजमेर कारखाने के असली कलाकारों/कारीगरों को निदेशक के कार्यालय एवं प्रशासनिक ब्लॉक के बाह्य भाग को पेंट करने हेतु आमंत्रित किया गया। प्रशासनिक कार्यालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया। इस स्थापना की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक डिब्बे के अंदर निर्मित किया गया है। इस अवधारणा को दर्शकों की अभूतपूर्व प्रशंसा प्राप्त हो रही है और यह उनका एक अन्य आकर्षण बन गया है। संक्षेप में, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ने अपनी क्षमताओं को विस्तार देते हुए रेल धरोहर को संरक्षित रखने हेतु एक और प्रयास किया है। ■


रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बना राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली का प्रशासनिक कार्यालय



संसद में भारतीय रेल

संसद सत्र के दौरान सांसदों द्वारा भारतीय रेल के सम्बंध में पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित जानकारियाँ दीं

उत्तर-पूर्व राज्यों में अवसंरचना विकास

इस समय असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली 1,786 किमी लंबाई के लिए 73,214 करोड़ रु. की लागत वाली 20 परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं - 14 नई लाइन परियोजनाएं 57,826 करोड़ रुपये की लागत में 1,302 किमी की लंबाई को कवर करती हैं और 6 दोहरीकरण परियोजनाएं 15,388 करोड़ रु. की लागत पर 483 किमी की लंबाई को कवर करती हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं, विगत में मुख्यत: निधियों की कमी के कारण से प्रभावित हुई थीं, लेकिन वर्ष 2014-19 के दौरान, परियोजनाओं का निष्पादन तेजी से किया गया है और परियोजनाओं के लिए अधिक निधियों का आबंटन किया गया है।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, न्यायालयों के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना दर परियोजना और स्थल दर स्थल पर भिन्न-भिन्न होते हैं और परियोजना के समापन समय तथा लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंतत: कार्य समापन स्थिति पर गणना की जाती है। जैसाकि इस चरण में शेष परियोजनाओं के पूरा होने के समय को निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ■

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2015 के बाद से निम्न लिखित परियोजनाओं को पूर्ण कर यातायात हेतु खोल दिया गया है:

- हारमुती-नाहरलागुन नई लाइन (21.75 किमी) परियोजना को 2015 में यातायात हेतु खोल दिया गया है।
- रंगिया-मुर्कोंगसलेक आमान परिवर्तन (505 किमी) परियोजना को वर्ष 2015 में यातायात हेतु खोल दिया गया है।
- लमडिंग-सिलचर आमान परिवर्तन (421 किमी) परियोजना को 2015 में यातायात के लिए खोल दिया गया है।
- कुमारघाट-अगरतला नई लाइन (109 किमी) परियोजना को वर्ष 2016 में यातायात के लिए खोल दिया गया है।
- भैराबी-सैंरग आमान परिवर्तन (51.38 किमी) परियोजना को वर्ष 2016 में यातायात के लिए खोल दिया गया है।
- लिंकिंग नई लाइन के साथ बोगीबील पुल (73 किमी) परियोजना को 2018 में यातायात हेतु खोल दिया गया।
- अगरतला-सबरूम नई लाइन (112 किमी) परियोजना को वर्ष 2019 में यातायात के लिए खोल दिया गया है।
- होजाई-लमडिंग दोहरीकरण (44.92 किमी) परियोजना को 2019 में यातायात के लिए खोल दिया गया है।

हेड-ऑन जनरेशन (एचओजी) प्रणाली

भारतीय रेल ने सवारी डिब्बों के लिए हेड ऑन जनरेशन (एचओजी) प्रणाली नामक ऊर्जा कुशल विद्युत आपूर्ति प्रणाली को अंगीकार किया है, जिसमें सवारी डिब्बों में वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था, पंखे आदि के लिए बिजली इंजन (डब्ल्यूएपी-7/डब्ल्यूएपी-5) में उपलब्ध कन्वर्टर्स के माध्यम से शिरोपरि उपस्कर (ओएचई) से बिजली आपूर्ति की जाती है। यह प्रणाली एंड ऑन जनरेशन गाड़ियों में प्रदान की जा रही है, जहाँ डीजी सेट से लैस पावर कारों को दोनों छोरों पर उपलब्ध कराया जाता है। यह प्रणाली सवारी डिब्बों के लिए लागत प्रभावी, विश्वसनीय और ऊर्जा कुशल आपूर्ति प्रणाली प्रदान करने के लिए है। इससे पावर कारों में डीजल ऑल्टरनेटर सेट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है जो ध्वनि और वायु प्रदूषण पैदा करते हैं।

लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) सवारी डिब्बों में एचओजी प्रणाली शुरू होने से पावर कारों के डीजल ईंधन की खपत में भारी बचत हुई है। अब तक, 500 गाड़ियों को एचओजी प्रणाली में रूपांतरित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 1,182.22 करोड़ रु. की बचत हुई है। 2019-20 के दौरान, शेष (200 गाड़ियों) एंड ऑन जनरेशन (ईओजी) एलएचबी रेकों को एचओजी प्रणाली में रूपांतरित करने की योजना है। ऐसी गाड़ियों के रूपांतरण से भारतीय रेल को प्रतिवर्ष लगभग 470 करोड़ रु. की बचत होने की संभावना है। ■

राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष

रिजर्व कोष के रूप में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) का सृजन किया गया है। इस कोष में 2017-18 से आरंभ करके पांच वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 (अनंतिम) और 2019-20 (ब.अ.) के दौरान राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) के अंतर्गत आबंटित धनराशि का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटन
2017-18	16,090.75
2018-19 (अनंतिम)	18,015.33
2019-20 (ब.अ.)	20,000.00

वर्ष 2018-19 में आरआरएसके के अंतर्गत निधियों की उपयोगिता का लघु- शीर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

लघु शीर्ष	वास्तविक 2018-19 (अनंतिम)
16-यातायात सुविधाएं	498.23
21-चल स्टॉक	1637.28
29-समपार	678.60
30-ऊपरि/निचले सड़क पुल	3488.82
31-रेलपथ नवीकरण	9697.31
32-पुल संबंधी कार्य	516.72
33-सिग्नल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य	1461.29
36-बिजली संबंधी अन्य कार्य	349.79
41-मशीन एवं संयंत्र	179.82
42-उत्पादन इकाइयों सहित कारखाने	202.67
53-यात्री सुख- सुविधाएं	795.10
64-अन्य विनिर्दिष्ट कार्य	42.00
65-प्रशिक्षण / मा.सं.वि.	48.01
जमा/वसूलियां	1580.31
कुल	18015.33

भारतीय रेल द्वारा संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं की रोकथाम करने और संरक्षा को बेहतर करने के लिए निरंतर आधार पर हर संभव कदम उठाए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव, रेलपथ, चल स्टॉक, सिग्नल और इंटरलॉकिंग प्रणालियों के रखरखाव और उन्नयन हेतु यथोचित प्रौद्योगिकियां अपनाना, संरक्षा अभियान चलाना, पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर अधिक जोर और निगरानी के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण और संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों को शिक्षित करना शामिल है। सुरक्षित गाड़ी परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों का निवारक और भावी अनुरक्षण किया जाता है। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए संरक्षा उपकरणों/प्रणालियों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, रेलपथ परिपथन, ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर की व्यवस्था, कलर लाइट एलइडी सिग्नल, गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली, सतर्कता नियंत्रण उपकरण, फॉग पास डिवाइस, 52 किग्रा/60 किग्रा, 90 अथवा उच्चतर यूटीएस पटरियों और पूर्व-बलित कंक्रीट स्लीपर का प्रयोग, पटरियों/वेल्डिंग में आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए पूर्व निर्धारित अंतराल पर पटरियों एवं वेल्डिंग के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन का उपयोग करना शामिल है। दोषों को ढूंढ़ने और योजनागत अनुरक्षण के लिए रेलपथ संरचना की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाती है। प्राथमिक रेलपथ नवीकरण के समय गर्डर पुलों पर स्टील चैनल स्लीपरों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, चिह्नित मार्गों पर थिक वेब स्विचों, वेल्डेबल कास्ट मैगनीज स्टील क्रॉसिंग बिछाने का विनिश्चय, लिंके हॉफमेन बुश (एलएचबी) सवारी डिब्बों का उत्तरोतर प्रयोग, सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ) द्वारा निर्मित सवारी डिब्बों में सेंटर बफर कपलर आदि का उपयोग किया गया है। रेल पटरियों को आयु-सह-स्थिति आधार पर रेलपथ नवीकरण कार्यों द्वारा बदला जाता है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। अन्य उपायों में लोको पायलटों और संरक्षा कोटि के अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण, उनके समुचित विश्राम तथा आवधिक रूप से चिकित्सा जांच आदि सहित काम करने की स्थितियों में सुधार लाना शामिल है।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर निरंतर निगरानी और संरक्षा पहलुओं में सुधार लाने के लिए रेलपथ की पेट्रोलिंग, फुटप्लेट निरीक्षण और विभिन्न स्तरों पर संरक्षा समीक्षाएं नियमित रूप से की जाती हैं। इन प्रयासों के कारण परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 में 135 से घटकर 2018-19 में 59 रह गई है। ■

माल ढुलाई दरें

भारतीय रेल की मालभाड़ा दरें परिवहन पण्यों के वर्गीकरण, आवश्यक पण्यों के सामाजिक प्रभाव और इसके संचालन आदि के आधार पर स्थाई संरचना के रूप में स्पष्ट रूप से अधिसूचित हैं। बहरहाल, मालभाड़ा संरचना परिवहन के अन्य साधनों, जैसे रोडवेज आदि में सार्वजनिक नहीं हैं। अत: रेल मालभाड़ा दर अवसंरचना को किसी अन्यत्र के साथ तुलना करना सटीक नहीं होगा।

भारतीय रेल, मालभाड़ा व्यवसाय विगत पचास वर्षों में लगभग सात गुना अर्थात् 1970-71 में 167.39 मिलियन टन से बढ़कर 2017-18 में 1,159.55 मिलियन टन तक हो गया है।

अपने मालभाड़ा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भारतीय रेल द्वारा कई उपाय किए गए हैं। प्रमुख उपायों में रेक भार अवधारणा को अपनाना, कंटेनराइजेशन, उच्च पे लोड के साथ नए मालडिब्बों को डिजाइन करना, दीर्घकालिक दर ठेका नीति, 'अपना माल डिब्बा अपनाओ योजना', निजी मालभाड़ा टर्मिनल नीति और मालभाड़ा प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। ■

भारतीय रेल की परियोजनाएँ

इस समय, 498 रेल परियोजनाएं निष्पादन/ नियोजन/स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें 188 नई लाइन, 55 आमान परिवर्तन और 255 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 49,069 किमी और लागत 6.75 लाख करोड़ रुपये है। परियोजनाओं के परियोजना-वार ब्यौरे भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात www.indianrailways.gov.in>Ministry of Railways>Railway Board>About Indian Railways> Railway Board Directorates>Finance (Budget) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, न्यायालय के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक एक परियोजना से दूसरी परियोजना और एक स्थल से दूसरे स्थल की तुलना में भिन्न-भिन्न होते हैं और परियोजना के समापन समय तथा लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंततः कार्य समापन स्थिति पर गणना की जाती है।

बिहार के अररिया जिले में चार रेलवे परियोजनाएं हैं। इनमें से दो परियोजनाओं यथा अररिया-गलगलिया नई लाइन (110.75 किमी.) और अररिया-सुपौल नई लाइन (92 किमी.) में संपूर्ण भूमि प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, अररिया-गलगलिया परियोजना में उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है और शेष दो परियोजनाओं (सहरसा-फारबिसगंज) आमान परिवर्तन परियोजना और जोगबनी बिराटनगर नई लाइन परियोजना के कार्य शुरू हो गए हैं।

समग्र राष्ट्र के हित में और लागत में वृद्धि हुए बिना परियोजनाएं समय पर पूरी करना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर एवं बोर्ड स्तर) पर अत्यधिक निगरानी रखी जाती है तथा राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों का समाधान किया जा सके।

परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने ठेकों में बोनस खंड के रूप में ठेकेदारों के लिए प्रोत्साहन अवधारणा अपनाई है, जिससे परियोजनाओं के निष्पादन में और तेजी आएगी।

क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं आदि के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है, जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है। ■

ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन

मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क में स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के जरिए पश्चिम रेलवे में 486 एटीवीएम और मध्य रेलवे में 92 एटीवीएम में वन-टच टिकट सुविधा की शुरुआत की गई है। इन 'वन-टच एटीवीएम' की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- एक टच में गंतव्य स्टेशन का चयन किया जा सकता है।
- कोई व्यक्ति दूरी स्लैब के भीतर स्टेशन का चयन कर सकता है।
- सर्वोच्च 20 गंतव्य स्टेशनों को टिकटें जारी की जा सकती हैं।
- एकल टच के जरिए प्लेटफॉर्म टिकटें भी जारी की जा सकती हैं।
- इकहरी और वापसी यात्रा टिकटों के चयन के लिए एक स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य यात्रियों का प्रतीक्षा और लेन-देन समय कम करना और उन्हें लंबी कतारों में खड़े होने से बचाना है।

नियमित एटीवीएम में स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करके अनारक्षित टिकट प्रणाली में दर्शाए गए मार्ग के भारतीय रेल के सभी स्टेशनों के लिए अनारक्षित टिकटें खरीदी जा सकती हैं। बहरहाल, वन-टच एटीवीएम में अनारक्षित टिकटें केवल 20 चुनिंदा गंतव्य स्टेशनों के लिए ही खरीदी जा सकती हैं।

सभी क्षेत्रीय रेलों पर 'एक्सटेंशन ऑफ ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स' परियोजना के अंतर्गत 2019-20 के दौरान 26.5 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यात्री 6 सेकेंड के भीतर टिकट प्राप्त कर सकता है। इससे यात्रियों के लेन-देन समय और प्रतीक्षा समय में कमी आई है।

सभी क्षेत्रीय रेलों के लिए इस ऐप्लिकेशन का विकास पहले ही कर लिया गया है और इस सुविधा को कार्यात्मक रूप देने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने अपेक्षित होंगे। ■

इको-स्मार्ट स्टेशन

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कम-से-कम 5% प्रमुख रेलवे स्टेशन को ईको-स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने का आदेश दिया है।

तदनुसार, 16 क्षेत्रीय रेलों में से प्रत्येक से 2-3 स्टेशनों को शामिल करते हुए 720 प्रमुख स्टेशनों में से 5% स्टेशन का चयन किया गया था और इस प्रकार कुल 37 स्टेशन का चयन किया गया था।

एनजीटी के निर्देशों के अनुसार, 37 स्टेशनों की सूची भारतीय रेल की वेबसाइट पर भी निम्नलिखित लिंक पर अपलोड कर दी गई है:-

http://www.indianrailways.gov.in@railwayboard@uploads@directorate@Environment_management@2019@EnHM_Station_List_13082019.pdf ■

रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय मानकों विकसित करने हेतु

रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय मानकों पर विकसित करने और निजी पैसेंजर गाड़ी संचालकों को भारतीय रेल नेटवर्क पर विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी के साथ गाड़ियों के संचालन की अनुमति देने के लिए एक सचिव दल (ईजीओ) का गठन किया है। सचिव दल में निम्नलिखित शामिल हैं :

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग - अध्यक्ष
- अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड - सदस्य
- सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय - सदस्य
- सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय - सदस्य
- वित्त आयुक्त (रेलवे) - सदस्य
- सदस्य (इंजीनियरिंग), रेलवे बोर्ड, और सदस्य (यातायात), रेलवे बोर्ड अपनी संबंधित परियोजनाओं के लिए सहयोजित सदस्य हैं।

सचिव दल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :-

- आरएफक्यू/आरएफपी और रियायत संबंधी समझौतों सहित बोली दस्तावेजों के साथ-साथ बोली प्रक्रिया का अनुमोदन करना।
- बोली प्रक्रिया की निगरानी करना और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से सौंपे जाने को सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेना।

निजीकृत गाड़ियों के परिचालन के ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ■

मिशन रफ्तार

यात्री और माल गाड़ियों की औसत रफ्तार बढ़ाने के उद्देश्य से रेल बजट 2016-17 में 'मिशन रफ्तार' की घोषणा की गई है।

गतिशीलता में सुधार लाने और औसत रफ्तार में वृद्धि से संबंधित कार्य योजना में गति प्रतिबंध हटाना, ऊपरी सड़क पुलों (आरओबी) और निचले सड़क पुलों (आरयूबी) का निर्माण, गाड़ियों में सही पावर का इंजन लगाना और परंपरागत गाड़ियों के स्थान पर मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (मेमू) गाड़ियां और डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (डेमू) गाड़ियां चलाना शामिल हैं।

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 5 अगस्त, 2019 को मौजूदा नई दिल्ली-मुंबई (वडोदरा-अहमदाबाद सहित) और नई दिल्ली-हावड़ा (कानपुर-लखनऊ सहित), मार्गों पर 160 किमी प्रति घंटा (केएमपीएच) तक गाड़ियों की गति बढ़ाने की दो परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।

परियोजनाओं का निष्पादन समूची मार्ग लंबाई पर एक साथ करने की योजना बनाई जा रही है और तेजी से पूरा करने के लिए इसकी निगरानी की जाएगी।

ये कॉरीडोर भारतीय रेल के मार्गों के एक नेटवर्क, स्वर्णिम चतुर्भुज और विकर्णों का भाग हैं जिसमें भारतीय रेल नेटवर्क का सिर्फ 16% भाग शामिल है लेकिन यह भारतीय रेल द्वारा ढोए जाने वाले कुल यात्री यातायात के 52% और कुल मालभाड़ा यातायात के 58% का वहन करता है। ■

मानव रहित समपार

बड़ी आमान वाली लाइनों पर बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को जनवरी, 2019 तक समाप्त कर दिया गया है। बहरहाल, चौकीदार वाले समपार पर, यदि यातायात घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन यूनिट (टीवीयू) से अधिक होता है, तब इन समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) को लागत भागीदारी के आधार पर निर्मित किया जा रहा है, बशर्ते राज्य सरकार से समपार को समाप्त करने और लागत में भागीदारी करने की सहमति प्राप्त हो। आरओबी का मंडलवार डाटा नहीं रखा जाता है। पिंक बुक 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित लागत भागीदारी आधार पर स्वीकृत आरओबी का राज्यवार ब्यौरा परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। सामान्यत: रेलवे अपने हिस्से में आरओबी का निर्माण करती है जबकि पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। सामान्यत:, रेलवे के हिस्से में आरओबी के निर्माण में कोई समस्या नहीं होती। तथापि इनकी समय-सीमा तय करना कठिन है क्योंकि पहुंच मार्गों पर आरओबी का निर्माण, भूमि की उपलब्धता, अतिक्रमण हटाने, पहुंच मार्गों का संरेखण निर्धारित करने, अपेक्षित धनराशि का आबंटन आदि जैसे बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। समपारों को अनावश्यक रूप से बंद नहीं किया जाता है। इन्हें गाड़ी अथवा गाड़ियों अथवा रेलवे के किसी अन्य परिचालन के लिए सुरक्षित मार्ग सड़क यातायात हेतु बंद किया जाता है। ये रेल और सड़क उपयोगकर्ता, दोनों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। रेलवे समपारों को समाप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

लागत भागीदारी आधार पर स्वीकृत ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	राज्य	ऊपरी सड़क पुल
1	आंध्र प्रदेश	66
2	असम	1
3	बिहार	119
4	छत्तीसगढ़	29
5	दिल्ली	4
6	गोवा	3
7	गुजरात	127
8	हरियाणा	74
9	जम्मू एवं कश्मीर	1
10	झारखंड	41
11	कर्नाटक	42
12	केरल	109
13	मध्य प्रदेश	92
14	महाराष्ट्र	102
15	ओडिशा	42
16	पुदुचेरी	5
17	पंजाब	18
18	राजस्थान	62
19	तमिलनाडु	148
20	तेलंगाना	45
21	उत्तर प्रदेश	312
22	उत्तराखंड	6
23	पश्चिम बंगाल	87
	कुल	1,535

केन्द्रीकृत खान-पान सेवा निगरानी प्रकोष्ठ

विगत पांच वर्षों में केन्द्रीकृत खान-पान सेवा निगरानी प्रकोष्ठ (सीएसएमसी) द्वारा प्राप्त खान-पान सेवाओं से संबंधित शिकायतों की संख्या और निपटाई गई शिकायतों की संख्या का ब्यौरा परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।

भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की निगरानी के लिए विगत दो वर्षों में रेल पदाधिकारियों द्वारा किए गए नियमित और औचक निरीक्षण की संख्या के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा परिशिष्ट-II के रूप में संलग्न है।

खान-पान सेवाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट करने के लिए एनएबीसीबी-मान्यता प्राप्त ऑडिट एजेंसी को सीमित निविदा के जरिए आईआरसीटीसी द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय रेल पर खान-पान सेवाओं के थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए आईआरसीटीसी द्वारा मैसर्स टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लगाया गया था जिसने अगस्त, 2019 में ऑडिट कार्य को पूरा कर लिया है। इस समय, एनएबीसीबी-मान्यता प्राप्त ऑडिटिंग एजेंसी भारतीय रेल के साथ जुड़ी हुई नहीं है।

परिशिष्ट-I

वर्ष	2014-15	201516	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
कुल शिकायतें	1649	2599	4324	4328	4286	17186
निपटाई गई शिकायतें	1649	2599	4324	4328	4286	17186

परिशिष्ट-II

वर्ष	किए गए निरीक्षण के प्रकार	निरीक्षणों की कुल संख्या	निरीक्षण के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा						
			जुर्माना		चेतावनी	निरस्त	उपयुक्त सलाह	अन्य कार्रवाई	कुल
			मामलों की संख्या	लगाए गए जुर्माने की राशि (रु. में)					
2017-18	नियमित नरीक्षण	36737	12847	4,39,22,659	5432	0	8088	10370	36737
	औचक निरीक्षण	4377	2097	82,13,698	938	0	826	516	4377
2018-19	नियमित नरीक्षण	43096	12153	3,95,36,565	6848	0	11349	12746	43096
	औचक निरीक्षण	4704	2236	76,75,616	983	1	692	792	4704

स्टेशन पुनर्विकास योजना

रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और अन्य केंद्र सरकार की एजेंसियों के माध्यम से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनाई गई है। भारतीय रेल के सभी बड़े स्टेशनों को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए इन एजेंसियों को सौंप दिया गया है। इन व्यवहार्यता अध्ययनों के परिणामों के आधार पर स्टेशनों का चरणों में पुनर्विकास करने की योजना है।

स्टेशनों पर और उसके आसपास की खाली भूमि/वायु क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास का उपयोग करके स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना है अर्थात् स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं की लागत सामान्यत: रेलों को वहन नहीं करनी होगी।

हबीबगंज (भोपाल) और गांधीनगर स्टेशनों के पुनर्विकास के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। रेल मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से भुवनेश्वर स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। देहरादून रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अप्रैल, 2019 में अजनी (नागपुर) स्टेशन का मल्टी-मॉडल हब के रूप में पुनर्विकास करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं अपनी किस्म की पहली परियोजनाएं हैं और जटिल किस्म की हैं तथा इनके लिए विस्तृत तकनीकी-वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन और स्थानीय निकायों से सांविधिक स्वीकृतियां आदि अपेक्षित हैं। अत: फिलहाल किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता। ■

भारत और स्विट्जरलैंड के मध्य समझौता

भारत गणराज्य के रेल मंत्रालय और स्विस परिसंघ के संघीय पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के बीच रेल क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग के लिए 31 अगस्त को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

कर्षण चल स्टॉक, ईएमयू और ट्रेन सेट, कर्षण प्रणोदन उपस्कर, माल ढुलाई और यात्री कारें, टिल्टिंग ट्रेन्स, रेलवे विद्युतीकरण उपस्कर, ट्रेन शेड्यूलिंग और परिचालन सुधार, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, बहुविध परिवहन, सुरंग प्रौद्योगिकी, प्रतिभागी देशों द्वारा संयुक्त रूप से पहचाने गए कोई अन्य क्षेत्र।

समझौता ज्ञापन के तहत पहली संयुक्त कार्य दल की बैठक 21 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की गई थी जिसमें चल स्टॉक, विद्युत उप-प्रणालियां, प्रणाली एकीकरण, शिरोपरि संपर्क प्रणाली (रिजिड कैटेनरी और रिट्रेक्टेबल शिरोपरि उपस्कर) और अंतर-मॉडल परिवहन के क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

स्विट्जरलैंड स्थित कंपनियों की कुछ प्रमुख मदों का ब्यौरा, जिन्हें अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है और वर्तमान में जिन्हें भारतीय रेल में उपयोग किया जा रहा है, निम्न प्रकार है:

- 1990 के दशक की शुरुआत में डब्ल्यूएजी 9 और डब्ल्यूएपी 5 बिजली इंजनों को एबीबी स्विट्जरलैंड से आयात किया गया था।
- स्विट्जरलैंड में स्थित एक फर्म, ह्यूबर शूनर बिजली इंजनों के लिए केबल की एक अनुमोदित आपूर्तिकर्ता है।
- स्विट्जरलैंड में स्थित एक फर्म, आर्थर फ्लरी शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन असेंबली की एक अनुमोदित आपूर्तिकर्ता है और पिछले 20 वर्षों से भारतीय रेल को आपूर्ति कर रही है। ■

उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के लिए नई रेलगाड़ियाँ

भारतीय रेल में रेलगाड़ियों की शुरुआत/मार्ग परिवर्तन करना एक सतत् प्रक्रिया है। माल यातायात के अलावा, भारतीय रेल बोगीबील पुल के रास्ते 3 जोड़ी यात्री गाड़ी सेवाओं का संचालन कर रही है। बहरहाल ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर वन्य प्राणियों, विशेष रूप से जंगली हाथियों की आवाजाही देखी जाती है और वन विभाग के परामर्श से तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सलाह से हाथियों हेतु गलियारों को कार्यशील समय-सारणी में अधिसूचित किया जाता है और तदनुसार, रेलगाड़ियों (यात्री और माल यातायात, दोनों) के लिए गति प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इस कदम से हाथियों के हताहत होने के मामलों को कम करने में मदद मिली है। उपरोक्त के अलावा, हाथियों के हताहत होने की टक्कर वाली घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- रेलपथों के किनारे वनस्पति की नियमित आधार पर सफाई।
- लोको पायलटों को चेतावनी देने के लिए सभी हाथी गलियारों में संकेतक बोर्ड की व्यवस्था करना।
- वन विभाग की मदद से लोको पायलटों/सहायक लोको पायलटों और गार्डों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम।
- रेलपथों को खाद्य अपशिष्ट से मुक्त रखना, जो हाथियों को आकर्षित कर सकता है।
- रंगिया मंडल के कामाख्या-गोलपाड़ा टाउन खंड पर छह स्थाई गति प्रतिबंध और लमडिंग मंडल के गुवाहाटी-लमडिंग-फुरकटिंग खंड और धर्मनगर-अगरतला खंड पर 14 गति प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- चिन्हित हाथी गलियारों के अलावा स्थानों पर वन विभाग से हाथियों की आवाजाही की सूचना मिलने पर अस्थाई गति प्रतिबंध लगाना। वर्तमान में, जुगीजान से लेकर लमडिंग तक छह अस्थाई गति प्रतिबंध हैं।
- पूर्वोत्तर सीमा रेलवे प्रणाली में चौकीदार वाले समपार पर बड़ी संख्या में मधुमक्खी ध्वनि प्रणाली संस्थापित की गई है, जिनमें से कुछ दक्षिणी किनारे अर्थात् कामाख्या-गोलपाड़ा खंड में हैं। यह हाथी को रेलपथ से दूर रखने के लिए प्रतिकर्षक का कार्य करता है। ■

ई-कॉमर्स पैकेटों का परिवहन

ई-टेल कंपनियों के लिए रेलवे की पार्सल सेवा का उपयोग करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत अमेजन इंडिया को 12314/12313 नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस और 12952/12951 नई दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में लदान/उतराई के लिए गार्ड की देख-रेख में एसएलआर/ब्रेक वैन में 2.5 टन लदान के लिए स्थान प्रदान किया गया है। पायलट परियोजना के परिणाम के आधार पर विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

रेलवे द्वारा वित्त वर्ष (2019-20) के दौरान माल यातायात और यात्री यातायात के माध्यम से क्रमशः 1,43,000 करोड़ रु. और 56,000 करोड़ रु. की राशि अर्जित किए जाने का लक्ष्य है।

भारतीय रेल अपने नेटवर्क पर यात्री यातायात के साथ-साथ माल यातायात और आमदनी में सुधार करने का निरंतर प्रयास कर रही है।

यात्री यातायात और आमदनी में सुधार के लिए की गई कुछ पहलें, जैसेकि ऑन-बोर्ड क्षमता में वृद्धि, फ्लेक्सी किराया योजना के यौक्तिकीकरण, वैकल्पिक गाड़ी एकोमोडेशन विकल्प योजना का विस्तार, अतिरिक्त एकोमोडेशन प्रदान करने के लिए आरएसी बर्थ की संख्या में वृद्धि आदि हैं।

इसी प्रकार, माल यातायात व्यवसाय से आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें खाली प्रवाह दिशा में लदान किए गए यातायात के लिए लिबरलाइज्ड ऑटोमैटिक फ्रेट रिबेट योजना, प्रमुख माल यातायात ग्राहकों के साथ दीर्घ अवधि टैरिफ ठेका (एलटीटीसी), स्टेशन से स्टेशन दरें (एसटीएस), बड़ी संख्या में वस्तुओं का पुनःनिर्धारण करना ताकि उन्हें एफएके दरों आदि के तहत लाया जा सके, शामिल है।

इसके अलावा, भारतीय रेल के माल भाड़े के निष्पादन को बढ़ाने के लिए, मालगाड़ी के एक्सल भार और लंबाई को बढ़ाने, व्यापक कम्प्यूटरीकरण का उपयोग, उच्च क्षमता वाले वैगनों और इंजनों की तैनाती, रेलपथ और सिग्नलों में सुधार करना आदि जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। ■

स्टेशनों पर सौर-पैनल लगाना

भारतीय रेल द्वारा अब तक, 835 रेलवे स्टेशनों सहित, विभिन्न रेलवे इमारतों की छतों पर 95.67 मेगावाट (एमडब्ल्यू) सौर ऊर्जा को संस्थापित कर दिया गया है। इन रेलवे स्टेशनों का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशनों की संख्या जहाँ सौर पैनल लगाए गए
मध्य रेल	21
पूर्व रेलवे	39
पूर्व मध्य रेलवे	105
पूर्व तट रेलवे	14
उत्तर मध्य रेलवे	32
पूर्वोत्तर रेलवे	71
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	42
उत्तर रेलवे	51
उत्तर पश्चिम रेलवे	104
दक्षिण मध्य रेलवे	49
दक्षिण पूर्व रेलवे	13
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	15
दक्षिण रेलवे	52
दक्षिण पश्चिम रेलवे	132
पश्चिम मध्य रेलवे	23
पश्चिम रेलवे	69
मेट्रो	3
कुल	835

भारतीय रेल की अन्य स्टेशनों पर सौर ऊर्जा पैनलों को संस्थापित करने की योजना है, जो साइट की उपलब्धता तथा व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। अब तक, रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आरईएमसीएल) द्वारा 248.46 मेगावाट क्षमता के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं और ये निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इसमें रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म शेल्टर और विभिन्न अन्य रेलवे इमारतों की छतें शामिल होंगी। आरईएमसीएल द्वारा प्रदत्त सोलर रूफटॉप परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयां	छतों पर प्रदत्त सौर ऊर्जा क्षमता (मेगा वाट में)
चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना	7.64
मध्य रेल	20.85
डीजल रेलइंजन कारखाना	6.83
पूर्व रेलवे	19.79
पूर्व तट रेलवे	14.83
पूर्व मध्य रेलवे	12.65
सवारी डिब्बा कारखाना	2
मेट्रो कोलकाता	5.54
उत्तर मध्य रेलवे	10
उत्तर पश्चिम रेलवे	11.68
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1.88
उत्तर रेलवे	23.63
पूर्वोत्तर रेलवे	13.92
अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	1.08
रेल डिब्बा कारखाना	0.9
दक्षिण रेलवे	10.69
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	4.38
दक्षिण पूर्व रेलवे	24.94
दक्षिण मध्य रेलवे	33.14
दक्षिण पश्चिम रेलवे	2.46
पश्चिम मध्य रेलवे	9.63
पश्चिम रेलवे	10
कुल	248.46

भारतीय रेल की 2021-22 तक छतों पर 500 मेगा वाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना है। इस कार्य का अधिकांश भाग निजी भागीदारों द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति (डेवलपर पद्धति) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रेलों को पूंजीगत व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। निजी भागीदारों द्वारा गाड़ियों पर सौर पैनलों की व्यवस्था करने का कार्य भी किया जा रहा है। ■

रेल लाइनों का दोहरीकरण

इस समय, 20,500 किमी लंबी 255 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनकी लागत 2.32 लाख करोड़ रुपए है, नियोजन/ स्वीकृति/ निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से मार्च 2019 तक 2,784 किमी लंबाई पर यातायात चालू कर दिया गया है और 48,342 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में इन परियोजनाओं के लिए 17,602 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इनमें पूर्णत:/अंशत: बिहार में आने वाली 11,574 करोड़ रुपए की लागत वाली 937.11 किमी लंबी 14 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। सभी चालू दोहरीकरण परियोजनाओं और नए कार्यों पर खर्च की गई धनराशि और परिव्यय के ब्यौरे भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात www.indianrailways.gov.in>Ministry of Railways>Railway Board>About Indian Railways>Railway Board Directorates>Finance (Budget) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर, दोनों पर) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, न्यायालय के आदेश, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना दर परियोजना और स्थल दर स्थल भिन्न-भिन्न होते हैं और परियोजना के समापन समय तथा लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंतत: कार्य समापन स्थिति पर गणना की जाती है। अत: परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा नहीं दी जा सकती। ■

रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन

भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/अपग्रेडेशन निरंतर चलने वाली एक सतत् प्रक्रिया है। यह कार्य समय-समय पर विभिन्न आधुनिकीकरण योजनाओं, जैसे मॉडल स्टेशन योजना, मॉडर्न स्टेशन योजना और आदर्श स्टेशन योजना के तहत किया गया है। 'मॉडल स्टेशन योजना' (जून, 1999 से नवंबर, 2008) और 'मॉडर्न स्टेशन योजना' (2006-07 और 2007-08) के तहत स्टेशनों को विकसित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 'आदर्श स्टेशन योजना' के तहत स्टेशनों का अपग्रेडेशन 2009-10 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का चयन, सुविधाओं के अपग्रेडेशन के लिए चिह्नित आवश्यकता पर आधारित होता है। 'आदर्श स्टेशन योजना' के तहत विकास के लिए 1253 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से अब तक 1,149 रेलवे स्टेशनों को विकसित कर दिया गया है और शेष स्टेशनों को 2019-20 तक विकसित करने की योजना है।

इस समय, रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन और अनुरक्षण सहित 'आदर्श' स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का विकास विभागीय माध्यम से और आउटसोर्सिंग के जरिए पूरा किया जाता है। आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा राज्यवार नहीं रखा जाता है। 'आदर्श' स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का विकास सहित आधुनिकीकरण कार्यों पर आबंटन/व्यय सामान्यत: योजना शीर्षक-'यात्री सुविधाओं' के जरिए वित्त पोषित किया जाता है। पश्चिम रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे, जो गुजरात राज्य को कवर करती हैं और पूर्व तट रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे तथा दक्षिण पश्चिम रेलवे, जो आंध्र प्रदेश के साथ-साथ महबूबनगर रेलवे स्टेशन को कवर करती है, सहित बजटीय स्रोतों के तहत और विगत तीन वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 और चालू वर्ष के दौरान योजना शीर्ष 'यात्री सुविधाओं' के अंतर्गत निधियों का आबंटन/व्यय का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

क्षेत्रीय रेलवे	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	आबंटन (सं.अ.)	व्यय	आबंटन (सं.अ.)	व्यय	आबंटन (सं.अ.)	व्यय	आबंटन (ब.अ.)	व्यय
मध्य	73.93	74.07	141.53	161.89	262.67	237.42	284.14	195.73
पूर्व	51.85	48.41	85.21	50.73	116.67	57.84	208.16	77.65
पूर्व मध्य	52.78	65.76	72.03	74.11	139.24	98.57	227.91	94.48
पूर्व तट	47.78	56.42	75.09	59.85	116.42	72.55	175.74	63.42
उत्तर	78.15	94.93	174.12	171.92	347.24	141.18	289.00	106.08
उत्तर मध्य	56.87	60.34	105.53	66.56	94.51	116.92	177.37	43.38
पूर्वोत्तर	107.69	109.84	92.81	96.44	112.20	89.53	186.17	57.66
पूर्वोत्तर सीमा	50.75	45.81	56.83	38.16	97.54	78.06	186.17	71.72
उत्तर पश्चिम	53.42	55.60	57.87	68.09	155.89	118.62	186.17	89.11
दक्षिण	61.18	70.68	148.52	102.00	147.47	57.57	264.22	64.30
दक्षिण मध्य	64.41	68.56	90.96	63.80	186.33	76.39	227.91	103.16
दक्षिण पूर्व	47.46	60.08	80.25	81.85	81.11	56.93	175.42	43.72
दक्षिण पूर्व मध्य	29.55	31.49	32.60	23.50	104.32	36.19	175.74	32.99
दक्षिण पश्चिम	42.63	41.93	64.19	49.77	61.22	26.19	186.17	45.64
पश्चिम	48.73	47.96	126.50	134.80	325.37	299.01	284.22	197.22
पश्चिम मध्य	45.29	43.78	58.55	44.44	53.21	19.03	175.49	24.68
मेट्रो	5.44	5.58	8.20	3.89	9.31	3.88	12.57	3.88
कुल	917.91	981.24	1470.79	1286.80	2410.71	1585.88	3422.57	1314.82

स्टेशनों के निकट ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) और निचले सड़क पुल (आरयूबी) स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होते हैं। ■

पूर्वोत्तर राज्यों के रेलवे स्टेशनों का स्तरोन्नयन

भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन एक सतत् और चालू प्रक्रिया है। धन की उपलब्धता के अध्यधीन, यात्री सुविधाओं संबंधी सुधार के कार्य, जिन्हें आवश्यकता, यात्री यातायात की मात्रा और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

रेलवे स्टेशनों को 'आदर्श स्टेशन योजना' के तहत अपग्रेड/आधुनिक बनाया गया है। अब तक पूर्वोत्तर राज्यों के निम्नलिखित 30 स्टेशनों को 'आदर्श स्टेशन योजना' के तहत पहचान कर अपग्रेड कर दिया गया है।

क्रम सं.	राज्य	आदर्श स्टेशनों का नाम	स्टेशन की सं.
1	असम	रंगपाडा नॉर्थ, सिलचर, बदरपुर जंक्शन., श्रीरामपुर असम, गोसाईगांव हाट, फकीराग्राम, सालकटी, बासुगांव, टिपकई, बिजनी, तिहु, गोरेश्वर, उढलगुड़ी, तंगला, रोवता बगान, बाड़पेटा रोड, होजई, रंगिया जंक्शन, जाखलाबांध, जोरहाट टाउन, करीमगंज जंक्शन., कोकराझार, न्यू बोंगईगांव, जागीरोड, टाटीबहार, बोंगईगांव, फरकटिंग और नारेंगी।	28
2	नगालैंड	दीमापुर	1
3	त्रिपुरा	पेंचारथल	1
		कुल	30

इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों में 2018-19 में 'स्टेशनों पर सॉफ्ट अपग्रेड सुधार' के तहत् विकास के लिए रंगिया, गुवाहाटी और न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशनों पर निम्नलिखित सुविधाओं को शामिल/बेहतर किया गया है :

स्टेशन का नाम	शामिल/बेहतर की गई सुविधाएं
रंगिया	प्रतीक्षालय, पार्किंग क्षेत्र, वाई-फाई लाउंज, शौचालय, प्लेटफॉर्म सतह, अल्पाहार गृह और परिपथन क्षेत्र के साथ स्टेशन के अग्रभाग में सुधार किया गया है।
गुवाहाटी	मॉड्यूलर वॉटर वैट (29), अष्टकोणीय बेंच (19), विश्राम कक्ष (12), क्लॉक रूम, जिसमें अलग-अलग लॉक करने की सुविधा उपलब्ध है। प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म सतह, शौचालय, विश्राम कक्ष का सुधार किया गया। 2 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर मुहैया कराए गए हैं।
न्यू तिनसुकिया	पेड एक्जीक्यूटिव लाउंज, महिला प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय, 6 वाणिज्यिक आउटलेट्स, 20 आरओ वॉटर बूथ प्रदान किए गए। द्वितीय श्रेणी और उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय की क्षमता, वीआईपी लाउंज, प्लेटफॉर्म सतह और शौचालयों का सुधार किया गया।

मनढारदिशा, पेंचारथल, हेतीखली, धालपुखुरी, लंका, हबायपुर, लमसाखंग और पथरखोला नामक 8 स्टेशनों पर ऊपरी पैदल पुल (एफओबी) का कार्य पूरा कर लिया गया है। 13 नई रेलवे लाइन परियोजनाएँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू की गई हैं जो योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। धन आबंटन सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

परियोजना	अनुमोदन का वर्ष	लंबाई (किमी में)	राज्य	नवीनतम प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	2019-20 के लिए परिव्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन (स्वीकृत)					
न्यू मल-मोयनागुड़ी रोड और न्यू चांगराबंडा - चांगराबंडा के आमान परिवर्तन के साथ न्यू मोयनागुड़ी-जोगीगोपा	2000-01	289	असम, पश्चिम बंगाल	3300	100
जिरीबाम-इम्फाल	2003-04	111	मणिपुर	13,809	850
दीमापुर (धनसिरी) - जुब्जा (कोहिमा)	2006-07	83	असम, नगालैंड	3000	500
तेतेलिया-बिरनीहाट	2006-07	22	असम, मेघालय	1532	125
भैराबी-सैरंग	2008-09	51	मिजोरम	5021	750
सिवोक-रांगपो	2008-09	44	सिक्किम, पश्चिम बंगाल	4086	200
बिरनीहाट-शिलांग	2010-11	108	मेघालय	6,000	0.10
मुरकोंगसेलेक-पासीघाट	2011-12	26	असम, अरुणाचल प्रदेश	661	2
अगरतला (भारत) - अखौरा (बांग्लादेश)	2012-13	11	त्रिपुरा, बांग्लादेश	970	100
नई लाइन (स्वीकृत की जाने वाली)					
दीमापुर-टिजिट*	2013-14	257	नगालैंड	4274	0.10
सलोना-खुमताई*	2017-18	99	असम	5958	0.10
सिबसागर-जोरहाट*	2017-18	62	असम	2696	0.10
तेजपुर-सिलघाट*	2017-18	25	असम	3512	0.10

रंगिया मंडल के 11 स्टेशनों पर स्टेनलेस स्टील के 435 अदद बेंच उपलब्ध कराए गए हैं। इन स्टेशनों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

स्टेशन	बैकरेस्ट वाला 10 सीटर, और सीट विभाजक सहित		बैकरेस्ट वाला 4 सीटर, और सीट विभाजक सहित		बैकरेस्ट वाला 4 सीटर, बिना विभाजक		बिना बैकरेस्ट वाला 4 सीटर, बिना विभाजक	
	आपूर्ति	फिक्स्ड	आपूर्ति	फिक्स्ड	आपूर्ति	फिक्स्ड	आपूर्ति	फिक्स्ड
आरएनवाई	20	20	30	30	15	15	8	8
बीपीआरडी	25	25	0	0	25	25	12	12
एनबीक्यू	30	30	25	25	10	10	20	20
जीएलपीटी	25	25	6	6	20	20	12	12
सीजीओएन	25	2	6	0	20	6	12	0
यूएलजी	25	0	20	0	12	0	6	0
एचएमवाई	25	0	6	0	20	0	12	0
आरपीएएन	30	30	10	10	20	20	13	13
डीएमसी	30	0	6	0	20	0	15	0
एमजैडएस	25	0	6	0	20	0	12	0
डीकेजीएन	30	30	6	6	20	20	15	15
कुल	290	162	121	77	202	116	137	80

रेल मंत्रालय के अंतर्गत 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रमुख कार्य
1.	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	फास्ट ट्रैक आधार पर रेल अवसंरचना का निर्माण।
2.	भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी)	खान-पान और आतिथ्य, रेलनीर, यात्रा और पर्यटन, इंटरनेट टिकट।
3.	रेल इंडिया टेकनिकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स)	परिवहन और अवसंरचना अर्थात् रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग, रोपवे, शहरी परिवहन, शहरी इंजीनियरिंग, कंटेनर डिपो, संस्थागत भवनों और रेलवे विद्युतीकरण का विकास।
4.	भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी)	आईआरएफसी भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व वाली आधारभूत पट्टा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह अवसंरचनात्मक मदों (रोलिंग स्टॉक परिसम्पत्तियों, रेल इंजनों, यात्री सवारी डिब्बे और माल डिब्बों को शुरू करती है) को पट्टे पर देती है।
5.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल)	रेलवे मालडिब्बों का विनिर्माण और रेलवे मालडिब्बों और क्रेन सेवाओं की मरम्मत।
6.	डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल)	रेल मंत्रालय ने दो डेडीकेटेड गलियारे अर्थात् स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके डाइग्नलों के साथ पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। पूर्वी डीएफसी (1856 किमी) लुधियाना (पंजाब) से दनकुनी (पश्चिम बंगाल) तक है और पश्चिमी डीएफसी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, न्यू मुंबई से दिल्ली के नजदीक दादरी तक है ।
7.	मुंबई रेल विकास निगम (एमआरवीसी)	मुंबई उपनगरीय की रेल अवसंरचना
8.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	यह कोलकाता में ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर की एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई है।
9.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	रेल परिवहन और कंटेनरों की हैंडलिंग, कंटेनर/कार्गो का भंडार।
10.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के पास रोहा तथा कर्नाटक राज्य में मैंगलोर के पास ठोकुर के बीच कोंकण रेलवे का निर्माण और संचालन ।
11.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)	टर्न-की आधार पर और अन्य प्रकार से रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता। रेलवे निर्माण कंपनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के बाद सड़क, भवन, विद्युत सब-स्टेशन और वितरण, हवाई अड्डे के निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों के साथ मेट्रो रेल कार्यों के लिए इसमें उत्तरोत्तर विविधता आई है। यह कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों को सेवा प्रदान करती है।
12.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल)	देश के सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक, जो रेलवे ट्रैक के साथ-साथ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पर पैन-इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का प्रदाता है।
13.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	बंद हो रहा है।
14.	बर्न स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएससीएल)	बंद हो रहा है।

कोहरे के दौरान रेल परिचालन सुचारु करने की योजना

शीतकालीन मौसम के दौरान उत्तर भारत में कोहरे का छाना एक आम बात है। तथापि, हाल ही के वर्षों में, देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में कोहरे की अवधि और स्थितियों में काफी बदलाव दिख रहा है, जिसके कारण अनेक तरह की चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ सामने आ रही हैं।

धुंध के मौसम में सामान्य जन-जीवन भी प्रभावित होता है। इसका रेल परिचालन प्रणाली पर भी गहरा असर पड़ता है। कम दृश्यता के चलते रेलगाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित होता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कोहरा प्रभावित क्षेत्रों में रेलगाड़ियों की गति सीमा पर प्रतिबंध लगाने जैसे अनेक उपाय किए जाते हैं। कोहरे के चलते रेलगाड़ियाँ अपने गंतव्य पर विलम्ब से पहुँचती हैं और अधिक विलम्ब से चलने वाली रेलगाड़ियों की वापसी यात्रा को प्रायः परिवर्तित समय से चलाया जाता है अथवा निरस्त कर दिया जाता है।



पिछले तीन वर्षों के दौरान नवंबर से फरवरी के बीच कोहरे के कारण विलंबित हुई मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	कोहरे के कारण विलंबित हुई गाड़ियों का प्रतिशत
2016-17	20.51%
2017-18	15.13%
2018-19	05.38%

घने कोहरे के कारण रेलवे के समक्ष आने वाली कठिनाइयां

- रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण रेकों का अनियमित आगमन/प्रस्थान।
- मार्ग अवरोधों और रेलगाड़ियों की धीमी गति के कारण कार्य के घंटों में वृद्धि के चलते चालक दल की कमी।
- रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण रेलगाड़ियों की समय-सारणी, उनके प्लेटफॉर्मों पर लगाए जाने की योजना, वॉशिंग लाइन परिसरों में उनके रख-रखाव के समय पर प्रभाव।
- रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण खान-पान सुविधाओं पर असर।
- प्रमुख रेल टर्मिनलों के प्लेटफॉर्मों पर प्रतीक्षारत यात्रियों की भीड़ बढ़ना।
- कम क्षमता के कारण अनुरक्षण ब्लॉकों की अनुपलब्धता।
- गति सीमा पर प्रतिबंध और क्षमता बाधित होने के कारण परिसम्पतियों के न्यूनतम उपयोग और चालक दल के ओवर टाइम के कारण परिचालन की लागत में वृद्धि।



12,205 भारतीय रेल ने फॉग पास उपकरण मुहैया कराए

आगामी सर्दियों में कोहरे के मद्देनजर रेल परिचालन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने की प्रस्तावित योजना

- गत वर्षों के दौरान कोहरे के मौसम में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा रेल परिचालन की योजना तैयार की गई है।

यात्री सुविधा

- एक घंटे से अधिक विलम्ब से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ियों की सूचना यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर दी जाएगी।
- सामान्य कार्य अवधि के उपरांत भी देर तक प्लेटफॉर्मों पर खान-पान स्टॉलों को खोलने का प्रावधान किया गया है।
- भीड़-भाड़ प्रबंधन और सुरक्षा मामलों से निपटने के लिए स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी।

संरक्षा

- सर्दियों के मौसम में रेल लाइनों पर गश्त बढ़ाकर सतत् निगरानी की जा रही है
- रेल पथ पर गश्त लगाने वाले कर्मचारियों को जीपीएस आधारित हैंड-हेल्ड उपकरण प्रदान किए गए हैं ताकि किसी भी आकस्मिक घटना की सूचना वे दोनों ओर के निकटवर्ती स्टेशनों तक तुरंत पहुँचा सकें।
- सभी इंजनों में फॉग-सेफ्टी डिवाइस का प्रावधान। दृश्यता कम होने की स्थिति में ड्राइवर आने वाले सिग्नल की ऑडियो-विजुअल सूचना प्राप्त कर सकता है।
- जीपीएस नेटवर्क से जुड़ी सभी मॉडिफाइड स्वचालित सिग्नल इकाइयों की सिग्नल प्रणाली का अपग्रेडेशन।
- साइटिंग बोर्डों, लेवल क्रासिंग बोर्डों, फॉग सिग्नल चौकियों इत्यादि को चमकदार पेंट से बेहतर बनाना। रेल पटरियों के साथ लाइम मार्किंग की गई है। इससे कोहरे के दौरान दृश्यता कम होने पर आने वाले सिग्नलों और बोर्डों की जानकारी मिलती है।
- कोहरे के अवधि के दौरान इंजनों/ड्राइवरों/लिंक रेकों की योजना बनाना एवं उनकी समीक्षा करना ताकि चालक दल को आराम करने का पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही, चल स्टॉक की साफ-सफाई और अनुरक्षण ठीक प्रकार से किया जा सके। इससे रेलगाड़ी की अगली सेवा बिना विलम्ब के चलाना सम्भव हो सके।
- स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति को जांचने के लिए स्टेशन मास्टरों द्वारा विजिबिलिटी टेस्ट किए जाते हैं।
- कम दृश्यता संबंधी मामलों से निपटने के लिए लोको पायलटों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वह रेल पथों पर परिस्थिति के अनुसार रेलगाड़ी की गति सीमा को अपने विवेक और सूझ-बूझ के साथ नियंत्रित करेगा।

पुरट्चि तलैवर डॉ. एम.जी.आर. सेंट्रल स्टेशन भवन की रोचक जानकारी

श्री विमलेश चन्द्र

दक्षिण भारत में पहली रेलवे की शुरुआत तत्कालीन ईस्ट इंडियन रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे से काफी पहले ही प्रस्तावित हो गई थी। भले ही इसकी वास्तविक शुरुआत इन दोनों के बाद हो पाई थी।

दक्षिण भारत में पहली रेलवे की शुरुआत – भारत में तत्कालीन कलकत्ता प्रेसीडेंसी और बंबई प्रेसीडेंसी द्वारा रेल लाइनों को बनाने का प्रस्ताव रखने के काफी पहले ही अर्थात् वर्ष 1832 में ही मद्रास प्रेसीडेंसी द्वारा मद्रास में रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रकार मद्रास प्रेसीडेंसी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1836 में चींतादिरीपेंट के पास में तथा वर्ष 1837 में मद्रास के दक्षिण पूर्व में रेड हिल्स और लिटिल माउंट की पत्थर की खदानों में रेल लाइन बिछाई गई थी। मद्रास प्रेसीडेंसी में रेलवे लाइन के निर्माण और रेलगाड़ी के संचालन के लिए 8 जुलाई, 1845 को लंदन में मद्रास रेलवे कंपनी का गठन किया गया था। इसका सबसे पहला कार्य मद्रास से वालाजानगर और अर्काट के लिए रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करना था। इसे स्वीकृति नहीं मिलने पर बाद में पुनः आवेदन किया गया। 26 जुलाई, 1852 को मद्रास रेलवे कंपनी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। उस समय देश के दक्षिण भाग में कुल 5 प्रधान रेल प्रणालियाँ थीं – मद्रास रेलवे, साऊथ इंडियन रेलवे, सदर्न मराठा रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे (दक्षिणी खंड) सरकारी रेलवे और पांचवीं किन्तु स्वतंत्र रेल प्रणाली, मैसूर स्टेट रेलवे प्रणाली थी। 1 जनवरी, 1908 को इनका पुनर्गठन हुआ था।

भारतीय रेल में सर्वप्रथम गठित क्षेत्रीय रेलवे – दक्षिण रेलवे का गठन 14 अप्रैल, 1951 को मद्रास और सदर्न मराठा रेलवे, साऊथ इंडियन रेलवे तथा मैसूर स्टेट रेलवे को मिलाकर हुआ था। गठन के समय इसकी लंबाई 9,682 किमी थी। यह भारतीय रेल में सर्वप्रथम गठित क्षेत्रीय रेलवे है। इनमें पहले दोनों रेलवे को 1 अप्रैल, 1944 को तथा मैसूर स्टेट रेलवे को 1 अप्रैल, 1950 को सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। दक्षिण रेलवे का बेंगलुरू मंडल और मैसूर मंडल को 1 अप्रैल, 2003 को दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली में मिला दिया गया था। नए क्षेत्रीय रेलवे के गठन के समय 1 अप्रैल, 2003 को इस रेलवे की लम्बाई 5,235 रूट किमी थी। जिसमें चेन्नै 844 रूट किमी, मदुरै 1,451 रूट किमी, पालघाट 1140 रूट किमी, त्रिची 1,174 रूट किमी तथा त्रिवेन्द्रम् 626 रूट किमी थे।

देश के सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन और दक्षिण भारत का एवं दक्षिण रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, चेन्नै सेंट्रल-चेन्नै शहर, तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है। पहले इसका नाम मद्रास सेंट्रल था। वर्ष 1996 में इसका नाम 'मद्रास सेंट्रल' से 'चेन्नै सेंट्रल' रखा गया। 5 अप्रैल, 2019 को इसका नाम तमिलनाडु के स्वर्गीय मुख्य मंत्री डॉ. एम. जी. रामचंद्रन के नाम पर 'पुरट्चि तलैवर डॉ. एम.जी.आर. सेंट्रल स्टेशन' रखा गया है। राज्य के प्रिय अभिनेता और राजनेता एमजीआर के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. एम.जी. रामचंद्रन की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर एआईएडीएमके सरकार ने अपने संस्थापक एमजीआर के नाम पर सेंट्रल स्टेशन का नाम रखने की सिफारिश की थी। यह नाम इस समय भारतीय रेल के सभी स्टेशनों में सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन है। यह अपने आप में एक रिकार्ड है। यहाँ से पूरे भारत में सभी तरफ से जाने वाली रेलगाड़ियों का संचालन होता है। यहीं से उपनगरीय रेल गाड़ियों का भी संचालन होता है। यह स्टेशन मूर मार्केट कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, चेन्नै पार्क रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है।



चेन्नै के 4 खूबसूरत रेलवे भवन

भारतीय रेल का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भवन – रायपुरम रेलवे स्टेशन वर्तमान समय में भारतीय रेल का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भवन है, जो अभी भी उपयोग में है। इस स्टेशन भवन की शुरुआत 28 जून, 1856 को हुई थी। जब यहाँ से पहली रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। 28 जून, 1856 को तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हैरिस द्वारा मुख्य टर्मिनस और रोयापुरम स्टेशन भवन का उद्घाटन किया गया था। वर्ष 1922 तक यह स्टेशन भवन मद्रास एंड सदर्न मराठा रेलवे का मुख्यालय बना रहा जब तक कि इस रेलवे का यह मुख्यालय एग्मोर में स्थानांतरित नहीं हो गया। इसलिए रायपुरम स्टेशन वर्तमान समय में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे

पुराना रेलवे स्टेशन है। इसका विद्युतीकरण 9 अगस्त, 1979 को किया गया था। इस भवन का वर्ष 2005 में नवीनीकरण करने के बाद 2 अक्टूबर, 2005 को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था।

दक्षिण रेलवे का खूबसूरत और विशाल मुख्यालय भवन – दक्षिण रेलवे का मुख्यालय भवन एक बहुत खूबसूरत और विशाल भवन है। इस भवन के निर्माण के लिए जमीन का कार्य वर्ष 1913 में शुरू किया गया था तथा इस भवन का शिलान्यास 8 फरवरी, 1915 को मद्रास के गवर्नर लॉर्ड पेंटलैंड के द्वारा किया गया था। इसके कांट्रैक्टर टी. साम्यनदा पिल्लई थे। इस स्टेशन भवन का डिजाइन मि.एन. ग्रेसन द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन 11 दिसम्बर, 1922 को हुआ था। यह चेन्नै सेंट्रल स्टेशन के पास में ही है। पहले यह भवन तत्कालीन मद्रास एंड सदर्न मराठा रेलवे कम्पनी का मुख्यालय था।

एषुंबूर रेलवे स्टेशन भवन – एषुंबूर रेलवे स्टेशन को अंग्रेजी में 'एग्मोर' कहते हैं। यह स्टेशन भवन तत्कालीन साउथ इंडियन रेलवे के अधीन था। एषुंबूर रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण कार्य सितंबर, 1905 में शुरू हुआ था तथा 11 जून, 1908 को खोला गया था। यह स्टेशन भवन ईंटों से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत और रंग-बिरंगा भवन है। इस भवन के किनारों पर बलुआ और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। इसके छत पर लगे हुए पत्थरों पर बहुत ही सूक्ष्मता और कलाकारी के साथ नक्काशी की गई है, जो इस भवन की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। इस भवन का डिजाइन मिस्टर हेनरी इर्विन सी.आई.ई. ने तैयार किया था तथा इसका निर्माण कार्य बेंगलुरू के कांट्रैक्टर मिस्टर टी. स्वामीनाडा पिल्लई ने किया था। यह भवन मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है।



चेन्नै सेंटल स्टेशन बोर्ड

चेन्नै सेंट्रल रेलवे स्टेशन भवन की रोचक जानकारी – मद्रास सेंट्रल स्टेशन भवन का निर्माण वर्ष 1873 में किया गया था। इस स्टेशन भवन का डिजाइन जॉर्ज हार्डिंग ने किया था। इसे 7 अप्रैल, 1873 को यातायात के लिए खोला गया था। स्टेशन भवन के निर्माण के शुरू होने के कुछ वर्ष बाद इसके डिजाइन में फिर से सुधार किया गया तथा बीच में एक क्लॉक टॉवर भी लगाया गया तथा मुख्य टॉवर पर ट्रावनकोर का प्रतीक भी बनाया गया। इसके कुछ बचे हुए छोटे-मोटे कार्यों को वर्ष 1907 में पूरा किया गया था। वर्ष 1932 में इसे पूरी तरह आधुनिक बनाया गया था। वर्ष 1907 में इसे मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा अपना मुख्य रेलवे स्टेशन बनाया गया था।

मद्रास एंड सदर्न रेलवे कंपनी का वर्ष 1908 में गठन होने पर इस स्टेशन को अपने अधीन ले लिया गया। वर्ष 1980 में मद्रास स्टेशन के टर्मिनस के विस्तार करने की आवश्यकता होने पर इसे मूरी मार्केट भवन की तरफ विस्तार का विचार किया जा रहा था। वर्ष 1985 में मूरी मार्केट भवन में भयंकर आग लगने पर सब कुछ नष्ट हो गया था, जिसके कारण इस जगह को राज्य सरकार द्वारा रेलवे को दे दिया गया। फलस्वरूप, रेलवे ने यहाँ अपना 13 तल का भवन और उपनगरीय रेलवे का टर्मिनल स्टेशन बनाया, साथ ही साथ, रेलवे आरक्षण कार्यालय खोला। वर्ष 1998 में इस मुख्य भवन के पश्चिमी तरफ इसी तरह का एक नया भवन बनाया गया। यह मुख्य भवन लाल ईंटों से बना हुआ है तथा गोथिक स्थापत्य कला का एक अच्छा उदाहरण है। वर्ष 1873 से अभी तक इसका रंग मैरून या भूरे रंग का है। इसके स्टेशन भवन का क्षेत्रफल 14,062 वर्ग मीटर है। शुरुआत में यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म थे। वर्तमान में यहाँ कुल 17 प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें 12 प्लेटफॉर्म लंबी दूरी की गाड़ियों के लिए हैं जबकि 5 प्लेटफॉर्म उपनगरीय रेलगाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्लेटफॉर्म 2ए के नाम से बना हुआ है।



उपनगरीय रेलवे को मिलाकर यहाँ से प्रतिदिन 500 रेलगाड़ियों का आवागमन होता है, जिसमें 200 से कुछ ज्यादा लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ शामिल हैं। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 6 लाख लोग यात्रा करते हैं। वर्ष 2010 में इसका नवीनीकरण का काम किया गया, जिससे यह और अधिक आकर्षक तथा सुविधाजनक हो गया है। इसके पास में 25 मीटर की गहराई पर मेट्रो स्टेशन भी बन रहा है, जिससे यहाँ यात्री यातायात और बढ़ जाएगा। यह स्टेशन भारतीय रेल के पुराने स्टेशनों में से एक है। यह स्टेशन भारतीय रेल और तमिलनाडु का गौरव है। ■

सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर,
अहमदाबाद मंडल

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे : विश्व विरासत स्थल घोषित हुए 20 साल पूर्ण

यूनेस्को द्वारा 5 दिसंबर, 1999 को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर) को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के इस बार विश्व विरासत घोषणा के 20 साल पूर्ण हुए हैं। मालूम हो कि यूनेस्को द्वारा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के शिलालेख में उल्लेखित किया गया है कि सन् 1881 में शुरू की गई दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हिल पैसेंजर रेलवे के रूप में पहली पैसेंजर रेल का विशिष्ट उदाहरण है जो अभी भी बरकरार है। यहां पूरे पहाड़ी इलाके के सुन्दर स्थलों में प्रभावी रेल लिंक स्थापित करने के लिए साहसिक और सरल इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया है।

यह अभी भी पूर्ण रूप से क्रियाशील है और इसकी मूल विशेषताएं अक्षुण्ण हैं। यूनेस्को के उपरोक्त वाक्यों को सही ठहराते



फोटो : योगेश अवस्थी

↗ *बताशिया लूप में डीएचआर ट्वाय ट्रेन*

↘ *विस्टाडोम कोच*



हुए विश्व प्रसिद्ध डीएचआर अभी भी सिलिगुड़ी के मैदानी भाग से दार्जिलिंग के बीच हिल कार्ट रोड के साथ चलती है। उल्लेखनीय है कि इस हिल कार्ट रोड का निर्माण सन् 1831 में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट नेपियर द्वारा कराया गया था। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच की यात्रा काफी मनोहारी है, जो प्रकृति प्रेमियों को भाती है। पूरे विश्व के पर्यटक मुख्य रूप से दार्जिलिंग की यात्रा डीएचआर की सवारी का आनन्द उठाने के लिए करते हैं। इससे दार्जिलिंग क्षेत्र को आर्थिक दिशा के सुधार में सहायता मिलती है।

उल्लेखनीय है कि, 2 फीट (610 मिमी) चौड़े गेज वाले डीएचआर का निर्माण सन् 1879 में शुरू हुआ। यह मार्च, 1880 में तिनधरिया तक और अप्रैल, 1881 में घूम तक पहुंचा। शुरुआत में इससे चार पूर्ण लूप और चार जेड रिवर्स थे, लेकिन आज डीएचआर में तीन लूप और छह जेड रिवर्स हैं और उनके जरिए चढ़ना काफी लुभावना है। न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू होकर दार्जिलिंग तक 13 स्टेशन हैं। हालांकि डीएचआर की पुरानी नैरो गेज ट्रेनों को केवल स्टीम इंजनों द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन आज स्टीम और डीजल इंजनों द्वारा संचालित किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने पहले ही डीएचआर में विस्टाडोम कोच शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से पर्यटक यात्रा के दौरान हिमालयी इलाके का बेहतर प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को उम्मीद है कि विश्य विरासत घोषणा की 20वीं वर्षगांठ मनाने की योजना डीएचआर में पर्यटन को और बढ़ावा देने में मदद करेगी। ■

उत्तर मध्य रेलवे

महाप्रबंधक द्वारा ट्रेन संचालन में संरक्षा हेतु उल्लेखनीय योगदान देने वाले रेलकर्मी पुरस्कृत

11 नवम्बर को उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र में ट्रेन संचालन में संरक्षा की दृष्टि से उल्लेखनीय योगदान करने वाले 21 रेल कर्मियों को महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, श्री राजीव चौधरी ने पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। पुरस्कृत होने वालों में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, प्वाइंट्समैन एवं ट्रैक मेंटेनर शामिल थे।

इस अवसर आयोजित संरक्षा/समयपालनता बैठक को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे श्री राजीव चौधरी ने सम्मानित होने वाले रेलकर्मियों की संरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता एवं असाधारण सतर्कता द्वारा संभावित दुर्घटनाओं को टालने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने बल दिया कि भारतीय रेल एवं उत्तर मध्य रेलवे में संरक्षा रेल के सभी कार्यों के निष्पादन हेतु मूलभूत दर्शन के रूप में अंतर्निहित है। महाप्रबंधक ने कहा कि संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन संचालन संबंधी सभी नियमों और विनियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और संरक्षा से जुड़े स्टाफ को रिफ्रेशर कोर्सों के लिए भेजा जाए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अधिकारियों को नियमित रात्रिकालीन निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया और साथ ही निरीक्षणों के दौरान कार्यस्थलों के निरीक्षण के लिए निर्देशित करते हुए कार्यस्थलों पर संरक्षा से जुड़े मानदंडों के अनुपालन को भी देखने का निर्देश दिया।



संरक्षा की दृष्टि से उल्लेखनीय योगदान करने वाले रेलकर्मियों को सम्मानित करते हुए महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे श्री राजीव चौधरी

इसी क्रम में उन्होंने ट्रेन परिचालन में संरक्षा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गतिशीलता में सुधार लाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रीडिपार्चरडिटेंशन से जुड़े विषयों की सघन निगरानी की जाए ताकि ट्रेनों की समयपालनता में और सुधार हो और कोई भी ट्रेन ऐसे कारणों से विलंबित न हो।

इस अवसर पर कर्मचारियों को मुख्य संरक्षा अधिकारी श्री एस.के. कश्यप और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह एवं समीक्षा बैठक में उत्तर मध्य रेलवे के सभी प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीन मंडलों इलाहाबाद, आगरा और झांसी के मंडल रेल प्रबंधक उपस्थित थे। ■

दक्षिण पूर्व रेलवे

खड़गपुर में रेंजरिंग की शताब्दी समारोह का आयोजन

दक्षिण पूर्व रेलवे के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा खड़गपुर में 14 से 18 अक्टूबर, 2019 को रेंजरिंग की शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में शताब्दी शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री संजय कुमार मोहंती, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे एवं संरक्षक, दक्षिण पूर्व रेलवे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने किया। महाप्रबंधक ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के योगदान एवं आपदा एवं दुर्घटना के समय उनके द्वारा की गई सेवा एवं सहायता के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि सन् 1908 में लॉर्ड बेडेन पावेल द्वारा कल्पना की गई स्काउट्स एंड गाइड्स आंदोलन बच्चों के चरित्र को बेहतर बनाने और उन्हें देश का कर्तव्यनिष्ठ नागरिक



बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बाद में 16 से 25 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के साथ रेंजर समूह का गठन वर्ष 1919 में लड़कियों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए किया गया था।

श्री जे के साहा, प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता एवं राज्य के मुख्य आयुक्त ने अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। श्री के आर के रेड्डी, मंडल रेल प्रबंधक, खड़गपुर एवम् अध्यक्ष, दक्षिण पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, जिला, खड़गपुर ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया।

दक्षिण पूर्व रेलवे के सभी मंडलों एवम् मुख्यालय के साथ-साथ पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के रोवर्स एवम् रेंजर्स ने इस मेगा कार्यक्रम में भाग लिया। कुल मिलाकर 400 रोवर्स एवम् रेंजर्स ने विभिन्न परियोजनाओं जैसे इकेबाना, वाद विवाद, रंगोली, क्विज इत्यादि में भाग लिया। ■

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अगस्त तक 52.91% ट्रैक रिन्युअल कर भारतीय रेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया

भारतीय रेल के एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगभग 5172.530 ट्रैक रूट किलोमीटर रेल लाइन के साथ प्रतिदिन औसत लगभग 356 यात्री गाड़ियों के साथ-साथ माल गाड़ियों का भी परिचालन करती है। इतनी बड़ी संख्या में रेल लाइनों पर गाड़ियों के परिचालन से निश्चित ही रेल लाइनों को रिन्युअल की आवश्यकता होती है। अगर रेल लाइनों की बात की जाए तो यह मात्र लोहे के दो पटरियों को समतल जगह पर गिट्टी के ऊपर बिछाकर रेल चलाने जितनी सरल नहीं है। रेल परिचालन जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही जरूरी रेल पटरियों का मेंटेनेंस भी है। संरक्षा की दृष्टि से तो यह और भी अति आवश्यक है। रेल लाइनों के रिन्युअल एवं मेंटेनेंस में, मुख्य रूप से रेल लाइनों की लाइनिंग, लेवलिंग एवं अलाइनमेंट बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ रेल लाइनों के नीचे बिछी हुई गिट्टी या बैलास्ट लाइनों के लिए कुशन का कार्य करती है तथा रेल लाइनों के ऊपर पड़ने वाले गाड़ियों के भार को सही मात्रा में बाँटकर रेल यात्रियों की आरामदायक यात्रा को सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रेल लाइनों के रिन्युअल के लिए इस वर्ष अप्रैल से अगस्त, 2019 तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 116.4 किमी रेल लाइन के रिन्युअल का कार्य पूर्ण कर लिया है। यह इस जोन



को दिए गए टार्गेट का 52.91 % है। यह उपलब्धि भारतीय रेल के अन्य रेलवे की तुलना में प्रतिशत की आधार पर सर्वाधिक है जबकि दूसरे नंबर पर पश्चिम रेलवे 46% एवं तीसरे नंबर पर उत्तर पश्चिम रेलवे 42.07% पर है। ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, रेल कर्मचारी 24 घंटे के समय का एक-एक मिनट का सदुपयोग करते हुए संरक्षित रेल परिचालन के लिए कार्य करता है। इसके साथ ही साथ इसी दौरान रेलवे लाइनों पर ट्रैकों के रिन्युअल एवं मेंटेनेंस करने वाली मशीनों से भी कार्य लिया जाता है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लगभग 48 ट्रैक मशीनें उपलब्ध हैं जिनमें से बलास्ट या गिट्टी को साफ करने वाली 6 बीसीएम मशीनें, प्वाइंट एंड क्रॉसिंग का मेंटेनेंस करने वाली 5 यूनिमेट मशीनें, रेल लाइनों की पैकिंग करने वाली 6 ड्योमैटिक मशीनें, रेल लाइन बिछाने वाली 06 पीक्यूआरएस/ एसक्यूआरएस/ टी-28 मशीनें शामिल हैं। ■

रायपुर रेलवे स्टेशन में अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाने वाली मशीन का उद्घाटन



रायपुर रेलवे स्टेशन के गुढ़ियारी छोर पर रनिंग रूम, रायपुर के पीछे की तरफ अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाने वाली मशीन की कमीशनिंग की गई है। 15 नवम्बर को मशीन का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक श्री कौशल किशोर रायपुर के द्वारा किया गया। मशीन की क्षमता 250 किलोग्राम प्रतिदिन है। मशीन का संचालन पूरी तरह से स्वचालित है और बायो कचरे को खाद में बदलने के लिए प्रक्रिया का समय 24 घंटे है। रनिंग रूम रायपुर में उत्पन्न जैव अपशिष्ट, स्टेशन पर स्टालों से उत्पन्न खाद्य अपशिष्ट और फलों के अपशिष्ट को संसाधित किया जा रहा है और अच्छी गुणवत्ता वाली खाद बनाई जा रही है। इस खाद को रायपुर मंडल के विभिन्न स्थानों पर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बनाए गए उद्यानों में उपयोग करने की योजना है। यह प्रक्रिया एनजीटी के दिशा-निर्देशों का हिस्सा है। ■

उत्तर पश्चिम रेलवे

लोडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए मालभाड़ा ग्राहकों के साथ बैठक

उत्तर पश्चिम रेलवे पर लोडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 23 अक्टूबर, 2019 को प्रधान कार्यालय में प्रमुख मालभाड़ा ग्राहकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री आनन्द प्रकाश, महाप्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे ने की। उन्होंने कहा कि मालभाड़ा की वर्तमान में चल रही योजनाओं का सभी ग्राहक लाभ उठाएं तथा लदान



को बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रेलवे सदैव अपने ग्राहकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करती है और उनको आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सदैव प्रत्यनशील रहती है। इसके अतिरिक्त प्रमुख विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक, जयपुर तथा चारों मंडलों के वरिष्ठ वाणिज्य एवं परिचालन प्रबंधक उपस्थित थे। ■

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

महिला सशक्तीकरण : स्टेशन स्वच्छता की जिम्मेदारी सेल्फ हेल्प ग्रुप पर



स्वच्छ रेल मिशन के हिस्से और जीविकोपार्जन के अवसरों के साथ महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने विशिष्ट पहल शुरू की है, जिसके तहत कई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप (ओसएचजी) को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे हैलाकांडी जिले में रेलवे स्टेशनों को साफ-सुथरा रखने के काम में लगाया है। इस पहल के तहत एक समझौते के जरिए हैलाकांडी जिला प्रशासन रोजगार और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में बेहतर सहयोग प्रदान कर रहा है। वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे नवनिता एसएचजी, लोकनाथ एसएचजी और मां मनोशा एसएचजी क्रमशः हैलाकांडी जिले के पांचग्राम, हैलाकांडी और लालाबाजार स्टेशनों के रख-रखाव में लगे हुए हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी जीविकोपार्जन मिशन के जरिए चलाया जा रहा है। यह पहल इस इलाके के जरूरतमंद महिलाओं के रोजगार में वृद्धि कर रही है। ■

ट्रेनों की गति में वृद्धि हेतु पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की पहल

निर्धारित समय पर बेहतर तरीके से ट्रेन के परिचालन तथा यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाओं में सुधार करने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने अपने क्षेत्राधिकार में ट्रेनों की गति में वृद्धि करने की पहल की है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने विभिन्न कारणों से ट्रैक पर स्थापित 17 स्थाई गतिरोधकों (पीएसआर) को हटा दिया है,फलस्वरूप, संबंधित अनुभागों में सभी ट्रेनों के परिचालन में 4.6 मिनट की बचत होगी। इस वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर महीने तक 170.50 किमी रेलवे ट्रैक पर गति में वृद्धि की गई है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने अलीपुरद्वार मंडल में फकीराग्राम-न्यू बोंगाईगांव तथा न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू कूचबिहार के बीच 3 पीएसआर, कटिहार मंडल में न्यू-जलपाईगुड़ी-रानीनगर के बीच एक पीएसआर तथा लामडिंग मंडल में लामडिंग-गुवाहाटी के बीच 13 पीएसआर, (कुल 17) को हटा दिया ह। इन्हें तंग मोड़, रेलवे ट्रैक की संकोचन अथवा रेलवे ट्रैक पर कर्व के अपर्याप्त संक्रमण हिस्से जैसे विभिन्न कारणों से रेलवे ट्रैक से हटाया गया है।

उल्लेखनीय है कि अलीपुरद्वार मंडल में न्यू कूचबिहार-गोलकगंज के बीच 59 किमी के विस्तार में 70 किमी प्रति घंटे से गति वृद्धि कर 90 किमी प्रति घंटे, लामडिंग मंडल में लामडिंग-हबाईपुर के बीच 25 किमी के विस्तार में 75 किमी प्रति घंटे से विस्तार कर 105 किमी प्रति घंटे तथा तिनसुकिया मंडल के फारकाटिंग-जोरहाट-मरियानी के बीच 86.5 किमी के विस्तार में गति 50 किमी प्रति घंटे से विस्तार कर 75 किमी प्रति घंटे किया गया है, इसमें कुल 170.50 किमी रेलवे ट्रैक शामिल है। हबाईपुर-लामडिंग अनुभाग के 3 स्टेशनों में लूप लाइनों पर वर्तमान गति 15 किमी प्रति घंटे से विस्तारित कर 30 किमी प्रति घंटे कर दी गई है।

संबंधित स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर से गतिरोधकों को हटाए जाने तथा इन अनुभागों में ट्रेनों की गति में वृद्धि से ट्रेनों के निर्धारित समय पर परिचालन में सुधार होगा तथा यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सकेगी। ■

वर्ष 2020 तक रेलवे स्टेशनों पर 25 एस्केलेटर एवं 32 लिफ्टों की स्थापना करेगी

बड़े स्टेशनों पर विभिन्न प्लेटफॉर्मों तक पहुँचने के लिए फुट ओवर ब्रिजों का इस्तेमाल करने में विशेष रुप से बुजुर्ग यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट एवं चलायमान सीढ़ियों (एस्केलेटर) की आवश्यकता होती है। ट्रेनों पर आराम से तथा समय पर सवार होने के लिए यात्रियों के सुविधार्थ भारतीय रेल ने और अधिक लिफ्टों तथा चलायमान सीढ़ियों की व्यवस्था करने का निर्णय किया है।

वर्तमान में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पांच मंडलों के अधीन प्रमुख स्टेशनों पर 11 लिफ्ट तथा 10 चलायमान सीढ़ियां परिचालित हो रही हैं। इसके अलावा, पू. सी. रेलवे दिसंबर, 2020 तक अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न स्टेशनों में 25 चलायमान सीढ़ियों एवं 32 लिफ्टों की स्थापना करने की प्रक्रिया कर रही है। स्थापित 10 चलायमान सीढ़ियां न्यू जलपाइगुड़ी, गुवाहाटी एवं न्यू कूचबिहार स्टेशनों पर परिचालित हैं। जबकि इस वर्ष दिसंबर तक रंगिया, न्यू तिनसुकिया, कामाख्या तथा लामडिंग स्टेशनों पर (प्रत्येक स्टेशन पर दो) और 8 चलायमान सीढ़ियों की स्थापना की जाएगी। अगले वर्ष दिसंबर तक गुवाहाटी (6), लामडिंग (3), अगरतला (2), कटिहार (4) तथा किशनगंज (2) और चलायमान सीढ़ियों की स्थापना की जाएगी। इसी तरह, तिनसुकिया (1), गुवाहाटी (2), न्यू कूचबिहार (2), न्यू जलपाइगुड़ी (2), लामडिंग (2) तथा कटिहार (2) आदि में 11 लिफ्टें परिचालित हो रही है। जबकि इस वर्ष के अंत तक तिनसुकिया (1), कामाख्या (1), गुवाहाटी (2) तथा डिब्रूगढ़ (2) अर्थात् कुल 6 और लिफ्टों की शुरुआत की जाएगी, और जून, 2020 तक और 26 लिफ्टों की स्थापना की जाएगी। आशा व्यक्त की गई है कि इन चलायमान सीढ़ियों तथा लिफ्टों की स्थापना से पूर्वोत्तर के यात्रियों की कठिनाइयां काफी हद तक कम हो जाएँगी। ■

पश्चिम रेलवे

सोमनाथ में ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पर मेंटेनेंस स्टडी ग्रुप की बैठक का आयोजन



मेंटेनेंस स्टडी ग्रुप की बैठक में रेलवे बोर्ड की अपर सदस्य (बिजली) श्रीमती मंजु गुप्ता उपस्थित रहीं

ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पर मेंटेनेंस स्टडी ग्रुप की 31वीं बैठक का आयोजन सोमनाथ में 8 एवं 9 नवम्बर को किया गया, जिसमें रेलवे बोर्ड, आरडीएसओ तथा सभी क्षेत्रीय रेलों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता रेलवे बोर्ड की अपर सदस्य (बिजली) श्रीमती मंजु गुप्ता ने की। उन्होंने बैठक में कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7,500 रूट किलोमीटर को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। उन्होंने पश्चिम रेलवे के सहयोग की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1,500 रूट किलोमीटर विद्युतीकृत किया जाना है। उन्होंने कहा टीआरडी असेट्स में सुधार की आवश्यकता है, जिससे ओवरहैड इक्युपमेंट में किसी भी प्रकार का फेलियर न हो सके। टीआरडी असेट्स का अनुरक्षण तथा सुपरवाइजरों और स्टाफ की नॉलेज को अपग्रेड करना, विशेषकर उन क्षेत्रीय रेलों के लिए एक चुनौती है, जहाँ पूर्व में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बैठक के दौरान इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑपरेशन में फेलियर को दूर करने के लिए ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनेंस तथा ओवरहेड इक्युपमेंट एवं पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन के अनुरक्षण के दौरान ध्यान में आए हुए विभिन्न विषयों पर बैठक में चर्चा हुई। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा उठाए गए, प्रस्तावित किए गए अन्य अभिनव सुझावों को प्रस्तुत किया गया तथा इस पर विचार-विमर्श किया गया। पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर श्री संजीव भूटानी ने भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री प्रतीक गोस्वामी तथा उनकी टीम को इस बैठक के सफल आयोजन और लॉजिस्टिक सपोर्ट तथा 8 नवम्बर, 2019 को भावनगर मंडल पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। रेलवे बोर्ड की अतिरिक्त सदस्य श्रीमती मंजु गुप्ता ने पश्चिम रेलवे की टीम को बैठक के सफल आयोजन के लिए 1 लाख रु. तथा भावनगर मंडल की सांस्कृतिक टीम के कलाकारों को मनोरंजक प्रस्तुति के लिए 20 हजार रु. का अवॉर्ड घोषित किया। ■

पश्चिम रेलवे द्वारा 'विश्व धरोहर सप्ताह' की आयोजन





पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय भवन परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में पुरातात्त्विक नमूनों का अवलोकन करते हुए एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पश्चिम रेलवे हेरिटेज कम्पेंडियम 'रेट्रोस्पेक्टिंग इन्टु अवर ग्रेट लीगेसी थ्रू मैग्निफिशेंट हेरिटेज' का विमोचन करते हुए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री ए. के. गुप्ता और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. नंदिनी भट्टाचार्या

पश्चिम रेलवे द्वारा 19 नवम्बर, 2019 को चर्चगेट स्थित प्रधान कार्यालय भवन के परिसर में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सहयोग से आयोजित आकर्षक प्रदर्शनी तथा विभिन्न हेरिटेज पुस्तकों के विमोचन के साथ 'विश्व धरोहर सप्ताह' का शुभारंभ हुआ।

समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री ए. के. गुप्ता द्वारा दो दिवसीय धरोहर प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। 'विश्व धरोहर सप्ताह' के अंतर्गत इन कार्यक्रमों में पश्चिम रेलवे द्वारा अपनी स्थापना के समय से रेलवे के गौरवशाली युग के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ अपनी समृद्ध विरासत को दर्शाया गया।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा मुंबई क्षेत्र के धरोहर स्थलों पर प्रस्तुतिकरण तथा बांद्रा स्टेशन के हेरिटेज रिस्टोरेशन सम्बंधी प्रस्तुतिकरण प्रधान कार्यालय के गोडबोले हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री ए. के. गुप्ता ने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की विवरणिका के साथ-साथ 'ट्रैवलिंग इन टाइम' शीर्षक से पश्चिम रेलवे द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक और 'रेट्रोस्पेक्टिंग इन्टु अवर ग्रेट लीगेसी थ्रू मैगनिफिशेंट हेरिटेज' शीर्षक से पश्चिम रेलवे के हेरिटेज कम्पेंडियम का विमोचन भी किया।

उसके बाद भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के कलाकारों द्वारा 'खजुराहो के शिल्पी' शीर्षक से एक विशेष नाटक का मंचन भी किया गया, जिसके अंतर्गत खजुराहो मंदिर के निर्माण सम्बंधी वृत्तांत को दिखाया गया। ■

पूर्व तट रेलवे

पूर्व तट रेलवे की ओर से मधुमेह जागरुकता कार्यक्रम एवं स्वस्थ आहार प्रदर्शनी

'विश्व मधुमेह दिवस' के अवसर पर पूर्व तट रेलवे के तत्वावधान में 'मधुमेह जागरुकता कार्यक्रम' एवं स्वस्थ आहार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

महाप्रबंधक श्री विद्या भूषण ने इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक श्री सुधीर कुमार की उपस्थिति में रेल सदन में मधुमेह आधारित स्वस्थ आहार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।



इससे पहले सेंट्रल हॉस्पिटल, मंचेश्वर में मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. अरुंधती सेनापति के नेतृत्व में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ ने ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन किया। 'विश्व मधुमेह दिवस' के अवसर पर मधुमेह जागरुकता को लेकर रेल सदन में एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इससे पहले सुबह महाप्रबंधक ने रेल सदन से सेंट्रल हॉस्पिटल, मंचेश्वर तक हुए वॉकाथॉन में सभी प्रतिभागियों का नेतृत्व किया। ■

पूर्वोत्तर रेलवे

हिंदी नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन

19 सितम्बर को मुख्यालय कला समिति एवं लखनऊ कला समिति के कलाकारों के मध्य हिंदी नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री श्रीकान्त सिंह, मुख्य राजभाषा अधिकारी ने की। लखनऊ मंडल की ओर से गिरीश चंद्र घोष की कहानी पर आधारित 'अबू हसन' नाटक का मंचन किया गया। गोरखपुर, मुख्यालय की ओर से श्री आसिफ जहीर द्वारा निर्देशित एवं मीरा सिकदर, शशि शेखर राय, मनोज कु. श्रीवास्तव सहित अन्य कलाकारों द्वारा नाटक (अभिनेत्री) का मंचन किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा 'अबू हसन' नाटक को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया।



उक्त नाट्य प्रतियोगिता में श्री संत श्रीवास्तव, वरिष्ठ रंगकर्मी तथा श्री रत्नेश मिश्रा, प्रोडक्शन अधिकारी/दूरदर्शन केन्द्र निर्णायक मंडल में थे। ■

मध्य रेल

'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' कार्ड धारकों का इलाज अब मध्य रेल के नामांकित अस्पताल में होगा

'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' लाभार्थी धारक को ई-कार्ड मिलता है। वह देश के किसी भी स्थान पर स्थित योजना के सूचीबद्ध अस्पताल में सेवा का लाभ ले सकता है।

कवरेज में शामिल हैं :

- 3 दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती और 15 दिन बाद अस्पताल में भर्ती का खर्च।
- सभी संबंधित लागतों, जैसे ऑपरेशन थिएटर खर्चों के साथ लगभग 1,400 प्रक्रियाओं का ध्यान रखते हुए खर्च रखा जाता है।
- पीएमजेएवाई ने सरकारी और निजी अस्पतालों में 1,350 से अधिक मेडिकल पैकेजों के लिए कवरेज का विस्तार किया है।
- यह रुपये 5 लाख / परिवार / वर्ष का कवरेज प्रदान करता है।

मध्य रेल में छह अस्पतालों को पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध किया गया है। जो निम्नवत हैं : -

1) क्षेत्रीय अस्पताल (डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल, भायखला, मुंबई)
2) मंडल रेलवे अस्पताल, कल्याण
3) मंडल रेलवे अस्पताल, पुणे
4) मंडल रेलवे अस्पताल, सोलापुर
5) मंडल रेलवे अस्पताल, भुसावल
6) मंडल रेलवे अस्पताल, नागपुर

यदि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) ई-कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी रेलवे अस्पताल में आता है तो उसे आवश्यक द्वितीय अथवा तृतीय मुफ्त प्रति वर्ष, प्रति परिवार अधिकतम रुपये 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। ■

मध्य रेल के मुंबई–कल्याण खंड के विद्युतीकरण के 91 वर्ष पूरे

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (तत्कालीन विक्टोरिया टर्मिनस) से कल्याण के लिए रेलवे विद्युतीकरण 12 नवम्बर, 1928 को 1500 वोल्ट डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के साथ शुरू किया गया था। विद्युतीकरण को बाद में नॉर्थ ईस्ट लाइन में इगतपुरी तक और साउथ ईस्ट लाइन में पुणे तक बढ़ाया गया। पहली यात्री ट्रेन, डेक्कन क्वीन, इलेक्ट्रिक लोको डब्ल्यूसीपी–1 के साथ 1 जून, 1930 को बॉम्बे वीटी (अब सीएसएमटी) और पूना (अब पुणे) के बीच चली।



पृष्ठभूमि

1500–वोल्ट डीसी सिस्टम पर ओवर हैड इक्विपमेंट पावर को 1500 वोल्ट पर रेक्टिफायर फेड ट्रैक्शन सबस्टेशन (टीएसएस) से सप्लाई किया जा रहा था। यानी टीएसएस समानांतर में जुड़े हुए थे। ओवर हेड डीसी ट्रैक्शन पावर सप्लाई सिस्टम अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था और सेक्शन में अधिक ट्रेनों को चलाना बहुत मुश्किल था। डीसी कर्षण प्रणाली के रख–रखाव की लागत भी बहुत अधिक थी। डीसी प्रणाली में बहुत अधिक समस्या के कारण फाल्ट बढ़ते गए।

25 केवी एसी प्रणाली यूरोप में, विशेष रूप से फ्रांसीसी रेलवे (एसएनसीएफ) पर अनुसंधान और परीक्षणों के परिणामस्वरूप विद्युतीकरण की एक किफायती प्रणाली के रूप में सामने आई। भारतीय रेल ने विद्युतीकरण के 25 केवी एसी प्रणाली को सन् 1957 में एक मानक के रूप में अपनाने का फैसला किया।

मौजूदा डीसी ट्रैक्शन सिस्टम की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, इसे 1996–97 में 25 केवी एसी कर्षण में बदलने का निर्णय लिया गया था। 12 नवम्बर, 2006 को इगतपुरी–कल्याण खंड का डीसी से एसी ट्रैक्शन में रूपांतरण और 24 अक्टूबर, 2010 को कल्याण– पुणे– लोनावाला खंड के रूपांतरण का काम पूरा हुआ। मध्य रेल के कल्याण–ठाणे खंड का डीसी से एसी ट्रैक्शन में रूपांतरण का काम 24 जनवरी, 2014 को और ठाणे–सीएसएमटी खंड का 8 जून, 2015 को पूरा हुआ। इसके साथ, मध्य रेल के संपूर्ण मेन लाइन रेल नेटवर्क में 25 केवी एसी ट्रैक्सन का उपयोग हो रहा है।

जमा पूंजी

1500 वी डीसी ट्रैक्शन से 25 केवी एसी ट्रैक्शन में स्विच करने के कारण, कल्याण–सीएसएमटी में ट्रैक्शन सब स्टेशन की संख्या 21 से घटकर 4 और सीएसएमटी–इगतपुरी / पुणे सेक्शन में 72 से 18 हो गई है। डीसी से एसी में रूपांतरण के कारण बिजली बिल में प्रति वर्ष लगभग रु 120 करोड़ की बचत होती है क्योंकि ट्रांसमिशन हानियाँ कम हो गई हैं, श्री फेज ईएमयू और इंजनों में रिजनरेटिव ब्रेकिंग शुरू की गई है। ■

खेल जगत्

43वीं अखिल भारतीय रेल महिला कबड्डी प्रतियोगिता में दक्षिण मध्य रेलवे विजयी

पूर्व मध्य रेल क्रीड़ा संघ द्वारा पटना में 24 से 27 सितम्बर तक 43वीं अखिल भारतीय रेल महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पूर्व मध्य रेल, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं उत्तर रेलवे सहित भारतीय रेल की कुल आठ क्षेत्रीय रेलों के 96 खिलाड़ियों एवं 28 तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया।



विजेता ट्राफी के साथ दक्षिण मध्य रेलवे महिला टीम

प्रतियोगिता का शुभारंभ 24 सितम्बर को पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक सह पूर्व मध्य रेल क्रीड़ा संघ के मुख्य संरक्षक श्री ललित चंद्र त्रिवेदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता के अंतिम चार टीमों में पूर्व मध्य रेल, दक्षिण मध्य रेल, पश्चिम रेलवे एवं उत्तर रेलवे शामिल रहीं, जिनके बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया। पहले सेमीफाइनल मैच में दक्षिण मध्य रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे को 20–16 से तथा दूसरे सेमीफाइनल मैच में पश्चिम रेलवे की टीम उत्तर रेलवे को 26–22 से पराजित करते हुए फाइनल में पहुंची। 27 सितम्बर को प्रतियोगिता का फाइनल मैच में दक्षिण मध्य रेलवे की टीम ने पश्चिम रेलवे को 30–24 से पराजित करते हुए 43वीं अखिल भारतीय रेल महिला कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। तीसरे और चौथे स्थान के लिए खेले गए मैच में उत्तर रेलवे ने पूर्व मध्य रेल को एक कड़े मुकाबले में 14–13 से पराजित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। दक्षिण मध्य रेलवे की सुश्री पूजा को प्रतियोगिता का 'सर्वश्रेष्ठ ऑलरांउडर' तथा सुश्री रीतु नेगी को प्रतियोगिता का 'सर्वश्रेष्ठ कैचर' घोषित किया गया। ■



पवित्र गंगा नदी पर आधारित वेस्टइंडीज के पर्यटक श्री जिम्मी शेख द्वारा हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर की गई वॉल पेंटिंग का दृश्य

स्टेशन

कोटद्वार रेलवे स्टेशन





उधना रेलवे स्टेशन





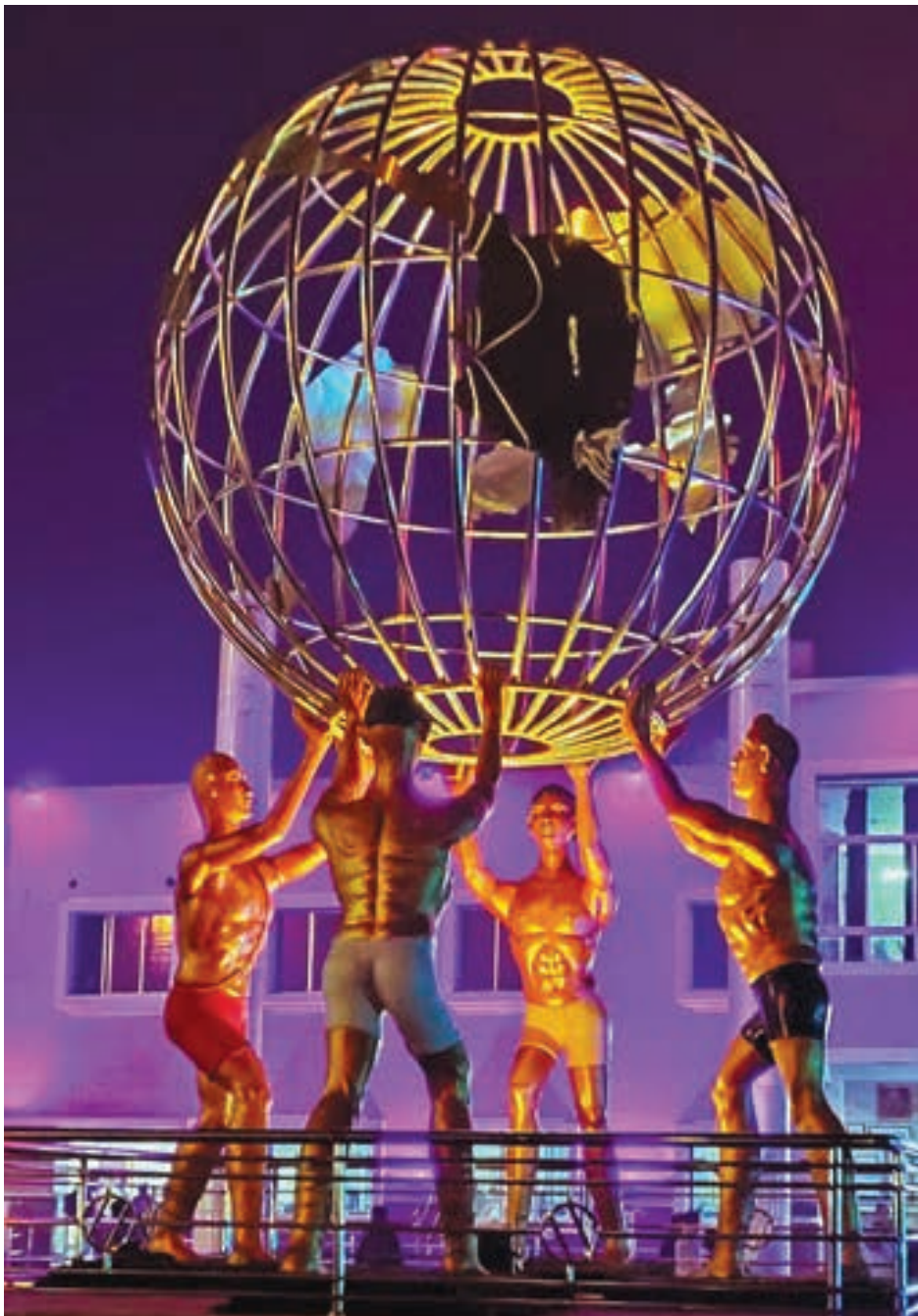
सौंदर्यीकरण

उधना रेलवे स्टेशन





दुर्गापुर रेलवे स्टेशन



सतर्कता से इस साल सौ से अधिक हाथियों की जान बची


रेल ट्रैक पार कर रहे हाथी

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कई निवारक उपाय से इस साल 140 से अधिक हाथियों की जान बची। गत वर्ष रेलवे कर्मियों की सतर्कता से 165 से अधिक जंगली हाथियों की जान बचाई गई।

यद्यपि 67 अधिसूचित हाथी गलियारे हैं, जो पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पांच मंडलों (कटिहार-1, अलीपुरद्वार-22, रंगिया-23, लामडिंग-16 और तिनसुकिया-5) के पांच संबंधित राज्यों के वन विभाग के साथ परामर्श से संयुक्त रूप से अधिसूचित किए गए। ऐसा पाया गया कि उन क्षेत्रों में हाथी प्राय: रेलवे ट्रैक पार कर जाते थे जो गलियारे के रूप में अधिसूचित नहीं थे। अधिसूचित क्षेत्रों में रेलवे चालकों को नियंत्रित गति में ट्रेन चलाने का निर्देश दिया गया है, जिससे ट्रेन की ठोकर से मरने वाले हाथियों की संख्या में काफी कमी आई, लेकिन बिना अधिसूचित वाले हाथी गलियारों में हाथियों के ट्रैक पर आ जाने पर चालकों के लिए ट्रेन को नियंत्रित करना काफी कठिन होता है।

अलीपुरद्वार मंडल और कुछ हद तक लामडिंग और रंगिया मंडल में हाथियों द्वारा रेलवे ट्रैक को पार करना काफी सामान्य बात है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, अलीपुरद्वार में वर्ष 2018 के दौरान 115 हाथियों को ट्रेन की गति पर नियंत्रण कर बचाया गया। यह नियंत्रण चालक द्वारा तब किया गया जब हाथी रेलवे ट्रैक के नजदीक थे या इसके ऊपर से गुजर रहे थे। 2017 में इस प्रकार के मामलों में अलीपुरद्वार मंडल में चालक द्वारा ट्रेन रोक कर 119 हाथियों की जान बचाई गई थी जबकि वर्ष 2016 और 2015 में क्रमश: 145 और 118 हाथियों की जान बचाई गई। उल्लेखनीय है कि 28 अक्टूबर, 2019 को ट्रेन नं. 75713 पैसेंजर के चालक ने जब अलीपुरद्वार मंडल के गुलमा और सिबोक स्टेशन के बीच ट्रैक के ऊपर हाथियों की गतिविधियों को देखा तब उन्होंने आपातकालीन ब्रेक लगाया, जिससे हाथियों की जान बची। मौजूदा वर्ष में आज तक चालकों द्वारा रेलवे ट्रैक पार करने के लिए ट्रेन रोकने की 122 घटनाएं हुईं।

मालूम हो कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने ट्रेन-हाथियों की टक्कर रोकने के लिए विभिन्न पहल शुरू की है, जिनमें इलिफेंट जोन में अत्यधिक गति का पता लगाने के लिए लेजर स्पीड राडार स्थापित करना शामिल है। सभी ट्रेन चालकों को सभी स्थाई और अस्थाई गति प्रतिबंधों को मानने की सलाह दी गई है। इसके लिए जोखिमवाले स्थानों के लेवल क्रॉसिंग गेटों में हनी बी साउंड का गुंजक लगाया गया है। रसोइयान के कर्मियों और यात्रियों को रेलवे ट्रैक के नजदीक खाद्य सामग्री/बचे हुए खाद्य पदार्थ नहीं फेंकने के लिए जागरुक किया जा रहा है ताकि उससे प्रलोभित होकर ट्रैक के पास हाथी या कोई अन्य जानवर न आ सकें। चालकों को पूर्व चेतावनी के लिए सभी चिन्हित हाथी गलियारों में साइनेज लगाए गए हैं। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ के पेड़-पौधों को हटाया गया है ताकि चालक आसानी से कोई चीज देख सकें। अलीपुरद्वार मंडल में तत्काल सूचना की अदला-बदली के लिए वन विभाग की फ्रीक्वेंसी के साथ 25 वॉट वीएचएफ लगाया गया है। ये उपकरण राजाभातखावा, कालचीनी और हासीमारा स्टेशनों में लगाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न जोखिम वाले स्थानों पर रैंप, मार्ग, सुरंग, ऊपरी मार्ग और घेरों का निर्माण किया गया है और किया जा रहा है ताकि हाथियों को मरने से बचाया जा सके। रेलवे द्वारा की गई इस पहल से ट्रेन और हाथियों की टक्कर कम हो रही है। ■





पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आजारा और कामाख्या स्टेशन के बीच हाथियों को बचाने के लिए लेवल क्रॉसिंग गेट एनएन-274 पर स्थापित पहला हनी 'बी' ध्वनि प्रवर्धित उपकरण



डीजल रेल इंजन कारखाना विशेषांक



डीजल रेल इंजन कारखाना : कल, आज और कल



रहिम गोयल
महाप्रबंधक

1950 के दशक में वाष्प रेल इंजनों की तुलना में डीजल विद्युत रेल इंजनों की विविधता, बेहतर हॉलिंग क्षमता, अल्प अनुरक्षण आवश्यकता और समग्र लागत का लाभ लेने के लिए डीजल विद्युत रेल इंजनों को भारतीय रेल में प्रयुक्त किया गया। भारतीय रेल परिवहन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करना भी आवश्यक था।

परिणामस्वरूप, प्राचीन शहर वाराणसी में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा 23 अप्रैल, 1956 को 'डीजल कलपुर्जा कारखाना' का शिलान्यास किया गया। अगस्त, 1961 में 'डीजल कलपुर्जा कारखाना' को मैसर्स अल्को, अमेरिका के सहयोग से 'डीजल रेल इंजन कारखाना (डीरेका)' के रूप में पहचान मिली। डीरेका निर्मित प्रथम बड़ी लाइन रेल इंजन 'डब्ल्यूडीएम-2' को 3 जनवरी, 1964 को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ाया।

अपनी शुरुआत से ही डीरेका नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात् करने में अग्रणी रहा है। वर्तमान में डीरेका को विश्व के अग्रणी डीजल एवं विद्युत रेल इंजन निर्माताओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में भारतीय रेल के सम्पूर्ण विद्युतीकरण के लक्ष्य के अनुरूप डीरेका ने विद्युत रेल इंजन के निर्माण के लिए अपने को तैयार किया है। फरवरी, 2017 में उत्पादित प्रथम विद्युत रेल इंजन से लेकर अक्टूबर, 2019 तक मात्र 2 वर्ष 7 माह की अल्पावधि में ही डीरेका ने कुल 319 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण कर अपनी असीम क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त डीरेका ने विश्व में प्रथम बार 2,600 अश्व शक्ति के दो डीजल रेल इंजनों को युग्मित कर 10,000 अश्व शक्ति के विद्युत ट्रैक्शन रेल इंजन में बदलकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस रेल इंजन को 19 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो कि डीरेका के लिए गर्व का विषय है। विगत 10 वर्षों में डीरेका में रेल इंजनों का उत्पादन दोगुने से अधिक हो गया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रेल प्रणालियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे मल्टी-गेज के रेल इंजन बनाने में सक्षम डीरेका ने एशिया और अफ्रीका में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। डीरेका के द्वारा निर्मित रेल इंजन बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, तंजानिया, सूडान, सेनेगल, माली, मलेशिया, वियतनाम, अंगोला और मोजाम्बिक में दौड़ रहे हैं। अपने देश में भारतीय रेल के लिए मोटिव पावर प्रदाता होने के साथ-साथ डीरेका विभिन्न स्टील प्लांटों, पावर प्लांटों और पोर्ट ट्रस्टों को भी रेल इंजनों की आपूर्ति कर रहा है। इसी प्रकार अपनी स्थापना से अब तक अपने स्वर्णिम 55 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाते हुए डीरेका ने विभिन्न श्रेणियों के कुल 8,600 रेल इंजनों का उत्पादन कर राष्ट्र निर्माण में अपना अतुलनीय योगदान दिया है।



रेल इंजनों के अलावा डीरेका हाई-टेक माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित दोष निदान प्रणाली के साथ 2.4 मेगावॉट क्षमता के डीजल जेनसेट का डिजाइन एवं निर्माण भी कर रहा है। अब तक डीरेका ने 62 उच्च क्षमता वाले डीजल जेनसेट का निर्माण किया है।

पर्यावरणीय संरक्षण में सदैव अग्रणी डीरेका ने 1980 के दशक से पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिका का निर्वाह करते हुए मानव जनित मल-मूत्र के शोधन के लिए मल-जल शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) और मिश्रित





पेट्रोलियम ऑयल एवं लुब्रिकेंट (पी.ओ.एल.) के लिए औद्योगिक निस्राव शोधन संयंत्र (आई.ई.टी.पी.) की स्थापना की है। उक्त संयंत्रों ने 'गंगा निर्मलीकरण योजना' में सहयोग करने के साथ ही संसाधनों की रिसाइक्लिंग में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। एस.टी.पी. में प्रतिदिन लगभग 3.46 मिलियन लीटर जल का शोधन किया जाता है और किसी भी प्रकार का शोधित या अशोधित जल गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किया जाता है। शोधित जल को कृषि कार्यों एवं बागवानी के उपयोग में लाया जाता है। एस.टी.पी. और आई.ई.टी.पी. के मानकों की ऑनलाइन निगरानी की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए मानकों के अनुरूप रहें। डीरेका को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 प्रमाणन प्राप्त है। इस प्रमाणन के फलस्वरूप डीरेका को कारखाना एवं उपनगर, दोनों स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण हेतु सुपरिभाषित एवं लिखित नीति तैयार करने में मदद मिली है।

डीरेका में प्रतिवर्ष 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए 'विश्वकर्मा पूजा' मनाई जाती है। पूजा के उपरांत भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाओं को पवित्र नदी गंगा में विसर्जित किया जाता था। डीरेका के कर्मचारियों द्वारा जल प्रदूषण के प्रति अपनी संवेदना के दृष्टिगत अग्रणी भूमिका निभाते हुए प्रतिमाओं की जगह भगवान विश्वकर्मा के चित्रों की पूजा शुरू की गई। भूमिगत जल को रिचार्ज करने हेतु 425 सोकपिट और 47 डीप रिचार्ज वेल के निर्माण के साथ वॉटर हॉर्वेस्टिंग के लिए डीरेका प्रतिबद्ध है।

डीरेका ने 3.859 मेगावॉट शक्ति के सोलर पावर पैनल लगाए हैं। इससे प्रतिमाह लगभग 3.5 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। डीरेका कर्मियों के आवासों में एवं सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट्स लगाने का भी कार्य किया गया है, जिससे ऊर्जा खपत में कमी आई है।

डीरेका द्वारा ओपेन एक्सेस के तहत सामान्य विद्युतीय सेवाओं हेतु 132 किलोवॉट पर विद्युत सप्लाई प्राप्त की जा रही है। यह व्यवस्था 15 मई, 2019 से लागू की गई है। डीरेका द्वारा ओपेन एक्सेस के तहत विद्युत उर्जा की खरीद करने के कारण प्रति माह लगभग 47 लाख रुपये की बचत हो रही है। ऐसा करने वाला डीरेका भारतीय रेल की दूसरी उत्पादन इकाई है।

पंप ऑटोमेशन सहित मोटराइज्ड गेट वॉल्व का प्रयोग, डीरेका द्वारा ऊर्जा की खपत में कमी लाने की दिशा में दूसरा कदम है। इस प्रणाली में सुधार से न केवल बहुमूल्य जल की बचत हुई, बल्कि पम्पिंग के समय में भी दो घंटे की कमी आई है। वर्तमान में डीरेका परिसर में 1,50,000 से अधिक छोटे एवं बड़े वृक्ष हैं, जिससे डीरेका में लगभग 40% क्षेत्र हरा-भरा दृष्टिगोचर होता है। सम्पूर्ण परिसर में प्रतिवर्ष हजारों वृक्षों का रोपण किया जाता है। 'स्वच्छ डीरेका, हरित डीरेका' हेतु 'टीम डीरेका' के तत्संबंधी प्रयासों के फलस्वरूप यहाँ का वातावरण चहुंओर न केवल हरा-भरा है, बल्कि जल, वायु, उत्सर्जन एवं हानिकारक कचरे का प्रदूषण स्तर भी सीमा के अंदर है। डीरेका का हरा-भरा परिसर स्वयं ही इस उपनगर के निवासियों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता एवं प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डीरेका परिसर में प्रवेश करते ही तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट स्पष्टतया महसूस होती है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से सम्पूर्ण डीरेका परिसर की 95 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है, जिसमें 8 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे शामिल हैं। केन्द्रीय अस्पताल की भी 34 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा





रही है। प्रशासन भवन में फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के तहत ऑटोमैटिक डिटेक्शन एंड फायर अलार्म सिस्टम व एक्स-रे बैगेज स्कैनर लगाया गया है। डीरेका में पहली बार एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, जिसे एनडीआरएफ द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में एनडीआरएफ की टीम द्वारा डीरेका के साथ मेगा मॉक ड्रिल 'सक्षम' का आयोजन किया गया, जो बहुत सफल रहा।

डीरेका ऐसी पहली उत्पादन इकाई है, जहाँ ऊर्जा खपत एवं अनुकूल ऊर्जा प्रयोग की निगरानी के लिए स्काडा (एस.सी.ए.डी.ए.) प्रणाली को सामान्य सेवाओं के रूप में स्थापित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि डीरेका को तीनों महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्ता प्रमाणपत्र), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण संरक्षण प्रमाणपत्र) तथा ओहसास 18001:2007 (स्वास्थ्य एवं संरक्षा प्रमाणपत्र) के नवीनतम संस्करण प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त डीरेका को उत्कृष्ट ऊर्जा प्रबंधन हेतु आईएसओ 50001:2011 प्रमाणपत्र, वेल्डिंग तकनीकी का विश्वस्तरीय प्रमाणन आईएसओ 3834-2:2005 प्रमाणपत्र, मैसर्स सीआईआई - गोडरेज जीबीसी द्वारा सर्वे के अंतर्गत 'ग्रीनको सिल्वर' (GreenCo Silver) का दर्जा एवं कार्यशाला स्थित प्रयोगशाला को एनएबीएल द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। साथ ही, सुसज्जित रख-रखाव एवं उत्तम हाउसकीपिंग हेतु '5S' प्रमाणपत्र भी डीरेका को जारी किया गया है। डीरेका को इस बात का गर्व है कि रेलवे बोर्ड द्वारा डीरेका को लगातार तीसरे वर्ष 'सर्वोत्तम उत्पादन इकाई शील्ड 2017-18' प्रदान की गई। इससे डीरेका टीम की निष्ठा, कार्य के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता का प्रदर्शन होता है।

प्रतिक्षण मील का नया पत्थर प्राप्त करने के लिए डीरेका के अत्यधिक समर्पित एवं प्रेरित कार्यबल से युक्त लगभग 6,200 कर्मचारियों को सारा श्रेय देना अतिशयोक्ति नहीं होगा। डीरेका ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए पर्यावरण अनुकूल, अत्याधुनिक हरे-भरे उपनगर के परिक्षेत्र में 3,675 आवासीय सुविधा प्रदान कर रखी है। इसके अतिरिक्त डीरेका स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्कूली शिक्षा और खेलकूद के संबंध में अपने कर्मियों एवं उनके परिजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्कृष्ट नागरिक सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है।



रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से सर्वोत्तम उत्पादन इकाई शील्ड प्राप्त करते हुए

वर्तमान में डीरेका परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अतीत के शानदार स्वर्णिम अध्याय का अनुकरण करते हुए डीरेका ने अनेकानेक कीर्तिमान स्थापित कर न केवल भारतीय रेल को गौरवान्वित किया है, अपितु विश्व मानचित्र में भी भारत का नाम रौशन करने में अहम योगदान दिया है। आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हमें और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आत्मविश्वास से ओतप्रोत हमारी टीम सतत् कुशलता के साथ आनेवाली हर चुनौतियों को अवसरों में परिणत कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। ■

आज का डीरेका : डीजल से विद्युत रेल इंजन की ओर



श्री अनिल कुमार सिंघल
प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर

भारतीय रेल की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर डीरेका ने खुद को नई तकनीकों से सुसज्जित किया। इसी क्रम में डीरेका ने 1990 के दशक में अल्को से ईएमडी (हाई हॉर्स पावर) लोको उत्पादन शुरू किया। वर्तमान में विद्युत लोको (डब्ल्यूएपी7 एवं डब्ल्यूएजी9) उत्पादन का बीड़ा उठाया है।

वर्ष 2016 में रेलवे बोर्ड द्वारा कार्बन फुट प्रिंट कम करने का निर्णय लिया गया एवं डीरेका को पहली बार वर्ष 2016-17 में 2 विद्युत लोको उत्पादित करने का लक्ष्य दिया गया।

तत्कालीन रेल राज्यमंत्री ने डीरेका निर्मित प्रथम विद्युत लोको 'वरुण' को 14 फरवरी, 2017 को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। तत्पश्चात् रेलवे बोर्ड ने डीरेका की क्षमताओं को देखते हुए और अधिक विद्युत लोको बनाने का लक्ष्य दिया जिसके अनुपालन में डीरेका ने वर्ष 2017-18 में 25 एवं 2018-19 में 145 विद्युत लोको का निर्माण किया। तत्कालीन सदस्य कर्षण रेलवे बोर्ड श्री घनश्याम सिंह ने डीरेका निर्मित 100वें विद्युत लोको को 7 फरवरी, 2019 को राष्ट्र के नाम समर्पित किया।

विगत 3 वर्षों का लोको उत्पादन तथा अगले 3 वर्षों के उत्पादन लक्ष्य का विवरण निम्न है:

वित्त वर्ष	लक्ष्य		उत्पादन	
	डीजल लोको	विद्युत लोको	डीजल लोको	विद्युत लोको
2016-17	320	2	332	2
2017-18	290	25	296	25
2018-19	122	173	129	145
2019-20	34	303	13 (जुलाई तक)	92 (जुलाई तक)
2020-21	30	300	-	-
2021-22	30	250	-	-

* इसके अलावा 2017-18 में 02 डब्ल्यूएजी-10 लोको एवं 2018-19 में 2 डब्ल्यूएजी-11 लोको निर्मित किए गए।

डीरेका के उत्पाद में यह बदलाव एक ऐतिहासिक कदम था। इसको पाने के लिए यहां पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समय-समय पर ट्रेनिंग दी गई एवं कुल लगभग 40 अधिकारियों, 100 पर्यवेक्षकों एवं 400 तकनीशियनों को विद्युत लोको उत्पादन की तकनीक से अवगत कराया गया। इसके अलावा डीरेका में विद्युत लोको के निर्माण हेतु मैटीरियल प्रोक्यूरमेंट 2018-19 से शुरू किया गया, निर्माण हेतु अन्य आवश्यक संसाधन, जैसे हॉर्स, लैड्डर-टैक्लस, लोको को उठाने हेतु सिंक्रोनाइज्ड जैक, ट्रांसफॉर्मर मॉउंटिंग हेतु हाइड्रॉलिक सिस्टम, डमी बोगी इत्यादि का भी निर्माण किया गया। उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उक्त संसाधनों के अलावा टेस्टिंग हेतु विभिन्न संसाधन जैसे लूप एवं लॉजिक बॉक्स टेस्टिंग अरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मर ऑयल सेंट्रीफ्यूजिंग अरेंजमेंट, बैटरी रीचार्जिंग अरेंजमेंट और ट्रैक्टर मोटर रन टेस्ट अरेंजमेंट की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई। अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली एवं मेहनती टीम की वजह से वर्तमान में डीरेका विद्युत रेल इंजनों के निर्माण में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है। जुलाई, 2019 तक कुल 244 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण कर राष्ट्र के नाम समर्पित किया जा चुका है।

विद्युत सामान्य सेवाएं एवं अनुरक्षण विभाग

विद्युत सामान्य सेवाएं एवं अनुरक्षण विभाग, डीरेका कॉलोनी परिसर सहित कारखाना परिक्षेत्र में विद्युत सप्लाई निर्बाध उपलब्ध करता है। डीरेका में ओपेन एक्सेस के तहत 132 केवी पर विद्युत सप्लाई प्राप्त की जा रही है। डीरेका में एक अदद् 132 केवी, 2 अदद् 33/11 केवी एवं 26 अदद् 11/0.415 केवी विद्युत उपकेंद्र सहित कुल 29 अदद् विद्युत उपकेंद्र स्थापित हैं। डीरेका के सभी विद्युत उपकेंद्र का रिमोट परिचालन स्काडा द्वारा हो रहा है। इसके अतिरिक्त डीरेका की सम्पूर्ण दूरसंचार व्यवस्था भी विद्युत अनुरक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

ऊर्जा प्रबंधक प्रणाली

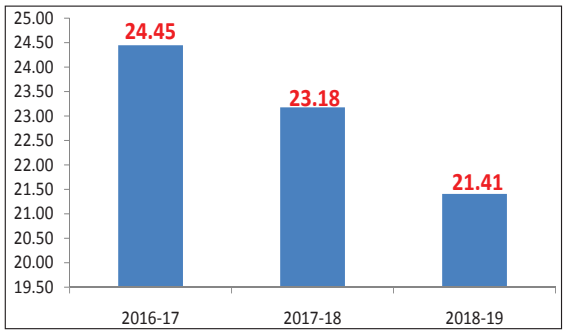
स्काडा - ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भारतीय रेल में विद्युत सामान्य सेवाओं के अनुरक्षण एवं निगरानी के लिए अत्यंत उपयोगी है। डीरेका में स्थापित इस सिस्टम द्वारा सभी विद्युत उपकेंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं रिमोट परिचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा के आंकड़ों का विश्लेषण और तद्नुसार ओपेन एक्सेस हेतु ऊर्जा डिमांड की आवश्यकता का निर्धारण हो रहा है। स्काडा द्वारा स्ट्रीट लाइटों, कारखाने की हाई-बे लाइटों एवं जलापूर्ति प्रणाली की भी परिचालन व मॉनिटरिंग का जा रही है।



ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण के तहत डीरेका में विगत वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कराए गए हैं:

- आवासीय एवं सर्विस भवनों में पारम्परिक लाइट फिटिंग्स (टी-5, टी-8, टी-12) को एलईडी लाइट फिटिंग से बदला गया है। इसके अतिरिक्त सभी सीएफएल फिटिंग को भी एलईडी लाइट फिटिंग से बदला गया है।
- सभी पारम्परिक स्ट्रीट लाईट फिटिंग्स को एलईडी लाइट फिटिंग से बदला गया है।
- कारखाना परिक्षेत्र में स्थापित सभी मेटल हैलाईड फिटिंग को एलईडी हाई बे फिटिंग्स से बदला गया है।
- एस.टी.पी., आई.ई.टी.पी. एवं जलापूर्ति प्रणाली में स्थापित उच्च ऊर्जा खपत के पम्पों को ऊर्जा दक्ष पम्पों से बदला गया है।
- डीरेका परिसर की स्ट्रीट लाइटों एवं कारखाना परिक्षेत्र की हाई-बे लाइटों का ऑटोमेशन किया गया है, जिसके तहत समय एवं प्रकाश की आवश्यकता के अनुरुप उनका संचालन स्काडा से किया जाता है।



विगत वर्षों में ऊर्जा खपत में हुई बचत

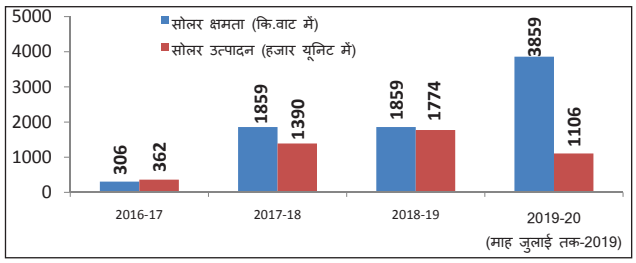
इन प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में ग्रिड ऊर्जा खपत में 8 प्रतिशत की कमी हुई है।

हरित ऊर्जा

डीरेका में रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ हुआ था। अब तक डीरेका के विभिन्न सर्विस भवनों, वर्कशॉप के शेडों पर 3,859 केडब्ल्यूपी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त ऊर्जा संयंत्रों में से 1,859 केडब्ल्यूपी टर्नकी आधार पर तथा 2000 केडब्ल्यूपी, पीपीपी मॉडल पर स्थापित हुए हैं। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों से प्रति माह औसत 3.75 लाख यूनिट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। 2018-19 में डीरेका की सम्पूर्ण विद्युत ऊर्जा खपत में सौर ऊर्जा का उत्पादन 8 प्रतिशत रहा है। 2019-20 में अनुमानित सौर ऊर्जा उत्पादन 35 लाख यूनिट होगा जोकि सम्पूर्ण विद्युत ऊर्जा खपत का 17 प्रतिशत होगा।



क्र.सं.	सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता (केडब्ल्यूपी)	स्थान का नाम
1	950	कॉलोनी
2	472	प्रशासन भवन
3	2437	कारखाना



विगत वर्षों में स्थापित सोलर क्षमता एवं सोलर उत्पादन

ओपेन एक्सेस के तहत विद्युत ऊर्जा की खरीद

डीरेका सामान्य विद्युतीय सेवाओं हेतु ओपेन एक्सेस के तहत विद्युत ऊर्जा की खरीद करने वाली रेल पहिया कारखाना, बेंगलुरु के बाद द्वितीय रेल उत्पादन ईकाई है। डीरेका 15 मई, 2019 से ओपेन एक्सेस के तहत विद्युत ऊर्जा की खरीद कर रहा है। ओपेन एक्सेस के तहत विद्युत ऊर्जा की खरीद करने से डीरेका को लगभग 47 लाख प्रति माह (@ 5.25 प्रति यूनिट) विद्युत प्रभार की बचत हो रही है।

सुरक्षा



स्वचालित नम्बर प्लेट रिकार्डर कैमरा

डीरेका प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील परिक्षेत्र है। डीरेका परिसर में आयोजित होने वाले विशिष्ट/अतिविशिष्ट आयोजनों की सुरक्षा के मद्देनजर विद्युत विभाग द्वारा डीरेका कॉलोनी व कारखाना परिसर के विभिन्न महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों पर कुल 100 सीसीटीवी कैमरों की स्थापना कराई गई है। इन कैमरों में से 8 स्वचालित नम्बर प्लेट रिकॉर्डर कैमरे (ऑटोमैटिक नंबर प्लैट रिकॉर्डर-एनपीआर) हैं जो डीरेका के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर स्थापित हैं, जिनके द्वारा डीरेका परिसर में आने व जाने वाले वाहनों के नम्बर प्लेट रिकार्ड किए जाते हैं। उक्त स्थापित सीसीटीवी कैमरों द्वारा सम्पूर्ण डीरेका परिसर की निगरानी केंद्रीयकृत कंट्रोल रूम से की जाती है। स्वचलित नम्बर प्लेट रिकॉर्डर कैमरे प्रकार के कैमरों से युक्त डीरेका प्रथम रेल उत्पादन ईकाई है।

स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली

सभी मैनुअल ऑपरेटेड जलापूर्ति गेट वॉल्वों को ऑटोमैटिक गेट वॉल्व से बदला गया है। ये मोटराइज्ड गेट वॉल्व निर्धारित समय के लिए खुलते हैं जिसे सॉफ्टवेयर कंट्रोल द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सम्पूर्ण जलापूर्ति प्रणाली की निगरानी स्काडा द्वारा की जाती है जो जल की खपत, ऊर्जा का विश्लेषण एवं ब्रेकडाउन के समय त्वरित कार्रवाई में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है।



मोटराइज्ड गेट वॉल्व कंट्रोल पैनल

दूरसंचार एवं इंटरनेट प्रणाली

दूरसंचार प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है जिसके अंतर्गत टेलीफोन एक्सचेंज का नवीनीकरण कराया गया है।

समय की मांग के अनुसार इंटरनेट सुविधाओं को अपग्रेड करते हुए उनका विस्तारीकरण किया गया है। निर्बाध कनेक्टीविटी के लिए सम्पूर्ण डीरेका परिसर में ओएफसी का नेट वर्क बिछाया गया है। रेलनेट की सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है जिसके अंतर्गत नए सर्वर सिस्टम की स्थापना के साथ-साथ डेटा की सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना कर उसे सर्वर से इंटीग्रेट किया गया है। ■

डीरेका में सामग्री प्रबंधन



श्री डी.एस. जंगपांगी
प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक

सामग्री प्रबंधन सभी व्यक्तियों, संगठनों, संसाधनों, क्रियाकलापों और प्रौद्योगिकियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें विभिन्न उपभोक्ताओं के खयालों और आकांक्षाओं को धरातल पर उतारकर उन्हें आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराने हेतु तथा उसके उपयोग के उपरांत उनके द्वारा चाही गई सामग्री के अप्रासंगिक होने पर उसके अंतिम निस्तारण संबंधी सभी क्रियाकलापों को करना शामिल है। सामग्री प्रबंधन नियोजन, संचालन, संप्रेषण, निदेशन और नियंत्रण के उन सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन है, जो मुख्य रूप से सामग्री के संगठन में प्रवाह से संबंधित है और इसे आगे उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। सामग्री प्रबंधन की भूमिका की महत्ता संगठन द्वारा की जा रही खरीद की मात्रा के सीधे अनुपात में बढ़ती है। इसीलिए डीजल रेल इंजन कारखाना में सामग्री प्रबंधन एक बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डीरेका अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और दक्षता बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। भंडार विभाग अपनी सभी प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण करके इन दोनों दिशाओं में, डीरेका में, सबसे अग्रणी है। डीरेका के भंडार विभाग की वर्तमान डिजिटल यात्रा, जिसमें सामग्री प्रबंधन से संबंधित सभी भागीदार एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, वर्ष 2009-10 में सामग्री खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करने जैसे सीमित, परंतु अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र से शुरू हुई और अब यह यात्रा एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है जिसमें सभी तरह की निविदाएं यथा विज्ञापित, विश्वजनीन, एकल, सीमित निविदाओं के द्वारा खरीददारी और बेकार सामान की बिक्री एक ही पोर्टल www.ireps.gov.in की जाती है। खरीददारी एवं बिक्री से संबंधित सभी निर्णय भी इसी वेब पोर्टल पर लिए जाते हैं। इस समूची खरीद प्रक्रिया यानी कि निविदा आमंत्रण से पूर्व की प्रक्रिया, निविदा आमंत्रण, निविदा पर निर्णय, क्रयादेश, सामग्रियों की प्राप्ति, भंडारण और निर्गम तथा रद्दी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया भी इसी पोर्टल पर की जा रही है, जिसके लिए सूचना तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया है।

विशेष कार्य / मुख्य आकर्षण : वित्त वर्ष 2019-20 में माह अक्टूबर तक डीरेका द्वारा 173 लोकोमोटिव बनाए जा चुके हैं जिसमें 137 डब्ल्यूएपी-7, 10 डब्ल्यूएजी-9 तथा 26 डीजल लोकोमोटिव हैं। गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 274+02 (कॉनवर्सन) लोकोमोटिव बनाए गए जिसमें 103 एचएचपी (डब्ल्यूडीजी4/डब्ल्यूडीपी4डी), 145 विद्युत तथा 26 निर्यात/गैर रेलवे ग्राहक लोकोमोटिव सम्मिलित हैं। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए भण्डार विभाग में लगभग 7,400 करोड़ रुपये मूल्य (प्राप्ति एवं इशू को लेकर) के सामग्री का आदान-प्रदान किया गया। इतनी अधिक सामग्री के आदान-प्रदान के बाद भी वर्ष के अन्त में फिजिकल क्लोजिंग बैलेंस केवल 517.04 करोड़ रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप डीरेका ने विगत वर्ष 2017-18 के टीओआर-4.03% की तुलना में 1.28% प्राप्त किया।

डीजल रेल इंजन कारखाना में डीजल लोको का विनिर्माण बंद करके शत-प्रतिशत विद्युत लोको का विनिर्माण शुरू किया जा चुका है जो कि भंडार विभाग के अथक प्रयासों द्वारा अत्यंत कम समय में सभी आवश्यक उपकरण तथा कच्चा माल उपलब्ध करवा पाने के कारण ही संभव हो पाया है।

कार्य क्षेत्र : भण्डार विभाग, विद्युत, एच.एच.पी. और एन.आर.सी. रेल इंजनों के उत्पादन एवं सामानों के रख-रखाव तथा विभिन्न मदों, जैसे - लोको स्पेयर्स, कच्चे माल, उपभोज्य एवं सामान्य वस्तुओं की खरीद एवं केन्द्रीयकृत रूप से मांगे गए मदों को विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को रोलिंग स्टॉक के अनुरक्षण हेतु आपूर्ति करने में मुख्य भूमिका है। इन कार्यों के लिए वाराणसी में क्रय कार्यालय के साथ एक मुख्य भण्डार डिपो है तथा एक छोटा ट्रांजिट डिपो सियालदह में भी है।

संगठनात्मक ढांचा

मुख्यालय : प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक के निर्देशन में वाराणसी स्थित मुख्यालय रेल इंजनों के उत्पादन के लिए उपकरणों/कच्चे माल की खरीद तथा, क्षेत्रीय रेलों एवं गैर रेलवे ग्राहकों की अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त पुर्जों की खरीद का कार्य करता है।



एएसआरएस बिन में रखने के लिए प्रतिक्षारत पैलेट का दृश्य



स्टैकर द्वारा स्टोरेज बिन में सामग्री रखने का दृश्य

भण्डार डिपो : उप मु.सा.प्र. के नियंत्रण में कार्यरत भण्डार डिपो डीरेका परिसर के अन्दर स्थित है, जो सामग्री की प्राप्ति, भण्डारण एवं शॉप्स को उत्पादन के लिए सामान जारी करने के साथ-साथ रेलों और गैर रेल ग्राहकों के लिए अतिरिक्त पुर्जो के वितरण एवं रद्दी मालों के निस्तारण का कार्य देखता है।

वर्तमान में भण्डार डिपो में लगभग 6,524 मदों का भण्डारण किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक लोको, उच्च अश्व शक्ति (एचएचपी) लोको, डी.जी. सेट तथा एल्को लोको के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। इस कार्य हेतु डिपो में कुल 14 प्राप्ति एवं 27 भण्डारण वार्ड के साथ अस्वीकृत, वारंटी, एम एस, सेंट्रल डिस्पैच, एनआरसी एवं स्कैप वार्ड हैं।

भंडार डिपो में सामग्री के भंडारण हेतु एएसआरएस के रूप में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया गया है। इस अत्याधुनिक तकनीकी युक्त कम्प्यूटर नियंत्रित स्वचालित भंडारण एवं निर्गमन (ए.एस.आर.एस.) की कुल भंडारण क्षमता 1436 घन मीटर है तथा इसमें 3,024 पैलेट एवं लगभग 1,000 मदों के भंडारण की व्यवस्था है, इसमें वर्टीकल स्थान का समुचित उपयोग, कम श्रम की आवश्यकता, मद निर्गम में न्यूनतम गलती की संभावना एवं समय की बचत होती है।

कोलकाता संगठन : कोलकाता में कार्यरत यह छोटी इकाई कोलकाता समुद्री पत्तन और हवाई पत्तन पर आयातित सामानों का निपटारा करने के लिए पूर्व रेलवे से सम्पर्क में रहती है। साथ ही, एक छोटा ट्रांजिट डिपो सियालदह (कोलकाता) में है, जहाँ विदेशों से आयातित सामग्रियों का अस्थाई भण्डारण किया जाता है।

माल सूची निष्पादन

टर्न ओवर अनुपात : वर्ष 2014-15 एवं आगे के भण्डार शेष, निर्गत एवं टर्न ओवर अनुपात वित्त नियंत्रण आंकड़ा के अनुसार सांख्यकीय आंकड़ों में नीचे दिया गया है :-

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के अन्तर में भण्डार शेष	वर्ष के दौरान निर्गमिक सामग्रियों का मूल्य	टर्न ओवर अनुपात
2014-15	378.66	3681.25	10.29%
2015-16	215.73	4842.93	04.45%
2016-17	-119.11	4460.34	-02.67%
2017-18	-158.14	3922.55	-04.03%
2018-19	-44.05	3429.40	-01.28%

लेखा बही के अनुसार खरीदे गए स्वदेशी बनाम आयातित सामानों का मूल्य

भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पॉलिसी के तहत, डीरेका एवं भारतीय फर्मो से आयात की जाने वाली सामग्री का कुल मूल्य एवं प्रतिशत घटता जा रहा है जो कि निम्नलिखित टेबल में दिया गया है :-

(आंकड़े हजार रुपये में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स्वदेशी सामग्रियाँ	2559,72,95	2826,45,82	3022,11,90	3088,58,78	2982,09,91
सीमा शुल्क के साथ आयातित सामग्रियाँ	940,57,00	1395,77,45	781,00,70	389,79,54	277,65,28
स्वदेशी तथा आयातित	3500,29,95	4222,23,27	3803,12,60	3478,38,32	3259,75,19
मद सं.-03 के संदर्भ में मद सं. 01 का प्रतिशत	73.12%	66.94%	79.46%	88.79%	91.48%

क्रय निष्पादन (2018-19)

दिए गए क्रयादेशों एवं खरीद की गई मदों की सं.	
(क) दिए गए क्रयादेशों की सं.	5423
(ख) विज्ञापित निविदा की सं.	2178
(ग) विश्व जनीन निविदा सं.	360
(घ) बुलेटिन निविदा सं.	Nil
(ड़) सीमित निविदा सं.	3024
सरकारी उपक्रमों से किए क्रय का मूल्य	594.17 करोड़
कुटीर एवं लघु उद्योगों से किए क्रय का मूल्य	1319.79 करोड़
खादी सामग्री का क्रय मूल्य	0.65 करोड़
5.2+5.3+5.4 का कुल मूल्य	1914.61 करोड़
स्वदेशी खरीद	2982.10 करोड़
आयातित खरीद	277.65 करोड़
कुल (स्वदेशी+आयातित) खरीद	3259.75 करोड़

रद्दी माल का निपटारा आंकड़े (लाख रुपयों में)

वर्ष	लौह	अलौह	विविध	योग
2014-15	586.683	47.457	167.557	801.697
2015-16	462.177	119.980	215.852	795.009
2016-17	421.253	74.453	123.926	619.632
2017-18	567.148	55.591	107.510	730.249
2018-19	723.729	46.508	279.90	1,050.137

क्षेत्रीय रेलों को अतिरिक्त पुर्जो की आपूर्ति : डीरेका लोकोमोटिव के क्रिटीकल मद को खरीदकर या बनाकर सभी रेलवे को उसकी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति करता है। विगत पाँच वर्षों के दौरान रेलवे को आपूर्ति किए गए अतिरिक्त पुर्जो का मूल्य निम्नलिखित है:-

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वर्ष	योग
2014-15	148.23
2015-16	360.90
2016-17	350.59
2017-18	238.92
2018-19	317.69

कम्प्यूटरीकरण : क्रय कार्यालय एवं डिपो से संबंधित अधिकतम कार्य कम्प्यूटरीकृत है और आंकड़े ऑन लाइन उपलब्ध हैं। इस उद्देश्य के लिए क्रय कार्यालय एवं डिपो में लोकल एरिया नेटवर्क अलग से स्थापित है। ये ई.डी.पी. सेंटर से जुड़े हैं और बिल पास करने के लिए इसे लेखा कार्यालय और अन्य विभाग तक बढ़ाया गया है।

एमएमआईएस प्रणाली के तहत निविदा एवं क्रय

इस प्रणाली के अन्तर्गत माँगों का पंजीकरण से शुरू कर के निविदा जारी करना, टेबुलेशन विवरण तैयार करना, क्रय आदेश भेजना, पीओ संशोधन और उसको ऑडिट करना आदि क्रय से संबंधित विभिन्न क्रिया-कलाप, शामिल हैं। दक्षतापूर्ण निर्णय के लिए, ऑनलाइन पूछताछ का उत्तर प्रणाली में दिया

जाता है। यह प्रणाली सामग्री प्रबंधन सुचना प्रणाली के एमएल जेनरेशन माड्यूल के साथ एकीकृत है जो स्वत: क्रय प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाती है। इसमें डिपो की ऑनलाईन प्राप्ति और जारी के ई-आंकड़े भी उद्यतन हो जाते हैं।

भण्डार प्राप्ति प्रबन्ध : सामग्री प्रणाली का पूरा विवरण ऑनलाईन है। इसमें दस्तावेज चालान की प्राप्ति और प्रेषण प्रक्रिया और भण्डार की प्राप्ति शामिल करते हुए, निरीक्षण रपट, प्राप्ति नोट एवं अस्वीकृति सूचना का मुद्रण इत्यादि सभी का विवरण है। यह प्रणाली क्रय प्रणाली से जुड़ी हुई है एवं इसमें निष्क्रिय सरप्लस तथा अधिभण्डारण मदों इत्यादि के मामले में सावधान करने के लिए चेतावनी प्रणाली (वार्निंग सिस्टम) है, जो विशेष तौर पर माल सूची नियंत्रण को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में सहायक है।

भण्डार लेन-देन प्रबन्धन : स्टाकिंग वार्डों के सभी लेन-देन ऑनलाइन से जुड़े हैं। वार्डों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने से सभी लेन-देन ऑनलाइन हो गए हैं। इससे लेन-देन का हिसाब रखने के समय में कमी आई है और आंकड़ों की विश्वसनीयता में बढ़ोत्तरी हुई है। उत्पादन नियंत्रण मॉड्यूल के साथ स्टाक मॉड्यूल को जोड़ दिया गया है और सामग्री निर्गत पर्चियाँ ऑन-लाईन उपलब्ध हैं। यह प्रणाली केवल चालू (करेंट) एवं वैध कार्यादेशों के तहत भण्डारों की निकासी होने देता हैं।

आई.एम.एम.एस. प्रोक्योरमेंट प्रणाली : भण्डार विभाग में आईएमएमएस प्रणाली 1 अप्रैल, 2019 से सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है, जिससे सभी मांगकर्ता, क्रय अधिकारी, निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, निरीक्षण अधिकारी और कॉनसाइनी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और सारा कार्य मांगपत्र बनाने से लेकर क्रय आदेश जारी करने तक का तथा सामग्री प्राप्ति से लेकर उसके अंतिम निस्तारण तक की सारी प्रक्रियाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर बिना किसी देरी के, बिना किसी डुप्लीकेसी के हो रही हैं।

सम्भारक सम्मेलन का आयोजन : रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार सम्भारकों को भारतीय रेल की विविध एवं बढ़ती हुई आवश्यकताओं से जागरुक करने हेतु तथा नए सम्भारकों को रेल से जोड़ने हेतु, डीरेका में 22 मई, 2019 को एक सम्भारक सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन में सम्पूर्ण भारतवर्ष से आए सम्भारकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सम्भारकों को रेलवे में पंजीकरण के बारे में, क्रिटिकल मद के बारे में, खरीद प्रक्रिया के बारे में एवं बिल पास करने के नए सिस्टम के बारे में बताया गया एवं उनके द्वारा उठाई गई शंकाओ का समाधान किया गया।

भविष्य की योजना : सामग्री प्रबंधन की शेष बची हुई कुछ प्रक्रियाओं, जैसे प्रेषण पूर्व निरीक्षण, प्रेषण, डिजिटल बिल सबमिसन को भी इसी पोर्टल पर लाने के लिए कार्य जारी है, ताकि इस वेब पोर्टल के जरिए सामग्री प्रबंधन से जुड़े हुए सभी लोग यानी कि मांगकर्ता, क्रय अधिकारी, निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, निरीक्षण अधिकारी, कॉनसाइनी और वित्त अधिकारी बिना किसी कम्युनिकेशन गैप के एक साथ जुड़े रहें ताकि सामग्री प्रबंधन से संबंधित किसी भी निर्णय का पालन करने में अनावश्यक रूप से होने वाली देरी से बचा जा सके। ■

With Best Compliments from Well Wisher

KAUSHIV ASSOCIATES

B-38/47 PR, Mehmoorganj,
Varanasi-221010
Phone : 0542-2360408
E-mail : info@kaushiv.com

डीरेका के अभिकल्प एवं विकास केंद्र



श्री अनिल कुमार सिंह
प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर एवं मुख्य अभिकल्प इंजीनियर/ डीजल लोको

अभिकल्प एवं विकास केंद्र ने डीजल रेल इंजन कारखाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं–
(क) रेल इंजन परियोजनाएँ, (ख) संरक्षा, (ग) चालक सुविधा, (घ) ईंधन की बचत, (ड) अति मालवाहक क्षमता, (च) स्वदेशीकरण एवं बहु-स्रोतीकरण



डब्लूएजीसी3 इलेक्ट्रिक लोको को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

(क) रेल इंजन परिवर्तन परियोजनाएं

i) डीजल लोको का 10,000 अश्वशक्ति के युगल को-को इलेक्ट्रिक लोको डब्ल्यूएजीसी3 में परिवर्तन

डीरेका ने पुराने दो डब्ल्यूडीजी3ए डीजल लोको को डब्ल्यूएजीसी3 इलेक्ट्रिक लोको में परिवर्तित कर, युगल को-को इलेक्ट्रिक लोको के रूप में 10,000 अश्वशक्ति क्षमता का लोको बनाकर इतिहास रच दिया। प्रथम यूनिट को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णय लेने के मात्र 69 दिनों में 28 फरवरी, 2018 को तैयार कर ट्रायल हेतु निर्गत किया गया। युगल को-को लोको को 30 मार्च, 2018 को डीरेका से निर्गत किया गया। यह इसलिए भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इस परिवर्तन से लोको के कर्षण क्षमता में करीब 92% की विशाल वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप माल ढुलाई क्षमता में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

समुचित ट्रायल एवं मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त (सीसीआरएस) के निरीक्षण एवं संस्तुति के उपरांत रेलवे बोर्ड ने नवम्बर, 2018 को इसके नियमित संचालन की अनुमति प्रदान की। उस समय तक, डीजल लोको से इस उच्चतर क्षमता के इलेक्ट्रिक लोको में परिवर्तन का कार्य विश्व में कहीं नहीं किया गया था, जो कि एक विश्व कीर्तिमान था। **प्रधानमंत्री द्वारा इस लोको को 19 फरवरी, 2019 को डीरेका प्रांगण से राष्ट्र को समर्पित किया गया।**

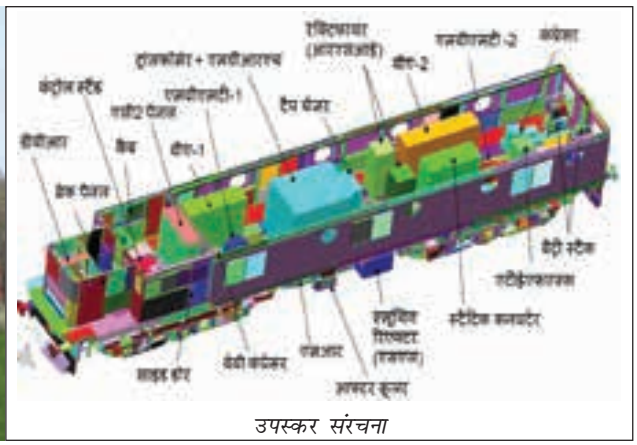
निर्माण की चुनौतियाँ-डब्ल्यूडीजी3ए के पुराने अंडरफ्रेम को मोनोकॉक डिजाइन तथा ट्रांसफार्मर यूनिट, बीए-1 एवं रियेक्टरों इत्यादि बिजली उपकरणों को समाहित करने के लिए बृहत् मॉडिफिकेशन/सुदृढ़ीकरण किया गया।

ii) डब्ल्यूडीजी4 डीजल लोको को 12,000 अश्वशक्ति के युगल को-को इलेक्ट्रिक लोको डब्ल्यूएजी11 में परिवर्तन

रेलवे बोर्ड ने डीरेका को डब्ल्यूडीजी4 लोको को भी 12,000 अश्वशक्ति के डब्ल्यूएजी11 इलेक्ट्रिक लोको में परिवर्तन का लक्ष्य दिया। डीरेका ने इस कठिन एवं चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को भी पूर्ण किया और प्रथम प्रोटोटाइप युगल को-को इलेक्ट्रिक लोको डब्ल्यूएजी11 को दिसंबर, 2018 में निर्गत किया। विश्व इतिहास में इतनी उच्च अश्वशक्ति क्षमता के डीजल लोको को इलेक्ट्रिक लोको में प्रथम बार परिवर्तन किया गया। वर्तमान में आरडीएसओ द्वारा अंतिम गति प्रमाणपत्र जारी होने के उपरांत यह भारतीय रेल का सर्वाधिक शक्तिशाली रेल इंजन बन गया है।



डब्ल्यूएजीसी3युगल को-को इलेक्ट्रिक लोको



उपस्कर संरचना



डबल्यूडीजी3ए के पुराने अंडरफ्रेम का मॉडिफिकेशन कार्य मॉउन्टिंग



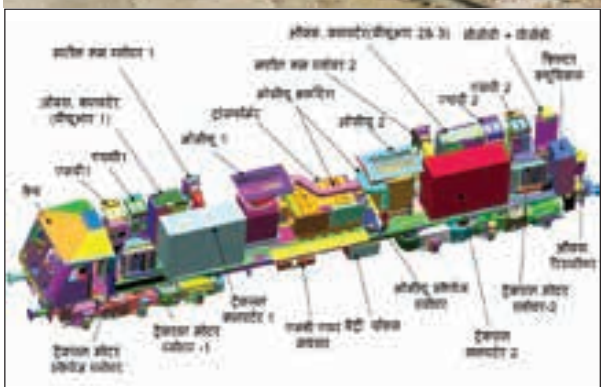
भारतीय रेल सवारी यानों के अनुरुप इंड-वॉल का वेस्टुबल युक्त नया फैब्रीकेशन



बिजली उपकरणों की माउन्टिंग

डब्ल्यूएजी11 युगल को-को इलेक्ट्रिक लोको एवं उसकी उपस्कर संरचना





उपस्कर संरचना

iii) श्रीलंका एसी-एसी लोको

श्रीलंका को पहले भी 1995 से 2014 के मध्य 20 डीरेका निर्मित ब्रॉडगेज लोको भेजा गया था, परंतु इनमें से कोई भी नई तकनीक पर आधारित एसी-एसी लोको नहीं थे। प्रथम बार श्रीलंका रेलवे हेतु 10 नवीनतम तकनीक आधारित 3,000 अश्वशक्ति के एसी-एसी लोको को डीरेका द्वारा डिजाइन कर तैयार किया गया।

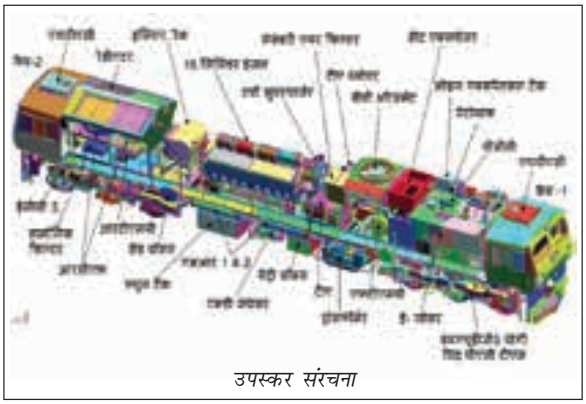
इसमें पहली बार 12 सिलेंडर 710 जी3बी ई.एम.डी. इंजन, ई.एफ.आई. के साथ प्रयोग में लाया गया। पहली बार टीए12सीए9 ऑल्टर्नेटर भी प्रयोग में लाया गया। इसके लिए लोको अंडरफ्रेम को पूरी तरह से नया डिजाइन करना पड़ा। श्रीलंका में क्षरण की गंभीर समस्या को देखते हुए पहली बार नए डिजाइन का स्टेनलेस स्टील कैब (कम ऊँचाई की), लाँग हुड, पाइप एवं पाइप फिटिंग्स का प्रयोग किया गया। पहली बार किसी निर्यात किए जाने वाले लोको में ट्रेड ब्रेक युक्ति (टी.बी.यू.) एवं कनवर्टर आधारित होटल लोड प्रणाली भी लगाई गई।

अक्टूबर, 2018, में प्रथम प्रोटोटाइप श्रीलंका लोको का निर्माण एवं परीक्षण कर प्रस्थान किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल तीन लोको का निर्माण कर श्रीलंका को भेजा जा चुका है।

iv) ड्यूल मोड लोकोमोटिव (डीजल एवं विद्युत चालित)

डीरेका विद्युत और बिना-विद्युत दोनों खण्डों में चलने योग्य ड्यूल मोड लोकोमोटिव के विकास का कार्य कर रहा है। 4,500 अश्वशक्ति, 16 सिलेंडर 710 जी3बी इंजन बिना-विद्युत खण्डों में लोको को शक्ति प्रदान करेगा, जबकि विद्युत खण्डों में लोको ओएचई से विद्युत शक्ति लेकर 4,500 एचपी को कर्षण शक्ति प्रदान करेगा। इस लोको का एक्सल लोड 21 टन होगा।

इस सीमित एक्सेल लोड में ड्यूल मोड लोको की डिजाइन एवं निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती थी। डीरेका ने आरडीएसओ के साथ मिलकर इस मुश्किल अभिकल्प चुनौती को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। इस एसी-एसी लोको में एक उच्च अश्वशक्ति डीजल इंजन के साथ-साथ एक उच्च कर्षण शक्ति विद्युत लोको के सभी उपकरण भी लगे हैं। सीमित एक्सेल लोड में इसे हासिल करने हेतु अंडरफ्रेम की पूरी नई डिजाइन बनाई गई, जिसे पोलैंड की नामी कंपनी ई.सी. इंजीनियरिंग द्वारा प्रमाणित भी कराया गया। साथ ही, वजन कम करने के लिए 5,000 की जगह 3,000 लीटर का ईंधन टैंक लगाया गया। ट्रांसफॉर्मर एवं अन्य उपकरणों में भी वजन कम किया गया। बोगी का वजन कम करने हेतु डबल्यूडीजी5



उपस्कर संरचना

लोको के हाइब्रिड बोगी का प्रयोग किया गया। इसके लिए इसमें तथा अंडरफ्रेम में आवश्यक परिवर्तन किए गये। यह लोको भारतीय रेल में पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए उपयुक्त होगा तथा 135 किमी/घंटा की गति से चलने में सक्षम होगा।

प्रथम ड्यूल मोड लोको का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

इस लोको से भारतीय रेल को निम्नलिखित लाभ होंगे –

- कर्षण परिवर्तन स्थान के दौरान लोकोमोटिव एवं रैक के ठहराव समय में 15 मिनट से अधिक की कमी।
- कर्षण परिवर्तन स्थान पर लोकोमोटिव के खड़े रहने का समय घटाकर इसकी उपलब्धता बढ़ाना एवं आवश्यकता को कम करना।
- कर्षण परिवर्तन स्थान पर लोकोमोटिव की शंटिंग के लिए कार्य दिनों को कम करना।
- नॉन-इलेक्ट्रिफाइड अधिकता वाले गुड्स यार्ड्साईडिंग में लोकोमोटिव के अंतिम खण्ड के परिचालन के उपयोग को बढ़ाना।
- खण्ड में ट्रेनों की संख्या में वृद्धि।
- प्राकृतिक आपदाओं, जैसे तूफान इत्यादि के समय जब ओएचई प्रभावित होता है, उस समय ड्यूल मोड लोको डीजल पर कार्य करके स्थिति सामान्य होने तक परिचालन उपयोगिता प्रदान करता है।
- इलेक्ट्रिफाइड क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्षण मोड उपलब्धता के कारण उच्च विश्वसनीयता।

(ख) संरक्षा

प) लोको कैब वीडियो एवं वॉइस रिकॉर्डिंग प्रणाली (एलसीवीआर)

लोको कैब में लोको पायलटों की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग, बाहरी ट्रैक गतिविधियां की जांच-पड़ताल/घटना के बाद का विश्लेषण तथा स्पैड (SPAD) की जांच हेतु उच्च अश्वशक्ति डीजल लोको कैब में एलसीवीआर पूरी घटना को टैम्पर प्रूफ रिकॉर्ड करने हेतु लगाए गए हैं। इस प्रणाली में प्रति कैब, 2 कैमरा कैब के अंदर और 1 कैमरा बाहर लगा है। इसमें 30 दिनों की वीडियो रिकार्डिंग्स रखी जा सकती है। डीरेका ने अब तक 25 लोको में एलसीवीआर लगा दिया है एवं ये लोको विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में कार्यरत हैं।

एलसीवीआर



बाहरी कैमरा 2 मेगा पिक्सेल





कैब कैमरा 0.4 मेगा पिक्सेल



डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर 1 टी.बी. मेमोरी

(ii) **कोहरा दृष्टि प्रणाली** (एफवीएस) – घने कोहरे के समय सिगनल और रेलपथ के न दिखने के कारण ट्रेन परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। एफवीएस प्रणाली में प्रत्येक कैब में एक डिस्प्ले इकाई लगा होता है, जो कि एक विशेष प्रकार के कैमरा से जुड़ा रहता है। यह घने कोहरे में भी लोको चालक की दृश्य क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे लोको को अधिक गति पर चलाया जा सकता है। यह प्रणाली आरडीएसओ द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टाटा एस.ई.डी. के सहयोग से विकसित की गई है। एफवीएस प्रणाली से युक्त दो पैसेंजर लोको दिसम्बर, 2018 में तुगलकाबाद डीजल शेड भेजे जा चुके हैं, जिनका परीक्षण आरडीएसओ कर रहा है।

कोहरा दृष्टि प्रणाली



कैमरा



कंट्रोल इकाई



कैब डिस्प्ले

(ग) चालक सुविधा

- **लोको पायलट कैब में वातानुकूलित, तापित एवं हवा का प्रवाह (एचवीएसी) का शत-प्रतिशत लगाया जाना**

लोकोमोटिव ऑपरेशन के दौरान कैब के तापमान को आरामदायक स्थिति में रखने के लिए एचवीएसी यूनिट को कैब में लगाया गया है। इससे लोको पायलटों की कार्य क्षमता में गुणात्मक सुधार एवं लोको के सुरक्षित संचालन में बढ़ोत्तरी होगी।

एचवीएसी यूनिट इन्वर्टर युक्त है जिसकी हीटिंग क्षमता 3.0 किलोवॉट तथा वातानुकूलन क्षमता 3.75 टन है। जनवरी, 2016 से सभी उच्च अश्वशक्ति डीजल लोको में एचवीएसी यूनिट नियमित रूप से लगाई जा रही है। 31 मार्च, 2019 तक कुल 911 उच्च अश्वशक्ति लोको एचवीएसीयूनिट के साथ निर्गत किए जा चुके हैं।

(घ) ईंधन की बचत - सहायक शक्ति इकाई (एपीयू)



मालवाहक लोको प्रचालन की अवधि के 50% समय से भी ज्यादा खड़ा रहता है। इस दौरान मुख्य इंजन, लोको बैटरी को चार्ज तथा ब्रेक दबाव को नियंत्रित करता है। इसी कार्य को एपीयू के छोटे इंजन से करने से लगभग 15 ली./घंटा डीजल की बचत होती है। यदि लोको वर्ष में 330 दिन चलता है तथा 50% समय खड़ा रहता है, तो 15,65,725 रुपये की बचत के साथ-साथ उत्सर्जन में भी कमी होगी। वर्ष 2017 से सभी लोको में एपीयू लगाया जा रहा है, तथा कुल 181 उच्च अश्वशक्ति के डीजल लोको में एपीयू लगाया जा चुका है।

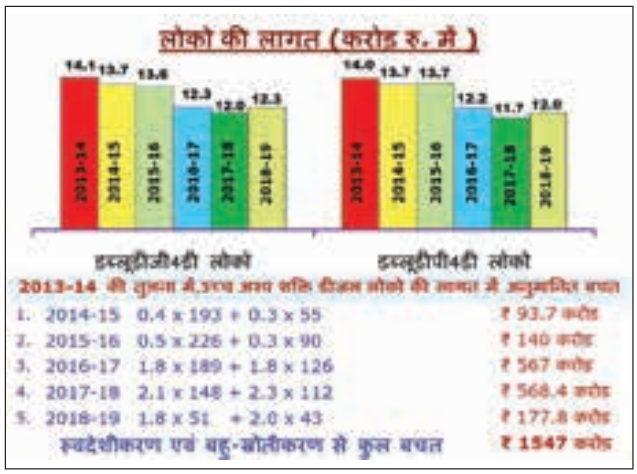
(ड.) वितरित शक्ति नियंत्रण प्रणाली (डीपीसीएस)

डीपीसीएस लम्बी एवं बहुत अधिक भार की मालगाड़ियों के परिचालन के लिए नवीनतम तकनीक है। इसके अंतर्गत ट्रेन निर्माण के दौरान मालगाड़ी में एक साथ 4 लोको एकल/समूह (1 लीड+3 रिमोट) में इच्छित्त स्थानों (अग्र/बीच/पश्च) पर लगाकर, मल्टिपल ऑपरेशन में बिना कप्लर शक्ति को बढ़ाये संचालित किया जा सकता है। रिमोट लोको का कंट्रोल, लीड लोको के द्वारा बेतार-संचार से 3 किमी की दूरी तक किया जा सकता है। भारतीय रेल में डीपीसीएस युक्त उच्च अश्वशक्ति डीजल लोको द्वारा सबसे लंबी ट्रेन (2.5 किमी) का सफलतापूर्वक परिचालन किया जा चुका है।

डीपीसीएस के प्रयोग से खण्ड की क्षमता में बढ़त, क्रू की बचत, बेहतर ट्रेन संचालन, कप्लर विफलता में कमी, ब्रेक दूरी, ब्रेक रिलीज टाइम तथा ब्रेक प्रणाली के घिसाव में कमी होती है। 31 मार्च, 2019 तक कुल 106 उच्च अश्वशक्ति के डीजल मालवाहक लोको में डीपीसीएस लगाए जा चुके हैं।

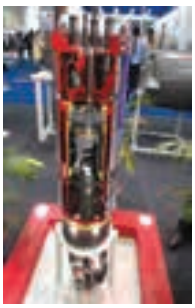
(च) स्वदेशीकरण एवं बहु-स्रोतीकरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उच्च अश्वशक्ति के डीजल इंजन के 65 मदों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, इसके परिणामस्वरूप 44.78 लाख रुपये प्रति लोको की बचत हुई। इसके अतिरिक्त सप्लाई में सुधार एवं दाम में कमी के लिए उच्च अश्वशक्ति के डीजल इंजन के 113 मदों का बहु-स्रोतीकरण किया गया है। इससे विगत 5 वर्षों में लागत में काफी कमी आई है, जिसे बार चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। साथ ही इसके फलस्वरूप होने वाली बचत का आंकलन भी प्रस्तुत किया गया है। इससे देखा जा सकता है कि इन 5 वर्षों में करीब 1547 करोड़ रुपयों की बचत संभव हो पाई है।



प्रमुख आइटम्स का स्वदेशीकरण

I. पावर असेम्बली ब्लेड एवं पावर असेम्बली फोर्क



- डीरेका ने प्रथम बार पावर एसेम्बली के स्वदेशी निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की जो एक प्रमुख आयातित मद है। इसे रेलों को स्पेयर के रूप में भी आपूर्तित किया जाता है।
- सिलेंडर हेड, सिलेंडर लाइनर, पिस्टन, पिस्टन रिंग, कैरियर पिस्टन पिन, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड आदि पावर असेंबली के महत्त्वपूर्ण अंग हैं।

मात्रा / लोको : 16 नं.
आयातित लागत : रु 4.32 लाख/नग (मैसर्स ईएमडी/यूएसए)
स्वदेशी लागत : रु 2.79 लाख/नग (मैसर्स सीएपीएल/सीबीई)
बचत / लोको : रु 24.50 लाख
अनुमोदित स्रोत : मैसर्स ईएमडी/यूएसए, मैसर्स जी.ई./यूएसए
स्वदेशी स्रोत : मैसर्स सीएपीएल/कोयम्बटूर

II. टर्बो व्हील इंपेलर बैलेन्स असेंबली



- डीरेका ने प्रथम बार पावर टर्बो व्हील इंपेलर बैलेंस असेंबली के स्वदेशी निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की, जो कि एच.एच.पी. टर्बो सुपरचार्जर का मुख्य चाइल्ड पार्ट है।
- ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलाजी के तहत कवर नहीं होने के कारण डीरेका के पास इससे संबंधित विस्तृत ड्राइंग, विनिर्देश और निर्माण प्रक्रिया के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
- ओ.ई.एम. द्वारा आपूर्ति किए गए इस आइटम के रिवर्स इंजीनियरिंग से सभी चाइल्ड पार्ट्स, सब-असेंबली और पूरी असेंबली के मॉडल और ड्राइंग विकसित किए गए।
- डीरेका में परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चाइल्ड पार्ट्स के सामग्री विनिर्देश, निर्माण प्रक्रिया तथा निरीक्षण के मानक विकसित किए गए।
- सब-असेंबली और पूरी असेंबली के लिए डाइनैमिक बैलेंसिंग प्रक्रिया द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया गया।

मात्रा/लोको : 1 नं.
आयातित लागत : रु 10.89 लाख/नग (मैसर्स ईएमडी/यूएसए)
स्वदेशी लागत : रु 8.26 लाख/नग (मैसर्स भारत फोर्ज/पुणे)
बचत / लोको : रु 2.63 लाख
अनुमोदित स्रोत : मैसर्स ईएमडी/यूएसए, मैसर्स जीई/ यूएसए, मैसर्स वाल्बर/यूएसए
स्वदेशी स्रोत : मैसर्स भारत फोर्ज/पुणे ■

कार्मिक विभाग के बहुआयामी कार्य



श्री प्रदीप कुमार सिंह
प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारतीय रेल के प्रगति पथ पर भागीदारी में कार्मिक विभाग का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान है।

कार्मिक विभाग द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं –

औद्योगिक सम्बन्ध और कल्याणकारी गतिविधियां

उत्पादन इकाई होने के कारण डीरेका में किसी ट्रेड यूनियन को मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रशासन और कर्मचारियों के बीच सहयोग और सद्भावपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए भारतीय रेल स्थापना संहिता आईआरईएम भाग-।। के 26वें अध्याय में निहित प्रावधानों के तहत कर्मचारी परिषद् का गठन किया गया है। कर्मचारी परिषद् में विभिन्न कार्यशालाओं और कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त महाप्रबन्धक द्वारा 6 अधिकारियों को नामित किया जाता है। कर्मचारी परिषद् की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित की जाती है, जिसमें सामान्य हितों के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। औद्योगिक सम्बन्ध संतोषजनक बने हुए हैं।

संयुक्त परिषद – प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी योजना के तहत निर्विघ्न कार्य संचालन के लिए संयुक्त परिषद् का गठन किया गया है आवधिक बैठकों में उत्पादन की प्रगति, सुरक्षा तथा कार्य स्थितियों में सुधार लाने के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर चर्चा की जाती है।

क्षेत्रीय समिति – डीरेका परिसर के निवासियों के बीच सामुदायिक भावना और नागरिकता बोध विकसित करने तथा सफाई, स्वच्छता और चहुमुखी सुव्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से एक क्षेत्रीय समिति बनाई गई है। क्षेत्रीय समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है, जिसमें आवासों के रख-रखाव के मामलों को समय से निपटाने के लिए प्रशासन को जानकारी दी जाती है।

डीरेका परिसर में शैक्षणिक वातावरण

डीरेका प्रशासन सीबीएसई पैटर्न पर कक्षा छह से बारहवीं कक्षा तक का एक इंटर कॉलेज एक पाली में चलाता है। इस कॉलेज में छात्र तथा छात्राओं की कुल संख्या 953 है। इसके अलावा-

- डीरेका परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय महिला डिग्री कालेज स्थापित है, जिसमें स्नातक स्तर की कला संकाय की शिक्षा दी जाती है। इसमें छात्राओं की संख्या 600 है।
- डीरेका उपनगर में कक्षा । से XII तक का एक केन्द्रीय विद्यालय है, जिसमें छात्रों की संख्या 1,902 है। यह विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संचालित है। डीरेका परिसर में एक अन्य केन्द्रीय विद्यालय नं. 4 भी पूर्व प्राथमिक पाठशाला नर्मदा के भवन में संचालित है जो कक्षा । से x तक चल रहा है जिसमें छात्रों की संख्या 460 है।
- डीरेका परिसर में डीरेका महिला संगठन द्वारा नर्सरी से कक्षा 5 तक अंग्रेजी माध्यम का एक विद्यालय बाल निकेतन संचालित किया जाता है जिसमें छात्रों की संख्या 1,054 है।
- डीरेका परिसर में लोअर केजी से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम का एक विद्यालय सेंट जॉन्स स्कूल है, जिसमें छात्रों की संख्या 3,920 है।

डीरेका परिसर में मनोरंजक गतिविधियां

सिनेमा क्लब – डीरेका सिनेमा क्लब के सदस्यों की संख्या 3,085 है। यहां प्रेक्षागृह में 4"x18" के प्लास्टिक स्क्रीन पर फिल्में दिखाई जाती हैं। इसमें केवल सिनेमा क्लब के सदस्यों के लिए ही प्रवेश की अनुमति है तथा प्रवेश दर 15 से 20 रुपये तक है।

डीरेका संस्थान – डीरेका संस्थान में 2,350 सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों के लिए पुस्तकालय, वाचनालय तथा इनडोर, आउटडोर खेल की सुविधाएँ प्रदान करता है। इस संस्था में सभी आयु वर्ग के लिए लगभग 10,948 पुस्तकें वाचनालय में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पश्चिम उपनगर में मुख्य संस्थान के पीछे एक वाचनालय की सुविधा भी उपलब्ध है।

डीरेका महिला संगठन

डीरेका महिला संगठन रेलकर्मियों एवं उनके परिवार, विशेषतया महिलाओं तथा बच्चों में सामाजिक कल्याण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्द्धन में सक्रिय है। समिति की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :-

बाल निकेतन – 'बाल निकेतन' डीरेका महिला कल्याण संगठन द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध अंग्रेजी मीडियम का प्राथमिक विद्यालय है। अकादमिक सत्र 2018-19 में छात्रों की कुल संख्या 1,054 थी। इसमें 54 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं।

कलांजलि स्कूल

कलांजलि सिलाई सेंटर – यह नियमित सिलाई, मशीन कढ़ाई, हाथ कढ़ाई और कपड़े चित्रकला में प्रशिक्षण देता है। इनके साथ, मेहंदी, पॉट बनाने, टाई और डाई इत्यादि जैसे शौक वर्ग भी आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, 82 छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण लिया।

कलांजलि ब्यूटीशियन ट्रेनिंग सेंटर – डीरेका महिला कल्याण संगठन ने इस साल मार्च, 2019 से डीरेका परिसर में एक ब्यूटीशियन ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। 36 प्रशिक्षु इस प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं।

चेतना – चेतना विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए एक स्कूल वर्ष 1996 से सफलतापूर्वक चल रहा है। स्कूल में 19 छात्र है, जिसमें सुनने में असमर्थ और मानसिक रूप से मंद, दोनों प्रकार के छात्र शामिल हैं।

छात्रों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षणों के साथ बुनियादी शिक्षा – जैसे कि त्यौहार के दौरान मोमबत्तियाँ बनाना, कपड़े की थैली और पाउच, पेपर क्राफ्ट का काम और गुलाल बनाना आदि।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र – डीरेका कर्मचारियों एवं उनके बच्चों को उचित कीमत पर कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए डीरेका महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित आई.टी. सेंटर एक उत्कृष्ट केन्द्र है। वर्ष 2018–19 के दौरान 90 विद्यार्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

क्रेच – हैप्पी हार्ट्स क्रेच 7 बच्चों के साथ मार्च, 2013 में शुरू हुआ था। 30 से 35 चुब्बी फेस्डी एंजिल पूरे दिन रहते हैं।

पेंटिंग स्कूल – डीरेका का पेंटिंग स्कूल काफी लोकप्रिय संस्थान है। यहां पर कलर पेंटिंग, स्केचिंग तथा मॉडल मेकिंग इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम डीरेका तथा डीरेका के बाहर के इच्छुक बच्चों के लिए चलाया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत एक प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018–19 के लिए कुल 102 विद्यार्थियों ने कक्षाओं के लिए अपना पंजीयन कराया है।

बागवानी प्रतियोगिता – डीरेका महिला कल्याण संगठन द्वारा फरवरी, 2019 में एक बागवानी प्रतियोगिता का आयोजन टाइप I,II,III एवं IV आवासों के डीरेकाकर्मियों के बीच किया गया। कुल 20 आवासों का डीरेका महिला कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया गया तथा उन्हें तद्नुसार पुरस्कृत किया गया।

वर्ष 2018–19 में किए गए अन्य कल्याणकारी क्रियाकलाप

(i) केन्द्रीय रेलवे महिला कल्याण संगठन नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 सितम्बर, 2018 तथा 16 सितम्बर, 2018 को डीरेका महिला कल्याण संगठन द्वारा संचालित बाल निकेतन स्कूल में पेंटिंग तथा निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 9 सितम्बर, 2018 को पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 156 विद्यार्थियों ने भाग लिया जबकि 16 सितम्बर, 2018 को आयोजित निबंध प्रतियोगिता में कुल 84 विद्यार्थियों ने अपने लेखन कौशल का प्रदर्शन किया। लगभग 27 विद्यार्थियों को निबंध एवं ड्राइंग प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया।

(ii) 25 वर्ष की सेवा पूरा करने वाले ग्रुप 'डी' के मेहनती कर्मचारियों के लिये अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कठिन परिश्रम एवं समर्पित सेवाओं के लिए 13 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

बैंक एवं डाकघर : डीरेका कर्मचारियों की सुविधा के लिए परिसर में दो बैंक एवं दो डाकघर हैं। दोनों बैंकों अर्थात् स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध है!

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र : डीरेका में आरक्षण सुविधा हेतु एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र है।

खेलकूद सुविधा : 18 होल (11 फेयारवेज) का एक गोल्फ कोर्स, एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का तरणताल, फ्लडलाइट युक्त एक मड वॉलीबॉल कोर्ट, एक हैंडबॉल कोर्ट, एक फुटबॉल ग्राउंड, एक घास युक्त हॉकी का मैदान, एक मल्टी इक्यूपमेंट युक्त जिम, वूडेन फ्लोरिंग युक्त 2 बैडमिंटन कोर्ट, मैट युक्त कुश्ती केन्द्र, फ्लडलाइट युक्त सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, फ्लडलाइट युक्त एक सिंथेटिक तथा एक सीमेंटेड बास्केटबॉल कोर्ट और पैवेलियन युक्त क्रिकेट का मैदान है जिसमें अभ्यास हेतु 4 विकेट बने हैं। ■



डीरेका में लागत निर्धारण की प्रक्रिया



श्री जय नारायण पाण्डेय
प्रमुख वित्त सलाहकार

किसी भी औद्योगिक उत्पादन इकाई में लेखा विभाग की एक अहम भूमिका होती है। समस्त वित्तीय लेन-देन का लेखा-जोखा तथा वित्तीय प्रबंधन के अतिरिक्त मासिक तथा वार्षिक लेखों का कुशलतापूर्वक सम्पादन करना इस विभाग का मुख्य कार्य होता है। इसके अतिरिक्त यह उच्च प्रबंधन को महत्त्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराता है, जिससे प्रबंधन को यथोचित निर्णय लेने में सुविधा होती है।

चूंकि डीरेका भारतीय रेल की एक उत्पादन इकाई है अत: देखा जाए तो इसकी लेखांकन की विधि क्षेत्रीय रेलों की लेखांकन पद्धति से थोड़ी भिन्न है, जहाँ क्षेत्रीय रेलों में राजस्व तथा पूंजी दोनों शीर्ष संचालित किए जाते हैं, वहीं डीरेका में मात्र पूंजी शीर्ष के अंतर्गत ही लेखों का संकलन किया जाता है तथा प्राइमरी यूनिट के स्थान पर वर्क ऑर्डर पद्धति के अंतर्गत समस्त वित्तीय लेन-देन का लेखांकन संपादित किया जाता है। चूंकि इस उत्पादन इकाई का प्रमुख उत्पाद रेल इंजन तथा इसके कलपुर्जे हैं अत: इन सबके लागत का निर्धारण करना लेखा के अन्य कार्यों के अतिरिक्त एक विशेष तथा महत्त्वपूर्ण कार्य है। अत: इस लेख में लागत निर्धारण की प्रक्रिया पर मुख्य रूप से प्रकाश डालना चाहूँगा।

लागतीकरण प्रक्रिया

डीरेका में लागतीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत रेल इंजनों की लागत निकालने हेतु वर्क ऑर्डर प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। 'कार्यदेश इकाई' द्वारा कारखाना व्यय का लेखा-जोखा रखने के साथ उसका विश्लेषण किया जाता है इस प्राधिकार के अंतर्गत कारखाने में निर्माण कार्य लिया जाता है। कारखाने में खर्चों की बुकिंग करने तथा व्यय के विश्लेषण हेतु पृथक-पृथक कार्यदेश होते हैं।

लागत के प्रमुख घटक

(क) सामग्री, (ख) श्रमशक्ति, (ग) ओवरहेड लागत

सामग्री लागत

स्टोर डिपो से सामग्री निकालने हेतु सामग्री मांग पत्र नोट तथा इशू नोट का उपयोग किया जाता है, जिसमें अन्य तथ्यों यथा मात्रा इत्यादि के अतिरिक्त कार्यादेश संख्या भी लिखी होती है। माह के अंत में समस्त इशू मात्रा का ब्योरा एलडीएसआई (मासिक इशू विवरणी) में संगणित करते हुए स्टोर सब लेजर तैयार कर कारखाना जनरल रजिस्टर में इशू संबंधित आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिसके आधार पर आगे चलकर कॉस्ट रिपोर्ट का प्रतिपादन किया जाता है।

श्रमशक्ति लागत

कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का हिसाब दो जगह रखा जाता है।

भुगतान हेतु

जिस कार्य हेतु उनको रखा गया है, उस पर श्रम भुगतान के आवंटन हेतु प्रथम कार्य के लिए गेट पर उपस्थिति कार्ड रखे जाते हैं, जिनको उपस्थिति का प्रारम्भिक रेकार्ड माना जाता है तथा यह मस्टर रोल का काम करते हैं। दूसरे कार्य हेतु अर्थात् कार्य आदेश पर श्रम भुगतान आवंटन करने हेतु कार्य कार्ड/समय शीट प्रणाली प्रचलित है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी द्वारा विभिन्न कार्यों पर लगाए गए समय का रेकार्ड समय प्रभारित किए जाने वाले कार्य आदेश के समक्ष किया जाता है। बाद में तुलना पत्रों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समाधान किया जाता है, कि गेट उपस्थिति कार्डों के माध्यम से वास्तव में भुगतान किए कार्य घंटों तथा कार्य कार्डों / समय शीटों द्वारा विभिन्न कार्य आदेशों में आवंटित कार्य घंटों में कोई अंतर नहीं है, समय बुक करने वाले दस्तावेजों में दर्शाए कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्य आदेशों के लिए दिए गए कार्य समय का श्रमिकों की प्रत्येक सीढ़ी, जैसे उच्च कुशल, कुशल, कुशल समान एवं अकुशल के लिए औसत प्रति घंटा दर के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है। इसमें श्रमिकों के लिए प्रभारित किए जाने वाले विभिन्न कार्य आदेशों की राशि पता चलती है। औसत प्रतिघण्टा दर का निर्धारण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है, श्रमिकों की विभिन्न कैटेगरी, जो अलग-अलग शॉप्स में कार्यरत रहते हैं, को पिछली तिमाही में किए गए भुगतान का औसत निकाल लेते हैं तथा वर्तमान त्रैमास हेतु अंडरचार्ज तथा ओवरचार्ज की गणना करते हुए प्रभारित कर दिया जाता है। इसके साथ ही जहां योजना लागू है वहां कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस भी दिया जाता है।

ओवरहेड लागत

श्रमिकों एवं सामग्री के स्पष्ट व्यय के साथ ही व्यय की बहुत सी ऐसी मदें होती हैं जिनको निर्मित सामान अथवा किए गए कार्य पर स्पष्ट प्रभारित नहीं किया जा सकता, जैसे अपरोक्ष सामग्री, श्रमशक्ति आदि। इस प्रकार के प्रभारों को ओवरहेड लागत कहा जाता है। डीरेका में यह चार प्रकार के होते हैं।

(i) कारखाना ओवरहेड (ii) प्रशासनिक ओवरहेड
(iii) टाउनशिप ओवरहेड (iv) स्टोर्स ओवरहेड

कारखाने में होने वाले ऐसे अप्रत्यक्ष खर्चों को अलग से प्रचलित वर्क ऑर्डरों द्वारा सभी कार्यों में उन पर होने वाले प्रत्यक्ष श्रम के खर्च के अनुपात में बाँट दिया जाता है। वार्षिक अधिव्यय बजट बनाकर और ऐसे कार्यदेशों में अंडरचार्ज तथा ओवरचार्ज की गणना करते हुए प्रभारित करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सम्पूर्ण व्यय का सही-सही आवंटन हो जाए। स्टोर्स ओवरहेड के बारे में स्थिति थोड़ी भिन्न होती है। यहां व्यय को प्रत्यक्ष श्रम के खर्च के अनुपात में न बाँट कर कुल स्टोर्स की लागत के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

कारखाना सामान्य रजिस्टर

प्रत्येक कार्यादेश के अंतर्गत निर्गत किए गए मटिरियल की लागत स्टोर्स सब लेजर से प्राप्त कर ली जाती है तथा उस वर्क ऑर्डर में प्रयुक्त होने वाली श्रमशक्ति की लागत की गणना लेबर

सब लेजर से प्राप्त कर ली जाती है। प्रत्येक वर्कऑर्डर में लगने वाले ओवरहेड खर्चों को उस वर्क ऑर्डर में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यक्ष श्रमिक घंटों के आधार पर प्रभारित किया जाता है। डब्ल्यूजीआर में प्रत्येक वर्क ऑर्डर का मासिक सकल व्यय तथा उस माह के अंत तक कुल योग भी उपलब्ध रहता है।

इस प्रकार से डब्ल्यूजीआर में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक लोको की कास्ट रिपोर्ट बना ली जाती है। वर्ष के अंत में सभी लोको की लागत का एक औसत निकाल कर हर प्रकार के लोको की औसत यूनिट कास्ट निकाल ली जाती है, जिसके आधार पर लोको का अंतरण मूल्य निर्धारित किया जाता है जो अमूमन यूनिट कास्ट के बराबर ही निर्धारित किया जाता है। लोको बन जाने के पश्चात् रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार लोको संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को भेज दिया जाता है तथा प्रत्येक माह की एक तारीख को इसी अंतरण मूल्य के आधार पर रेलवे बोर्ड से क्रेडिट प्राप्त कर लिया जाता है। डीरेका में विगत वर्षों में बनने वाले विभिन्न प्रकार के लोको का अंतरण मूल्य निम्न है।

विगत दस वर्षों में एल्को तथा एचएचपी लोको का अंतरण मूल्य

राशि (करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	एचएचपी एवं विद्युत लोको पर लागत (अंतरण मूल्य) HHP & Electric Per Loco									
		WDG-4	WDP-4	WDP-4B	WDP-4D	WDG-4D	WDG-5	WAP-7	WAG-9	WAG-10	WAG-11
1	2008-09	11.50	11.00	--	--	--	--	--			
2	2009-10	11.50	11.00	--	--	--	--	--			
3	2010-11	11.50	--	11.50	--	--	--	--			
4	2011-12	11.62	--	11.62	--	--	14.14	--			
5	2012-13	12.50	--	12.50	13.27	13.27	--	--			
6	2013-14	14.80	--	14.80	15.00	15.00	--	--			
7	2014-15	14.03	--	--	14.19	14.19	17.86	--			
8	2015-16	13.00	--	--	13.80	13.50	16.20	--			
9	2016-17	--	--	--	12.40	12.45	18.00	--			
10	2017-18	--	--	--	11.70	11.90	18.00	--			
11	2018-19	--	--	--	11.24	11.55	17.06	12.08	12.08	5.35	5.35
12	2019-20	--	--	--	11.70	12.30	17.70	12.08	10.85	6.80	12.80

0542-2980085.
V. Maurya
D 59/79,B2- C3, Mahadeva Residencies .
Sigra Mahmoorgunj Road, Varanasi -221010, Uttar Pradesh, INDIA.
railcorin@gmail.com

Our Channel Partners:

Gekatex Technical Wiping Solutions
KLINGSPOR
express painting
AVERY DENNISON

आदर्श डीरेका उपनगर के निर्माण में इंजीनियरिंग विभाग की महती भूमिका



श्री राजेश अग्रवाल
प्रमुख मुख्य इंजीनियर

डीजल रेल इंजन कारखाना (डीरेका) को प्रारंभ में डीजल पुर्जा कारखाना (एल.सी. डब्ल्यू.) के नाम से जाना जाता था। कारखाने की स्थापना से लेकर आजतक डीरेका के वर्तमान स्वरूप में इंजीनियरिंग विभाग की महती भूमिका रही है।

डीरेका परिसर लगभग 300 हेक्टेयर में फैला है। इसमें लगभग 3,700 आवास हैं, जिनमें दो डुप्लेक्स ईकाइयां हैं। सभी आवास, जो 102 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस एवं कंक्रीट सड़कों द्वारा भली प्रकार से जुड़े हुए हैं। संपूर्ण आवासीय परिसर आदमकद चारदीवारी से घिरा है। सुचारु आवागमन हेतु प्रत्येक दिशाओं में वृहद प्रवेश द्वार बनाए गए है। सम्पूर्ण परिसर के कुल क्षेत्रफल का 23.66 प्रतिशत भूमि हरित क्षेत्र है। परिसर में एक लाख से अधिक पौधरोपण कराये गए है। सम्पूर्ण परिसर बेहतरीन नगर योजना का अनूठा उदाहरण है।

मानव संसाधन का श्रेष्ठतम उपयोग : वर्तमान में इंजीनियरिंग विभाग में कुल 380 कर्मचारी (लगभग 221 तकनीकी एवं गैर तकनीकी चतुर्ण श्रेणी कर्मचारी, लगभग 123 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों एवं लगभग 36 पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त एक-एक लेखा विभाग व विधि विभाग के कर्मचारी) तैनात हैं। सभी कर्मचारी विभागाध्यक्ष, उप विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ इंजीनियर एवं सहायक इंजीनियर के कुशल निर्देशन में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

रेल संपत्ति का संरक्षण एवं राजस्व संग्रह : डीरेका चारदीवारी से घिरा होने के कारण अतिक्रमण मुक्त है। यहां की जरूरत एवं सुविधायों को ध्यान में रखकर स्कूल, बाजार, खेल एवं मनोरंजन के संसाधन गैर रेलवे व्यक्तियों/प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस के आधार पर आवंटित एवं संचालित किए जाते हैं, जिनसे लगभग रु. 70 लाख वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है।

स्वच्छ परिसर : इंजीनियरिंग विभाग ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को हाथों हाथ लिया है। डीरेका परिसर को स्वच्छ रखने के संकल्प को सिविल इंजीनियरिंग विभाग की स्वास्थ्य निरीक्षकों की दो इकाइयों जिसमें लगभग 29 (26+3) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी कार्यरत है, माध्यम से साकार किया जा रहा है। नियमित अंतराल पर मच्छर निरोधी छिड़काव एवं फागिंग आदि द्वारा स्वास्थ्य देखभाल की जाती है। कारखाना परिसर की भी दिन प्रतिदिन की विशेष स्वच्छता को प्रमुखता दी गई है।

पर्यावरण संरक्षण : डीरेका परिसर में पर्यावरणीय पैरामीटर के अनुपालन की मॉनिटरिंग सरकार की पंजीकृत प्रयोगशालाओं एवं आंनलाइन इन हाउस मॉनिटरिंग द्वारा की जाती है। पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के कारण डीरेका परिसर वर्ष 2001 से ही आईएसओ 14001 प्रमाणित परिसर है। इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयास निम्नलिखित हैं-

वृक्षारोपण कार्यक्रम : इस कार्यक्रम द्वारा डीरेका की खाली भूमि पर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुकूल वृक्षों का रोपण किया जाता है। वर्तमान में 71.08 हेक्टेयर भूमि, जो सम्पूर्ण परिसर के कुल क्षेत्रफल का 23.66 प्रतिशत है, वृक्षों से ढका है।

भू जल एवं पेय जल संरक्षण : भू जल संरक्षण हेतु भू जल दोहन के घंटो में भारी कटौती करके दोहन की मात्रा 12.17 एमएलडी प्रतिदिन तक न्यूनीकृत की गई है। भू जल स्तर के उन्नयन हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु डीरेका परिसर स्थित 47 रीचार्ज वेल एवं 424 जल सोप पिट का प्रयोग किया जा रहा है। 5 अन्य रीचार्ज वेल का निर्माण प्रस्तावित है। 5 परित्यक्त ट्यूबेल को भी रिचार्ज वेल में परिवर्तित करा लिया गया है। विभिन्न स्थानों पर शोधित एवं वर्षा जल संग्रह हेतु सरोवरों के निर्माण एवं प्रयोग हमारी संचेतना को घोतक है।

मल जल शोधन संयंत्र : डीरेका द्वारा बहिस्रावित मल जल के शोधन हेतु स्थापित संयंत्र 1989 से सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। इस संयंत्र की क्षमता 12 एम.एल.डी. प्रतिदिन है। यह लगभग 3.96 एम.एल.डी. मल-जल प्रतिदिन शोधित करता है। शोधित जल बागवानी, डीरेका स्टेडियम, गोल्फ कोर्स में सिंचाई हेतु एवं विभिन्न सरोवरो में संग्रह हेतु प्रयोग किया जाता है।

औद्योगिक बहिस्राव शोधन संयंत्र : डीरेका के औद्योगिक बहिस्राव के शोधन हेतु स्थापित संयंत्र से सफलता पूर्वक 03 एम.एल.डी. प्रतिदिन बहिस्राव शोधित किया जा रहा है।

वॉटर रिसाइक्लिंग प्लांट की स्थापना : विगत वर्ष दो वॉटर रिसाइक्लिंग प्लांट का निर्माण प्रारंभ हुआ। एक प्लांट द्वारा सरोवर स्थित जल को रिसाइकिल करके पुनः उपयोग लायक बना कर भूजल के दोहन को न्यूनीकृत करने का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। डीरेका वासियों के शिकायतों के निवारण हेतु आन लाइन सिविल कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से डीरेका वासियों में सिविल विभाग से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाता है। ■



डीजल रेल इंजन कारखाना सेवा अभियांत्रिकी विभाग : एक दृष्टि में



श्री सुनील कुमार
मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/
सेवा अभियांत्रिकी

डीजल रेल इंजन कारखाना, भारतीय रेल की एक उत्पादन इकाई है, जो पिछले 55 वर्षों से भारतीय रेलों को डीजल लोको की आपूर्ति करती रही है। वर्तमान में 'गैर रेलवे उपभोक्ता' एवं निर्यात हेतु डीजल लोको की आपूर्ति के साथ-साथ विद्युत लोको की भी आपूर्ति की शुरुआत की गई है। इस बदलते हुए उत्पादन मिश्रण के अनुसार इस उत्पादन इकाई ने अपने आंतरिक स्वरूप को विभिन्न स्तर पर बदला है। विद्युत लोको के निर्माण में आनेवाली विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। इस प्रकार डीजल लोको के निर्माण से 6,000 अश्व शक्ति के विद्युत लोको डबल्यूएपी7/ डबल्यूएजी9एच के निर्माण की चुनौती को भी स्वीकार कर सभी उपलब्ध संसाधनों को सरेखित किया गया है।

उपलब्ध संसाधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग को सरेखित करते हुए डीरेका वाराणसी के अंदर लोकोमोटिव की निर्माण प्रक्रिया के लिए उपलब्ध कुल 1,782 मशीनों का अनुरक्षण, सेवा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। इनमें 59 मशीनें उत्पादन के लिए अत्यावश्यक एवं विशेष महत्त्व की हैं। सेवा अभियांत्रिकी अनुभाग का मुख्य कार्य उत्पादन प्रक्रिया को संयंत्रों, औजारों, जिग्स, फिक्सचर्स एवं संपीडित वायु की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना है। इस विभाग के अंतर्गत आने वाले संयंत्र अनुभाग, औजार अनुभाग, आधुनिकीकरण अनुभाग तथा अतिरिक्त पुर्जा अनुभाग का सराहनीय योगदान रहा है।

संयंत्र अनुभाग : संयंत्र अनुभाग ने पुराने 'स्ट्रेस रिलिविंग फर्नेस' का रुपांतरण किया, जिसके बाद इस फर्नेस में इलेक्ट्रिक लोको की बोगी फ्रेम का 'स्ट्रेस रिलिविंग' कर सकने में डीरेका सक्षम हो पाया। इसी प्रकार सेवा अभियांत्रिकी अनुभाग ने इलेक्ट्रिक लोको के ब्रेकिंग सिस्टम की उचित टेस्टिंग की आवश्यकता को देखते हुए अपने आंतरिक स्रोतों का उपयोग करते हुए पूरी असेम्बली लाइन में 10 किग्रा/सेमी^{2} के दाब पर संपीडित वायु की उपलब्धता एलएएस तथा एलएफएस में कराई, जिससे लोको के निर्माण एवं टेस्टिंग में सुविधा हुई।

साथ ही साथ, व्हील एवं एक्सल के निर्माण की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 'टाकीसावा एक्सल टर्निंग लेथ' का पुनरुद्धार किया गया। इससे मशीन में बार-बार होने वाली खराबियों से बचा जा सका और मशीन की उपलब्धता बढ़ा कर उत्पादन की क्षमता बढ़ाई गई। महत्त्वपूर्ण एवं अति महत्त्वपूर्ण मशीनों पर विद्युत उर्जा की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यूपीएस लगाए गए, जिससे मशीनों का नियंत्रण सिस्टम तथा जॉब सुरक्षित रहते हैं।

इसके अलावा सेवा अभियांत्रिकी अनुभाग द्वारा विभिन्न मेक के कम्प्रेसरों की मरम्मत की जाती है जिसके लिए जेनेरिक स्पेसिफिकेशन के साथ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की खरीद करने के लिए विभिन्न फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए तेलों के विभिन्न नमूनों का सीएमटी लैब के माध्यम से परीक्षण किया गया और तेलों के महत्त्वपूर्ण मापदंडों की वैल्यू को प्राप्त किया गया। इसके आधार पर जेनेरिक स्पेसिफिकेशन को बनाया गया और जिससे बहुत कम लागत में डीरेका को प्रतिष्ठित ब्रांड के ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल प्राप्त हुए।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और वैधानिक आवश्यकता पूर्ण करने के लिए मौजूदा इनसिनरेटर में 'ऑनलाइन फ्यूल गैस मॉनिटरिंग सिस्टम' स्थापित किया गया है।

प्रणाली हवा की गुणवत्ता के बारे में ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्रदान करती है (यानि SO_x, NO_x एवं पार्टिकुलेट मैटर का %)। यह वास्तविक समय के आधार पर वातावरण में छोड़ी गई गैसों की गुणवत्ता संतोषजनक है या नहीं, के विषय में बताता है। इसका विवरण इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल पर भी उपलब्ध रहता है।



रुपांतरित फर्नेस



रुपांतरित फर्नेस



ऑनलाइन फ्यूल गैस मॉनिटरिंग सिस्टम

अतिरिक्त पुर्जा अनुभाग

यह अनुभाग बीआईएम, आयातित, टूलिंग एवं आरएसपी मदों को खरीदकर या डीरेका में बनाकर क्षेत्रीय रेलवे को आपूर्ति करता है।

टूलिंग (औजार) अनुभाग

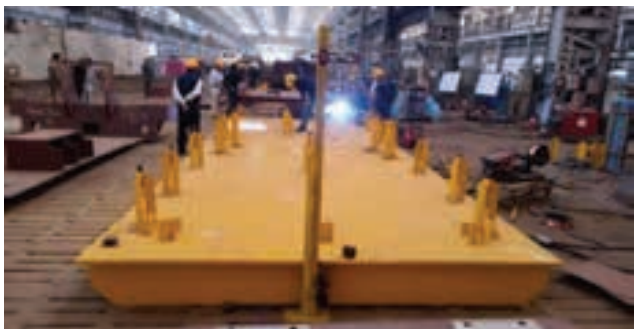
जिग फिक्सचर एवं औजार से संबंधित सभी कार्य टूलिंग अनुभाग द्वारा किया जाता है। प्लांट एवं टूल डिजाइन कार्यालय द्वारा तैयार डिजाइन को यंत्र कक्ष में भेजा जाता है। तद्नुसार यंत्र कक्ष औजार का निर्माण कर संबंधित कर्मशाला को सौंप देता है। उपरोक्त के साथ-साथ कर्मशाला में बन रहे लोकोमोटिव के पुर्जो के निर्माण के दौरान प्रयुक्त होने वाले औजार, जो सीधे बाजार में उपलब्ध हैं, की खपत के अनुसार खरीद प्रक्रिया के माध्यम से खरीद कर संग्रह करता है व कर्मशालाओं की मांग पर उपलब्ध कराता है।

समस्त कर्मशालाओं के द्वारा उपयोग में लाए जा रहे औजारों के रख-रखाव, अनुरक्षण इत्यादि भी यंत्र कक्ष के द्वारा किया जाता है। विभिन्न कर्मशालाओं में यंत्र कक्ष के छोटे-छोटे अनुभाग स्थापित हैं जिनके माध्यम से कर्मशालाओं को मदद मिलती है जिससे कि लोकोमोटिव का निर्माण कार्य सुचारु रुप से चलता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान औजार अनुभाग द्वारा विद्युत लोकोमोटिव के अंडर फ्रेम, शेल एवं बोगी के निर्माण में उपयुक्त जिग्स एवं फिक्सचर्स इत्यादि की डिजाइन तैयार करने के उपरांत यंत्र कक्ष द्वारा इनका निर्माण कर संबंधित कर्मशालाओं को सौंपा गया, जिसके फलस्वरूप विद्युत लोको के अंडर फ्रेम, शेल एवं बोगी निर्माण की क्षमता डीरेका ने हासिल की।

औजार अनुभाग द्वारा निर्मित महत्त्वपूर्ण एवं नवीनतम जिग्स, फिक्सचर्स निम्नांकित हैं :-

i) **अंडर फ्रेम निर्माण हेतु फिक्सचर :** इस फिक्सचर का निर्माण लोको फ्रेम शॉप के सहयोग से यंत्र कक्ष द्वारा किया गया। यह फिक्सचर विद्युत लोको के अंडर फ्रेम के निर्माण हेतु अति महत्त्वपूर्ण था।



विद्युत लोको अंडर फ्रेम फिक्सचर

ii) **शेल निर्माण हेतु फिक्सचर व अन्य सहायक फिक्सचर:** ये फिक्सचर्स विद्युत लोको के अंडर फ्रेम के निर्माण हेतु अपरिहार्य थे।



शेल निर्माण हेतु फिक्सचर

iii) **बोगी मेन एसेम्बली फिक्सचर :** इलेक्ट्रिक लोको (डबल्यूएपी7) के बोगी में कई सब-ऐसम्बलियाँ होती हैं।

इन सभी सब-एसेम्बलियों को बोगी मेन एसेम्बली फिक्सचर पर एकत्रित कर बोगी फ्रेम की मेन एसेम्ब्ली तैयार कर ली जाती है। तत्पश्चात् इन सभी को टैक वेल्ड कर जोड़ दिया जाता है।



बोगी मेन एसेम्बली फिक्सचर का प्रयोग

iv) **रोल ओवर बोगी फ्रेम फिक्सचर :** बोगी फ्रेम मेन एसेम्बली तैयार होने तथा टैक वेल्ड के पश्चात् इसे रोल ओवर बोगी फ्रेम फिक्स्चर पर लाया जाता है। बोगी मेन फ्रेम को घुमा-घुमाकर सम्पूर्ण डाउन हैंड वेल्डिंग की जाती है।

विद्युत लोको के अंडर फ्रेम एवं शेल के निर्माण हेतु कुल 22 फिक्सचर्स का डिजाइन एवं निर्माण औजार अनुभाग द्वारा किया गया इन फिक्सचरों से लोको फ्रेम शॉप में सफलतापूर्वक कार्य हो रहा है। निर्मित फिक्सचरों की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार विद्युत लोको की बोगी के निर्माण व एसेम्बली हेतु कुल 10 फिक्सचर्स का निर्माण ब्लॉक शॉप / ट्रक मशीन शॉप के सहयोग से औजार अनुभाग द्वारा किया गया। इन सभी फिक्सचर्स का मूल्य लगभग 85.38 लाख रुपये है।

टूलिंग अनुभाग ने पूरे कारखाने में विभिन्न स्थलों पर इधर उधर पड़े लावारिस स्टील स्क्रैप का निस्तारण भी करवाया। इसके तहत् वित्त वर्ष 2018-19 में 1,112 मीट्रिक टन स्टील स्क्रैप भंडार अनुभाग को अंतिम निस्तारण हेतु उपलब्ध करवाया गया, जिसके फलस्वरुप डीरेका को महत्त्वपूर्ण राजस्व की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ, इलेक्ट्रिक लोको के निर्माण स्थल को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाया जा सका और उत्पादन कार्य सुचारु रुप से हो सका। इस प्रकार डीरेका का औजार अनुभाग लोको उत्पादन में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

आधुनिकीकरण अनुभाग

आधुनिकीकरण अनुभाग योजना मद-41 एवं योजना मद-42 के अंतर्गत मशीनों की खरीददारी करवाने की जिम्मेदारी निभाता है।

पिछले एक वर्ष में आधुनिकीकरण अनुभाग ने इलेक्ट्रिकल लोको के निर्माण में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्र एवं संयंत्र की खरीददारी की, जिससे इलेक्ट्रिक लोको के निर्माण एवं निरीक्षण की सुविधा विकसित की जा सकी जिनमें मुख्य यंत्र निम्नलिखित प्रकार हैं:-

- व्हील प्रेस, ट्रांसफॉर्मर ऑयल फिल्ट्रेशन सह सेंट्रीफ्युजिंग यूनिट, लूप बॉक्स और लॉजिक बॉक्स सेट, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पम्प के साथ डाईलेस इंडेंटिंग क्रिम्पिंग हेड एवं बैट्री चार्जर इत्यादि मुख्य हैं।
- इस प्रकार सेवा अभियांत्रिकी विभाग लोको निर्माण एवं अनुरक्षण प्रक्रिया को सुगम बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। ■

प्रदूषण रहित उच्च गुणवत्तायुक्त पर्यावरण के साथ संरक्षित कार्य प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध : डीरेका



श्री महेश कुमार
मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा सुनियोजित आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन का एक अंतर्निहित तत्व है। किसी भी निर्माण इकाई के लिए मुख्यत: दो प्रकार के अर्थात् जीवित एवं जड़ (डेड) संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक संरक्षा का विषय मूल रूप से जीवित संसाधनों, जैसे मानव (व्यक्ति) की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करने में सहायता प्रदान करना है।

डीरेका संरक्षा विभाग अपने दायित्वों एवं कार्य व्यवस्था के क्रम में निरंतर सतत् प्रयास के द्वारा नियमों/विनियमों का कार्यस्थल पर अनुपालन कराते हुए, संरक्षा संसाधनों की उपलब्धता और उनकी क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाता एवं इनकी नियमित मॉनीटरिंग भी करता है।

अग्नि आपात स्थितियों से निपटने के लिए डीरेका में दो बड़े फायर टेंडर तथा 20 आरपीएफ जवानों के साथ अपना एक विंग है, जिसके माध्यम से तुरंत ही डीरेका परिसर तथा आस-पास में होने वाली अग्नि आपात स्थितियों को नियंत्रित कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त परिसर में 64 फायर हाइड्रेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं, और 7 स्थानों पर लाखों लीटर पानी से भरे स्टेटिक टैंक को बनाए गए हैं, जिनमें 24 घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। कारखाने तथा कॉलोनी आदि में कुल 1,200 विभिन्न प्रकार के अग्निशमन यंत्रों को स्थापित किया गया है तथा सभी कर्मचारियों को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है।

कर्मचारियों के बीच संरक्षा को बढ़ावा देने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कर्मचारियों में उत्कृष्ट गुणवत्ता के पर्याप्त मात्रा में जोखिमों के अनुसार 37 प्रकार के व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरणों (पी.पी.ई.) की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा उनके उचित उपयोग हेतु समय-समय पर प्रशिक्षित भी किया जाता है। डीरेका कर्मचारियों, उनके परिजनों तथा आस-पास में रहने वाले लोगों के लिए भी संरक्षा विभाग डीरेका द्वारा समय-समय पर कई संरक्षा एवं पर्यावरण जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। संरक्षा विभाग, डीरेका ने विगत कुछ समय में कई नए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो निम्न हैं:

डीरेका ने इस वर्ष अपना एक आपदा प्रबंधन योजना को तैयार कर उसको लागू किया है, जिसकी एनडीआरएफ ने काफी प्रशंसा की है। भारतीय रेल में पहली बार इस आपदा प्रबंधन योजना को जापान के सेंड़ाई फ्रेम वर्क के अनुसार तैयार करते हुए, आपदा संबन्धित सभी पहलुओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इस पुस्तिका का विमोचन इस वर्ष अप्रैल, 2019 माह में महाप्रबंधक डीरेका द्वारा तथा वाराणसी के विभिन्न अंशधारकों की उपस्थिति में किया गया है।

गृह मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के तीन-तीन जिलों में विभिन्न आपदा प्रबंधन विषय पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को शामिल करते हुए एक "Mega Mock Exercise on Industrial Disaster including Earthquake" विषय पर ड्रिल का आयोजन किया जाए।

इस मेगा मॉक ड्रिल के लिए उत्तर प्रदेश के तीन जिले, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी को चिह्नित किया गया। गौरतलब है कि वाराणसी के औद्योगिक मंदिर, डीजल रेल इंजन कारखाना को इस मेगा अभ्यास के लिए प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव आने पर, डीरेका ने बखूबी इसकी महती जिम्मेदारी लेते हुए तथा सभी विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इसका सफलतम आयोजन इस उद्देश्य से किया कि यह ड्रिल न केवल डीरेका कर्मियों उनके परिजनों अपितु आस-पास रहने वाले सभी नगर वासियों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी।



संरक्षा विभाग, डीरेका ने बढ़-चढ़कर 18 अप्रैल,



राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं एनडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मॉक ड्रिल का एक दृश्य



डीरेका महिला कर्मचारियों को भी कार्डियो पल्मोनरी रीसुसाइटेशन पर एनडीआरएफ द्वारा प्रदर्शन और प्रशिक्षण दिया गया

2019 को डीरेका के विभिन्न अंशधारकों (संरक्षा विभाग, सिविल डिफेंस, स्काउट गाइड, सेंट जांस एंबुलेंस ब्रिगेड, आरपीएफ, फायर) के अतिरिक्त वाराणसी नगर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे, जिला एवं राज्य आपदा मोचन बल, जिला स्काउट गाइड एवं सिविल डिफेंस, जिला अस्पताल, अग्निशमन विभाग, जल निगम, शिक्षा विभाग आदि के साथ मिलकर इस मेगा मॉक अभ्यास का सफलतम आयोजन कराया।

डीरेका कर्मचारियों तथा कॉलोनी परिसर के लोगों के लिए संरक्षा विभाग, डीरेका ने आपदा प्रबंधन विषय पर जागरुकता बढ़ाने हेतु एनडीआरएफ तथा सीड्स एशिया, जापान के सहयोग से 16 नवम्बर, 2018 को डीरेका प्रेक्षागृह में एक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में एनडीआरएफ तथा सीड्स एशिया, जापान ने विभिन्न आपदाओं के नियंत्रण एवं बचाव से संबन्धित जानकारी दी तथा बढ़ते वायु प्रदूषण से होने वाले खतरों से सभी को अवगत कराते हुए उससे बचने के उपायों पर अच्छी जानकारी दी।

एनडीआरएफ के विशेषज्ञ ने कार्डियो पल्मोनरी रीसुसाइटेशन (सीपीआर) पर प्रदर्शन के माध्यम से जीवन बचाने के गुणों पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा उपस्थित प्रतिभागियों को सजीव प्रदर्शन के माध्यम से सीपीआर का प्रशिक्षण भी कराया।

डीरेका में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून, 2019 को संरक्षा विभाग द्वारा चार विशेष कार्यक्रमों (1) वृक्षारोपण (2) नाटक (3) सेमिनार एवं (4) पर्यावरण जागरुकता के तहत पम्पलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के क्रम में डीरेका में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सौ से अधिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ श्रीमती रश्मि गोयल, महाप्रबन्धक, डीरेका द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया।

पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए डीरेका में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा इंडस्ट्रियल इफ्लूएण्ट प्लांट भी मानक के साथ स्थापित है, जिससे आवासों तथा कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित पानी को शोधन करके ही बाहर छोड़ा जाता है। राष्ट्र में पर्यावरण संरक्षण में अधिक सहयोग के लिए डीरेका सोलर पैनलों तथा सोलर स्ट्रीट लाइटों का स्थापन करके सोलर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है।

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु संरक्षा विभाग निरंतर तत्पर रहते हुए हरित डीरेका के लिए कार्य कर रहा है। डीरेका पर्यावरण के लिए ग्रीनको प्रमाणित भी है, जिसमें डीरेका को सिल्वर प्रमाण पत्र से नवाजा गया है।

डीरेका कर्मचारियों को औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाने तथा उन्हें समय-समय पर जागरुक करने के लिए संरक्षा गोष्ठियों का आयोजन संरक्षा विभाग द्वारा किया जाता है।

संरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर नियमित प्रशिक्षण, काउंसलिंग, प्लांट संरक्षा निरीक्षण एवं ऑडिट किया जाता है। कारखाने में संरक्षा तैयारियों की क्रियाशीलता जाँचने के लिए नियमित तौर पर मॉक ड्रिल का आयोजन भी होता है, जिससे आपात परिस्थितियों से आसानी से निपटा एवं किसी संभावित क्षति से बचा जा सके। अंततः संरक्षा विभाग, अपने नियमित सकारात्मक प्रयासों से तथा कर्मचारियों की जागरुकता और अन्य विभागों के सहयोग से पूर्व में हो रही 39 दुर्घटनाओं में कमी लाते हुए 1 दुर्घटना तक आ पहुंचा है, जिससे कर्मचारियों में उत्साह तथा उनके मनोबल में बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही साथ, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीरेका की अच्छी छवि भी बनी है। ■



वायु प्रदूषण पर जागरुक करती हुईं सीड्स एशिया, जापान की सदस्या



नेत्र संरक्षा जागरुकता हेतु संरक्षा गोष्ठी

डीरेका : राजभाषा प्रगति के नए आयाम



श्री गिरिराज कुमार मीना
मुख्य राजभाषा अधिकारी

भारत का ही नहीं, दुनिया के सर्वाधिक प्राचीन एवं जीवंत शहरों में एक वाराणसी प्राचीन काल से ही धर्म, दर्शन एवं शिक्षा का केन्द्र रहा है। यहां एक तरफ जहाँ संत रविदास, संत कबीर ने ज्ञान की अलख जगाई वहीं दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की रसधारा बहाई। यही नहीं, यहां के हिंदी के साहित्यकारों, जैसे - भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रेमचन्द एवं जयशंकर प्रसाद आदि ने भी साहित्य जगत् में बनारस का नाम रौशन किया।

डीजल रेल इंजन कारखाना लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर रहा। आज डीरेका विद्युत इंजन के उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। डीरेका ने डीजल से विद्युत में परिवर्तित लोको के निर्माण का भी रिकॉर्ड कायम किया। डीरेका उत्पादन के क्षेत्र में नित नए रिकॉर्ड कायम करने के साथ ही सरकारी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में भी नित नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा है। आज डीरेका के सभी विभाग रेलवे बोर्ड तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेशों-अनुदेशों को क्रियान्वित कर रहे हैं। राजभाषा के प्रयोग-प्रसार से संबंधित डीरेका के विविध आयामों पर प्रकाश डालना प्रासंगिक होगा।

वेबसाइट - डीरेका संबंधी समस्त सूचनाएं इसकी वेबसाइट www.dlw.indianrailways.gov.in पर द्विभाषी रुप में उपयोगकर्त्ताओं के लिए उपलब्ध हैं।

तत्काल राजभाषा सेवा - दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग में सहयोग करने के लिए राजभाषा अनुभाग द्वारा यह सेवा उपलब्ध कराई गई है। डीरेका के अधिकारी एवं कर्मचारी वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी अथवा राजभाषा अनुभाग के माध्यम से अंग्रेजी/तकनीकी शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची या अनुवाद जानने के लिए इस सेवा का उपयोग करते हैं।

कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय एवं वाचनालय - प्रशासन भवन में 8,552 पुस्तकों, अनेक विधा की 44 पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से युक्त एक कंप्यूटरीकृत 'प्रेमचंद हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय' है। इसकी सभी पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से सर्च किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय चिकित्सालय परिसर में 'संत कबीर पुस्तकालय-सह-वाचनालय' स्थापित है।

तकनीकी एवं साहित्यिक गोष्ठियों तथा समारोहों का आयोजन - तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने तथा प्रेरक वातावरण बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर तकनीकी गोष्ठियां, महापुरुषों एवं साहित्यकारों की जयंतियां, विचार गोष्ठियां, कवि सम्मेलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 6 सितम्बर, 2018 को 'संरक्षा' विषय पर, 4 दिसम्बर, 2018 को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग को तिमाही प्रगति रपट के प्रेषण विषय पर, 19 मार्च, 2019 को डीजल से विद्युत इंजन के निर्माण के सिद्धान्त विषय पर तथा 10 जून, 2019 को अनुरक्षण विषय पर कर्मशाला परिसर/कार्यालयों एवं प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र में कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों के बीच तकनीकी गोष्ठी का आयोजन किया गया।



डीजल से विद्युत इंजन के निर्माण पर तकनीकी गोष्ठी का दृश्य

हिंदी सप्ताह का आयोजन - डीरेका में 'हिंदी सप्ताह' समारोह का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है। इस दौरान हिंदी कार्यशाला, तकनीकी गोष्ठी, विचार गोष्ठी, क्विज एवं 'हिंदी दिवस' के उपलक्ष्य में 'संगोष्ठी आदि का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉ. रामकीर्ति शुक्ल ने 'हिंदी भाषा और हमारा समाज' विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया।

प्रतियोगिताओं का आयोजन - हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से वर्ष पर्यंत निबंध लेखन, वाक् एवं टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन



नराकास की छमाही बैठक में श्रीमती रश्मि गोयल, अध्यक्ष नराकास से पुरस्कार प्राप्त करते मुख्य राजभाषा अधिकारी, डीरेका



राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के अवसर पर डीरेका दर्पण का लोकार्पण करती हुईं श्रीमती रश्मि गोयल, महाप्रबंधक, डीरेका

प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को अखिल रेल स्तर पर आयोजित उक्त प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए भेजा जाता है।

प्रोत्साहन योजनाएं – राजभाषा का प्रयोग-प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, जैसे अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना, सरकारी काम-काज मूलरूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना और राजभाषा सामूहिक पुरस्कार योजना तथा साहित्य सृजन एवं तकनीकी पुस्तक लेखन के लिए मैथिलीशरण गुप्त, प्रेमचंद, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजनाएं भी लागू हैं।

पत्रिका का प्रकाशन – तकनीकी, सामयिक, साहित्यिक रचनाओं के सृजन के लिए डीरेका कर्मियों को प्रेरित करने एवं संगठन की उत्कृष्ट छवि प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अर्द्धवार्षिक पत्रिका 'डीरेका दर्पण' का नियमित प्रकाशन किया जाता है।

हिंदी कार्यशाला का आयोजन – समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन कर कर्मचारियों में राजभाषा नीति-नियमों के प्रति जागरुकता लाई जाती है। इससे उन्हें रोजाना के सरकारी कार्यों के साथ-साथ विभागीय परीक्षाओं में भी सुविधा मिलती है। विशेष अभियान के तहत विगत वर्ष यांत्रिक, कार्मिक एवं लेखा विभाग के लिए गहन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

निरीक्षण – राजभाषा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न विभागों में निरीक्षण करके राजभाषा के प्रयोग-प्रसार की स्थिति का जायजा लिया जाता है और राजभाषा संबंधी नीति-नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को कार्यस्थल पर ही दूर करने का प्रयास किया जाता है। 26 फरवरी, 2019 को श्री एस.पी. माही, कार्यपालक निदेशक/स्थापना (आर), रेलवे बोर्ड ने कार्यालय एवं कारखाना परिसर का निरीक्षण किया और डीरेका में राजभाषा के प्रयोग की सराहना की।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में राजभाषा – डीरेका में पहलकदमी करते हुए प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा संचालित प्रमुख पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में 'राजभाषा हिंदी-नीति एवं नियम' विषय भी शामिल कराया गया है, जिससे सभी कर्मचारियों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के दौरान अन्य विषयों के साथ-साथ राजभाषा संबंधी विषयों की जानकारी भी दी जाती है। इसके अलावा यूनिकोड की जानकारी तथा कंप्यूटर में 'यूनिकोड का इंस्टालेशन एवं वर्ड, एक्सल, पावर पॉइंट पर हिंदी में यूनिकोड के माध्यम से लिखना' विषय पर प्रशिक्षण की सुविधा भी मुहैया कराई गई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को की-बोर्ड एवं यूनिकोड का प्रशिक्षण दिया जाता है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति – गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का दायित्व डीरेका के महाप्रबंधक को तथा इसके संचालन का दायित्व राजभाषा विभाग को सौंपा गया है। इस समिति की बैठक हर छमाही में आयोजित की जाती है। इस प्रकार डीरेका नगर के कार्यालयों के बीच में राजभाषा के प्रयोग-प्रसार हेतु समन्वय कार्य भी करता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि विविध प्रकार की गतिविधियों द्वारा डीरेका, राजभाषा के विकास के लिए चहुँमुखी प्रयास कर रहा है। तकनीकी क्षेत्रों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एवं तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन



हिंदी कार्यशाला की एक झलक

को प्रोत्साहित करने के लिए डीरेका ने तकनीकी गोष्ठियों के आयोजन पर विशेष बल दिया है, साथ ही कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक बैठक में विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय विषयों पर हिंदी में प्रस्तुतिकरण का अभिनव प्रयास शुरू किया है। उदाहरण के लिए, 12 जून, 2019 को श्री अनिल कुमार सिंघल, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर द्वारा 'सौर ऊर्जा' विषय पर, डॉ. देवेश कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 27 जून, 2019 को 'जीवनशैली जनित बीमारियों एवं उनकी रोकथाम' विषय पर, 25 अक्टूबर, 2018 को श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा 'कार्मिक विभाग : कल्याणकारी योजनाएँ' विषय पर महाप्रबंधक महोदया की उपस्थिति में प्रस्तुतियां दी गई।

डीरेका में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं अन्य गतिविधियों के दौरान हमने यह महसूस किया है कि अभी भी राजभाषा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना है। सतत् प्रयासों के द्वारा आज कंप्यूटर में यूनिकोड जैसी सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे पर्सनल कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन आज का समय सूचना प्रबंधन प्रणालियों का है। किसी भी विभाग या संगठन के सभी कार्य एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से संपन्न किए जा रहे हैं। इन प्रबंधन प्रणालियों में राजभाषा हिंदी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना आवश्यक है। इसमें सफलता मिलने पर हिंदी के प्रयोग में स्वचालित ढंग से अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

हालांकि अब रेलवे के अधिकारी विशिष्ट विषयों पर हिंदी में पुस्तकें लिख रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। रेलवे के अधिकारी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। यदि विभिन्न तकनीकी विषयों पर वे मौलिक रुप से हिंदी में पुस्तकें लिखें तो यह न सिर्फ राजभाषा की, अपितु देश की भी सेवा होगी। अपनी भाषा में तकनीकी साहित्य के अभाव में आज तमाम लोग तकनीकी ज्ञान से वंचित हैं।

हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश की विशिष्ट पहचान तभी बनेगी और यह दुनिया का नेतृत्व तभी कर सकेगा, जब ज्ञान-विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में हम हिंदी सहित भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाएंगे। बाजार की दृष्टि से भी मौलिक उत्पादन ही मूल्यवान होते हैं। इसलिए ज्ञान के उच्चतम क्षेत्रों में हमें अनुवाद एवं अनुकरण से बचते हुए मौलिक, सृजनशील कार्य अपनी भाषा में प्रस्तुत करने होंगे।

हमारा पूरा विश्वास है कि इन क्षेत्रों में संकल्पबद्ध होकर, काम करके हम हिंदी सहित भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ाएंगे ही, दुनिया के देशों में भारत के मौलिक ज्ञान को भी प्रतिष्ठित करेंगे। ■

डीरेका में विपणन विभाग का क्रिया-कलाप एवं उपलब्धियाँ



श्री वाई. बी. शहारे
मुख्य विपणन प्रबन्धक

डीजल रेल इंजन कारखाना (डीरेका) आज विश्व की एक ऐसी उत्पादन इकाई है, जो कि डीजल रेल इंजन के निर्माण के साथ-साथ इलेक्ट्रिक लोको का भी निर्माण एक ही छत के नीचे कर रही है तथा नित नए कीर्तिमान स्थापित कर देश को गौरवान्वित कर रही है। इस कारखाने ने अपनी यात्रा वर्ष 1964 में 4 डीजल रेल इंजन के निर्माण से शुरू की थी और आज इस इकाई में लगभग 330 लोको प्रति वर्ष के हिसाब से उत्पादन हो रहा है। इस कारखाने के द्वारा निर्मित रेल इंजनों को भारतीय रेल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्षेत्रीय रेलों को सप्लाई के साथ-साथ गैर-रेलवे ग्राहकों (देशी तथा विदेशी) को भी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण कर आपूर्तित किए जाते हैं।

डीरेका मार्केटिंग विभाग की स्थापना अगस्त, 1987 को गैर-रेलवे ग्राहकों को लोकोमोटिव, डीजी सेट एवं स्पेअर्स की सेल तथा सेल के उपरान्त सभी प्रकार की सर्विस के लिए सिंगल विंडो के रूप में हुआ था। मार्केटिंग विभाग में बहु-विषयक अधिकारियों की टीम है जो कि गैर-रेलवे ग्राहकों को शुरू से अर्थात टेंडरिंग स्टेज से ही तकनीकी एवं कॉमर्सियल जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ सभी विभागों से समन्वय करके उनकी जरुरत के मुताबिक लोको, डीजी सेट इत्यादि डिजाइन करा कर डीरेका कारखाने में उत्पादन कराकर डिस्पैच कराते हैं। तदुपरान्त कस्टमर की फील्ड साइट पर लोको या डीजी सेट की कमीशनिंग भी कराते हैं तथा कमीशनिंग के उपरान्त उनके सुचारु रूप से कार्य करते रहने के लिए आवश्यक स्पेअर्स देने की भी सेवा प्रदान करते रहते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट आर्डर्स के लिए राइट्स एवं इरकॉन से आवश्यक समन्वय बनाए रखते हैं तथा विदेशी ग्राहकों की जरुरत के मुताबिक डीरेका डिजाइन विभाग एवं आरडीएसओ इत्यादि से समन्वय कर लोको डिजाइन कराना, उनके लिए पुर्जों की खरीददारी कराकर निर्माण कर विदेशों के लिए राइट्स अथवा इरकॉन के माध्यम से लोको डिस्पैच से लेकर कमीशनिंग कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसी क्रम में मोजाम्बिक रेलवे से 5 अदद 3,000 अश्वशक्ति के कैप गेज लोको की वार्ता राइट्स के माध्यम से अन्तिम दौर में चल रही है, जिसके तहत मोजाम्बिक रेलवे के अधिकारियों ने डीरेका भ्रमण 7 मार्च, 2019 को किया तथा विजिट के पश्चात् डीरेका के क्रिया-कलापों से यह काफी प्रभावित एवं संतुष्ट थे।

- डीरेका से अब तक कुल 165 डीजल रेल इंजन 11 विभिन्न देशों को निर्यात किए गए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है।

देश	मध्यस्त	निर्यात किए गए लोको			
देश	मध्यस्त	लोको के प्रकार	वर्ष	अश्व शक्ति	मात्रा
तंजानिया		वाईडीएम$_4$	1975-78	1350	15
वियतनाम		वाईडीएम$_4$	1983-84(15) 2002-03(10)	1350	25
बांग्लादेश	राइट्स	वाईडीएम$_4$	1995-97	1350	10
	राइट्स	डब्ल्यूडीएम$_2$ (बीजी)	2000-04	2600	13
	राइट्स	बीजी-बीआर 6500 (बीजी)	2012-14	3100	26
श्रीलंका	राइट्स	डब्ल्यूडीएम$_2$ (बीजी)	1995-2002	2600	08
	राइट्स	एसएलएम-एम10 (बीजी)	2011-12	2300	03
	इरकॉन	एसएलआर-एम10ए (बीजी)	2012-13	2300	03
			2013-14	2300	03
	राइट्स	एसएलआर-एम11 (बीजी)	2018-19	3000	03
	राइट्स	एसएलआर-एम11 (बीजी)	2019-20	3000	07
पीसीसीएल, श्रीलंका	राइट्स	डब्ल्यूडीएम6 (बीजी)	1997-98	1350	01
मलेशिया	इरकॉन	12 सीवाईएल (एमजी)	2001-02	2300	01
सूडान	राइट्स	वीडीएम4 (सीजी)	2005-06	1350	03
	राइट्स	2300 एचपी (सीजी)	2006-07	2300	05
अंगोला	राइट्स	वीडीएम4 (सीजी)	2006-07	1350	01
	राइट्स	2300 एचपी (सीजी)	2006-07	2300	02
म्यांमार	राइट्स	वाईडीएम4	2005-06	1350	11
सेनेगल/माली	राइट्स	2300 एचपी (एमजी)	2007-08	2300	04
मोजाम्बिक	राइट्स	3000 एचपी (सीजी)	2008-09	3100	01
				कुल	165



श्रीलंका को 3,000 एचपी एसी-एसी बी.जी. लोको निर्यात किया गया



म्यांमार को 1,350 एचपी वाईडीएम4 लोको निर्यात किया गया



मोजाम्बिक से प्रतिनिधियों का डीएलडब्ल्यू दौरा

- डीरेका द्वारा देशीय गैर-रेलवे ग्राहकों को अब तक लगभग 611 लोको निम्नलिखित विवरण के अनुसार आपूर्तित किए हैं।

ग्राहक का नाम	लोको का प्रकार	मात्रा	कुल
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	डब्ल्यूडीएस$_6$	211	212
	डब्ल्यूडीजी$_{3ए}$	01	
वीएसपी	डब्ल्यूडीएस$_6$	37	37
एनटीपीसी	डब्ल्यूडीएस$_6$	18	192
	डब्ल्यूडीएम$_2$	42	
	डब्ल्यूडीजी$_{3ए}$	132	
पोर्ट ट्रस्ट	डब्ल्यूडीएस$_6$	32	44
	डब्ल्यूडीजी$_{3ए}$	12	
स्टेट विद्युत बोर्ड	डब्ल्यूडीएम$_2$	11	31
	डब्ल्यूडीजी$_{3ए}$	05	
	डब्ल्यूडीएस$_6$	12	
	डब्ल्यूडीजी$_{4डी}$	03	
अन्य (डीआरडीओ-1, एचएफसी/नामरूप-2, नालको-3, टिस्को-11, एनएमडीसी-5, बीसीसीएल-2, एनआईएनएल-21, एनएसपीसीएल-1, बीएमएमआईएल-1, लानको-3, आर्सिया-1, वेदांत-3, जेपी सीमेंट-1, जेएसडब्ल्यू-7, बीवीएफसीएल01, आईएनडी बीएआरएटीएच-1, अदानी-7 एवं राइट्स/आरईएस-22	डब्ल्यूडीएस$_6$	74	95
	डब्ल्यूडीजी$_{3ए}$	20	
	वाईडीएस$_4$	01	
		कुल	611



गैर रेलवे ग्राहक के लिए डब्ल्यूडीजी3ए 3100 एचपी लोको



एनआरसी के लिए डब्ल्यूडीएस6एडीटी 1350 एचपी लोको

- डीरेका ने देशीय रेलवे एवं गैर-रेलवे ग्राहकों को अब तक 62 डीजी सेट निम्नलिखित विवरण के अनुसार आपूर्तित किए हैं।

ग्राहक का नाम	क्षमता (किलोवॉट)	वर्ष	कुल
एमएपीपी, मद्रास	1400-1750	1975-1990	10
एनएपीपी, नरोरा	1750	1988-1990	6
आइसीएफ, मद्रास	1750	1977-83	2
पीसीएल, बरोड़ा	1750	1977	1
सीएलडब्ल्यू	1750	1977-1992	5
डीएलडब्ल्यू	850-2400	1975-2013	4
ईआर, कचड़ापाड़ा	1750	1977-1983	2
ईआर, जमालपुर	1750-2400	1977-2018	4
एनआर, एलकेओ	1750	1979-83	3
एसईआर, खड़गपुर वर्कशॉप	1750	1982-1992	4
आरडब्ल्यूएफ	1750	1982-2011	3
सीआर, झांसी डब्ल्यू/एस	1750	1983	1
एनईआर, जीकेपी डब्ल्यू/एस	1750	1983	1
डब्ल्यूआर, अजमेर डब्ल्यू/एस	1750	1984	1
एनआर, जगाधरी	1750	1985	1
एनपीसीएल, कैगा एवं रावभट्टा	2400	2005-2007	12
सीडब्ल्यूपी, बेला/छपरा	2400	2010	2
		कुल	62

- उपरोक्त सभी लोको एवं डीजी सेट की कार्य क्षमता से गैर रेलवे ग्राहक सन्तुष्ट हैं तथा यह ग्राहक सन्तुष्टि का ही परिणाम हैं कि लगातार क्रय आदेश डीरेका को दे रहें हैं। ■



2.4 मेगावाट का डीजी सेट

डीरेका में विद्युत लोको का विकास



श्री सुजीत मिश्रा
मुख्य अभिकल्प अभियंता/
विद्युत लोको

बात वर्ष 2016 की है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के आठवें दौरे पर वाराणसी आए थे और इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सात योजनाओं का शुभारंभ किया था। इन सात योजनाओं में एक योजना थी, डीजल रेल इंजन कारखाना का विस्तारीकरण, जिसमें उन्होंने अपने मुख आभा से एक बात कही थी, "जब डीजल रेल इंजन कारखाना डीजल इंजन बना सकता है तो विद्युत इंजन क्यों नहीं?" अब फिर क्या... डीजल रेल इंजन कारखाना, जिसकी विशेष बात यह थी कि यह प्रति कार्य दिवस में एक डीजल रेल इंजन का निर्माण कर देश को समर्पित करता था। डीजल रेल इंजन कारखाना अपने समस्त कर्मचारी वृन्द के साथ विद्युत इंजन के निर्माण में तल्लीन हो गया और देखते-ही-देखते वह दिन भी आ गया जब डीरेका निर्मित प्रथम विद्युत रेल इंजन राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हो गया और हम समस्त डीरेका कर्मी इसके साक्षी थे।



अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की उपस्थिति में डीरेका निर्मित विद्युत इंजन का लोकार्पण

डीजल रेल इंजन की तुलना में विद्युत रेल इंजन के फायदे

वर्तमान से कुछ समय पहले डीजल रेल इंजन कारखाना, डीजल इंजनों के निर्माण का कार्य कर रहा था, किन्तु अध्ययन बताते हैं कि डीजल से होने वाले उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण तत्वों में सबसे खराब है। डीजल वाहन बड़े पैमाने में नाइट्रोजन डाईऑक्साइड छोड़ते हैं जो दमा, ब्रोंकाइटिस, दिल के दौरे और अन्य बीमारियों के कारक हैं। डीजल में मौजूद सल्फर, सल्फर डाईऑक्साइड का निर्माण करती है जो नाक, गले, साँस की नली में दिक्कतें पैदा करती है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार, पिछले साल के चार सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों में चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ के बाद भारत (सात फीसदी) हैं। भारत के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने वर्ष 2021-22 तक भारतीय रेल की ब्रॉड गेज लाइनों के सौ प्रतिशत विद्युतीकरण को मंजूरी दे दी है। भारतीय रेल का सौ फीसदी विद्युतीकरण जीवाश्म ईंधनों (डीजल) के प्रयोग में कमी लाएगा यह कमी 2.83 बिलियन लीटर प्रति वर्ष होगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। विद्युत रेल इंजन विद्युत मोटरों की उच्च दक्षता से लाभान्वित होते हैं। रेलगाड़ी में ब्रेकिंग के दौरान पुनर्योजी ब्रेकिंग से अतिरिक्त दक्षता प्राप्त की जा सकती है। डीजल इंजनों की तुलना में इलेक्ट्रिक इंजन कम ध्वनि प्रदूषण वाले और इनका जीवनचक्र लागत कम होता है।

विद्युत इंजन के निर्माण के दौरान आने वाली चुनौतियाँ

डीजल इंजनों से होनेवाले नुकसान को देखते हुए, भारत सरकार, रेल मंत्रालय की तरफ से डीजल रेल इंजन कारखाने को यह निर्देश मिला कि आप विद्युत इंजनों का निर्माण कार्य पर जोर दीजिये। इसके बाद यहाँ के कर्मचारी आवश्यकतानुसार समय-समय पर चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना जाकर वहाँ से तकनीकी ज्ञान लिए और लोको के निर्माण कार्य में लग गये। कुछ परेशानियाँ आईं, कुछ कठिनाइयां आईं, लेकिन प्रधानमंत्रीजी की तीव्र इच्छा शक्ति एवं डीरेका के कर्मठ कर्मचारियों के उत्साह और जुनून के आगे ये टिक न सकीं और वह दिन आ गया जब पहला विद्युत रेल इंजन बनकर राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हो गया।

जब विद्युत रेल इंजन, डीरेका में बनने लगे तो सामानों के आपूर्तिकर्ता सामानों को समय से उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे जिससे लोको को नियत समय में निर्मित करना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई थी। इसके अतिरिक्त डीरेका में विद्युत लोको बनने लगा तो उनके निरीक्षण टेस्टिंग के लिए लोको को मुगलसराय शेड में भेजा जाता था जिसके कारण लोको का सम्पूर्ण निर्माण समय बढ़ जाता था। समय बीतता गया और धीरे-धीरे डीरेका में शिरोपरी विद्युत तार बिछा दिए गए और लोको का (टेस्टिंग) निरीक्षण भी डीरेका में ही होने लगा और दिन प्रतिदिन विद्युत लोको उत्पादन बढ़ने लगा। वर्ष 2016-2017 में डीरेका निर्मित विद्युत लोको की संख्या 2 थी, जो 2017-18 में बढ़कर 25 हो गई, 2018-2019 में यह संख्या बढ़कर 145 हो गई एवं वर्ष 2019-20 में अभी तक (अक्टूबर, 2019) कुल 147 विद्युत इंजन के निर्मित किए जा चुके हैं। ■

डीरेका द्वारा निर्मित विद्युत रेल इंजन :-

लोको के प्रकार	डीरेका में निर्मित लोको
डब्ल्यूएपी-7	301
डब्ल्यूएजी-9एच	18
डब्ल्यूएजीसी-3	1
डब्ल्यूएजी-11	1

जन सम्पर्क विभाग : एक मिशन



श्री नितिन मेहरोत्रा
मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी

जन सम्पर्क एक प्रबंधकीय कार्य है, जिसमें लोक व्यवहार की परिवीक्षा और मूल्यांकन के साथ-ही-साथ किसी संगठन और उसके लोगों से पारस्परिक संबंधों की समझ तथा उसे बनाए रखना शामिल है। जहाँ तक 'जन' लोग अथवा जनसामान्य का प्रश्न है, उसमें अंशधारक, सरकार, उपभोक्ता, ग्राहक, कर्मचारी और मीडिया को शामिल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत उन लोगों से संपर्क बनाए रखना है, जो लगातार हमसे जुड़े होते हैं।

सामान्यत: जन सम्पर्क अधिकारी/मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी प्रबंध तंत्र और कर्मचारियों के बीच एक सुस्पष्ट संचार संजाल बनाए रख संगठन में आंतरिक संबद्धता सुनिश्चित करते हैं। इनका पहला लक्ष्य संप्रेषण माध्यमों को सुधारना और सूचनाओं तथा समझ के दोनों दिशाओं में प्रवाह के लिए एक नई राह स्थापित करना है।

डीरेका का जन सम्पर्क विभाग भारतीय रेल एवं डीरेका की छवि निर्माण, जननीति एवं इससे जुड़ी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार उपलब्ध संसाधनों एवं विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा करता है। जन सम्पर्क विभाग विभिन्न गतिविधियों द्वारा जनता से सम्पर्क स्थापित करता है, जिसमें प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलन, पुस्तकें, बैनर, पोस्टर, छायाचित्र, विज्ञापन, विरासत दीर्घा, एसएमएस अभियान, वेबसाइट, सोशल मीडिया इत्यादि माध्यम शामिल हैं।

डीरेका में रेलवे बोर्ड स्तर के साथ-ही-साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी जन सम्पर्क प्रणाली स्थापित है।

जन सम्पर्क विभाग के कार्य

- डीरेका एवं भारतीय रेल से सम्बंधित तथ्यपरक सूचनाओं को शीघ्र एवं समयबद्ध तरीके से जनता तक पहुँचाना।
- विभिन्न विभागों में अर्जित उपलब्धियों को समायोजित कर विशेष लेख के रूप में प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करते हुए विभिन्न समाचार-पत्रों को प्रेषित करना।
- विज्ञापनों एवं अन्य माध्यमों से उत्पादन से संबंधित सूचनाएँ जारी करना।
- प्रधानमंत्री, रेल मंत्री एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन एवं उनके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन, नवीन प्रकार के रेल इंजनों के लोकार्पण आदि कार्यक्रम के दौरान इवेंट प्रबंधन का कार्य।
- विभिन्न अवसरों, जैसे - स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, रेल सप्ताह इत्यादि का आयोजन एवं सफलतापूर्वक संचालन।
- विरासत का संकलन एवं संरक्षण।
- उत्पादन इकाई होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यशाला एवं कार्यालय परिसर में आने-जाने वाले आगंतुकों, वेंडरों, विदेशी नागरिकों एवं अन्य रेलवे से पधारे अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए गेटपास जारी कर उन्हें नियंत्रित करना।
- गृह पत्रिका 'संवाद', महाप्रबंधक वार्षिक रिपोर्ट, ब्रोशर, पुस्तकें आदि की डिजाइनिंग एवं प्रकाशन।
- विभिन्न विभागों से प्राप्त निविदा सूचनाओं को रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से डीएवीपी दरों से जारी करना।
- वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण यहां के जन सम्पर्क विभाग का दायित्व और भी चुनौतीपूर्ण एवं विस्तृत हो गया है। समय-समय पर प्रधानमंत्री एवं अन्य विशिष्ट जनों के आगमन पर जिला प्रशासन के साथ तालमेल स्थापित करते हुए आपसी सहयोग से महानुभावों की यात्रा को सफलतापूर्वक सुरक्षित एवं सकुशल सम्पन्न कराने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
- विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेकर डीरेका की उपलब्धियों एवं कार्यकलापों को जन-जन तक प्रचारित-प्रसारित करना।
- डीरेका प्रशासनिक भवनों एवं अन्य प्रमुख स्थलों पर डीरेका के क्रियाकलापों का इतिहास से संबंधित छायाचित्रों का प्रदर्शन।

डीरेका जन सम्पर्क विभाग ने भारतीय रेल एवं विशेष रूप से डीरेका की छवि निर्माण का हर सम्भव प्रयास किया तथा राष्ट्रीय प्रेस, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं उपलब्ध मीडिया का भरपूर उपयोग किया। वर्ष 2019 में अक्टूबर तक डीरेका के प्रमुख कार्यकलापों से संबंधित लगभग 99 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर डीरेका के क्रियाकलापों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

वर्ष 2019 के दौरान अनेकानेक विशिष्ट व्यक्तियों ने डीरेका का भ्रमण किया एवं डीरेका द्वारा विविध प्रशासनिक समारोह आयोजित किए गए, जिनका महाप्रबंधक श्रीमती रश्मि गोयल के कुशल मार्गदर्शन में जन सम्पर्क विभाग द्वारा कवरेज किया गया। कुछ विशेष कार्यक्रमों का तिथिवार विवरण निम्नलिखित है :-

- 7 जनवरी को श्री घनश्याम सिंह, सदस्य कर्षण, रेलवे बोर्ड द्वारा डीरेका निर्मित 100वें विद्युत रेल इंजन डब्ल्यूएपी-7 'शतक' को जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले उत्पादन से जुड़े डीरेका के सात कर्मचारियों के साथ झंडी दिखाकर लोकार्पित किया गया।



- 8 फरवरी को श्री विनोद कुमार यादव, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड द्वारा फरवरी में सेवानिवृत्त होने वाले उत्पादन से जुड़े डीरेका के छह कर्मचारियों के साथ एक 6,000 अश्व शक्ति के



विद्युत रेल इंजन 'डब्ल्यूएपी7' एवं गैर रेलवे ग्राहक को प्रेषण हेतु एक 3,100 अश्व शक्ति के डीजल रेल इंजन 'डब्ल्यू डीजी3ए' का लोकार्पण किया गया।

- 19 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दुनिया का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तित 10,000 अश्व शक्ति का ट्विन रेल इंजन डब्ल्यूएजीसी3 राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ, रेल राज्यमंत्री एवं संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनोज सिन्हा एवं संसद सदस्य चन्दौली डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय उपस्थित थे।



- 14 एवं 15 मार्च को आयोजित डीरेका में दो दिवसीय सतर्कता कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक में प्रमुख मुख्य कार्यकारी निदेशक (सतर्कता), रेलवे बोर्ड श्री रमेश कुमार झा, रेलवे बोर्ड के सभी कार्यकारी निदेशक व उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे एवं आरडीएसओ के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक सह मुख्य सतर्कता अधिकारी ने भाग लिया।



- 18 अप्रैल को डीरेका संरक्षा अनुभाग एवं 11वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के संयुक्त तत्वावधान में डीरेका प्रेक्षागृह (सिनेमा हॉल) में मेगा मॉक ड्रिल 'सक्षम' का आयोजन किया गया। इस व्यापक मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में डीरेका कर्मियों के अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा, जिला प्रशासन, पुलिस, फायर सर्विस, ट्रैफिक पुलिस, होम गार्ड, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों ने भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के उप महानिरीक्षक श्री आलोक कुमार सिंह, वाराणसी के जिलाधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द कुलकर्णी सहित डीरेका एवं वाराणसी शहर के प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।



22 मई को डीरेका सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा उत्तर मध्य रेलवे (प्रयागराज), पूर्वोत्तर रेलवे (गोरखपुर) व केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन (प्रयागराज) के सहयोग से स्थानीय प्रेक्षागृह (सिनेमा हॉल) में आपूर्तिकर्ता सम्मेलन (वेंडर मीट)-2019 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सदस्य/सामग्री प्रबंधन श्री वी.पी. पाठक, प्रमुख कार्यकारी निदेशक, रेलवे भंडार श्री वी.के. श्रीवास्तव सहित श्री आर.के. यादव, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, श्री पी.एन. पाण्डेय, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, प्रयागराज, श्री कमलेश शुक्ला, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, प्रयागराज तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ही साथ बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं रेलवे से जुड़े फर्म के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।



- 28 एवं 29 जून को डीरेका कीर्ति कक्ष (हॉल ऑफ फेम) में क्षेत्रीय रेलों की वर्ष 2021-22 के लिए रेल इंजनों के अतिरिक्त पुर्जों की वार्षिक मांग संबंधी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य/विद्युत श्रीमती मंजू गुप्ता द्वारा संबोधन किया गया। इस दो दिवसीय बैठक में क्षेत्रीय रेलों से अतिरिक्त पुर्जों की मांग के



एकत्रीकरण के साथ ही रेल इंजनों के पुर्जों की आपूर्ति से संबधित विभिन्न तकनीकी विषयों एवं इनके वारण्टी क्लेम्स पर भी चर्चा की गई।

- 9 जुलाई को श्री विनोद कुमार यादव, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधक सभा कक्ष में कर्मचारी परिषद् एवं अन्य कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजीव अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।



- 2 एवं 3 अगस्त को डीरेका में क्षेत्रीय रेलों के लिए विद्युत रेल इंजनों की मांग, रख-रखाव, विश्वसनीयता के मुद्दे पर चर्चा हेतु 'कस्टमर मीट-2019' का आयोजन किया गया। बैठक के समापन पर रेलवे बोर्ड की अपर सदस्य/एल श्रीमती मंजू गुप्ता द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए।



- 10 अगस्त को श्री विजय कुमार, वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड द्वारा डीरेका में विद्युत रेल इंजन 'डब्ल्यूएपी-7' को झंडी दिखाकर लोकार्पित किया गया। इसके उपरान्त उन्होंने प्रमुख अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।



- 19 सितम्बर को रेल राज्यमंत्री श्री सुरेश अँगडी द्वारा 275वें विद्युत रेल इंजन डब्ल्यूएपी-7 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।

- 20 एवं 21 सितम्बर को अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के सहयोग से भारतीय रेल की 63वें इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्डस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में सदस्य कर्षण श्री राजेश तिवारी एवं अपर सदस्य/एल श्रीमती मंजू गुप्ता ने भी विचार व्यक्त किए।



- 2 अक्टूबर को महाप्रबंधक श्रीमती रश्मि गोयल द्वारा डीरेका निर्मित 300वें विद्युत रेल इंजन डब्ल्यूएपी-7 को झंडी दिखाकर लोकार्पित किया गया।

इस वर्ष पुष्प प्रदर्शनी, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, राजभाषा पखवाड़ा, सतर्कता जागरुकता सप्ताह, राष्ट्रीय एकता दिवस इत्यादि अवसरों पर जन सम्पर्क टीम ने पूर्ण तन्मयता के साथ योगदान दिया।

इसके अतिरिक्त जन सम्पर्क विभाग द्वारा इस वर्ष निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया गया :-

- 18 से 27 फरवरी तक आगरा, उत्तर प्रदेश में आयोजित 'ताज महोत्सव' में भाग लिया।
- 8 से 10 मार्च तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित 'TECHNEX'19' में भाग लिया।
- 21 से 23 जुलाई तक 64वें केन्द्रीय रेल सप्ताह समारोह के अंतर्गत सनातन धर्म कॉलेज, अम्बाला, हरियाणा में आयोजित रेल प्रदर्शनी एवं मेले में भाग लिया। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा रेल राज्यमंत्री श्री सुरेश अँगडी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव एवं अन्य सदस्यगणों की उपस्थिति में डीरेका की महाप्रबंधक श्रीमती रश्मि गोयल को रेल मंत्री द्वारा जारी प्रशंसा-पत्र प्रदान किया गया। यह प्रशंसा-पत्र विश्व में प्रथम उच्च अश्व शक्ति के डीजल से विद्युत में परिवर्तित रेल इंजन के निर्माण के सराहनीय कार्य हेतु प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी के समापन पर आकर्षक मंडप सज्जा हेतु डीरेका को भारतीय रेल की उत्पादन इकाई की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- 22 से 24 अक्टूबर तक एरोसिटी, नई दिल्ली में आयाजित 13वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपस्कर प्रदर्शनी में भाग लिया

डीरेका के जन सम्पंर्क विभाग ने अपने कुशल समयबद्ध प्रबंधन के माध्यम से एक सुस्पष्ट वातावरण बनाए रखा है। यह विभाग संगठन में आंतरिक एवं बाह्य संबद्धता सुनिश्चित करने एवं लक्ष्य निर्धारण करने में संप्रेषण माध्यमों का भरपूर उपयोग कर रहा है और सूचनाओं तथा समझ के दोनों दिशाओं में प्रवाह के लिए प्रतिबद्ध भी है। ■

प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र, डीरेका : एक परिचय



श्री रामजन्म चौबे
प्राचार्य

डीरेका में प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 2 फरवरी, 1959 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री वी.वी. गिरि द्वारा की गयी। अत: प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र, डीरेका की स्थापना के पूर्व से ही प्रशिक्षण के माध्यम से डीजल रेल इंजन कारखाना में निरंतर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

डीरेका में उत्पादन की आवश्यकतानुसार प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों, जैसे फिटिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि विषयों में डीरेका के कर्मचारियों एवं अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उच्च अश्वशक्ति के रेल इंजनों तथा आधुनिक विद्युत इंजनों के प्रशिक्षण तथा निर्माण प्रक्रिया में यह केंद्र निरंतर अपना योगदान बनाए हुए है।

मुख्य गतिविधियाँ

- डीरेका के कर्मचारियों के लिए आंतरिक एवं अन्य बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- विभिन्न कोटियों, जैसे रेल भर्ती बोर्ड, अनुकंपा, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं पदोन्नति के अंतर्गत नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- अन्य क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों से आने वाले प्रोबेशनर्स, अधिकारियों, पर्यवेक्षकों एवं तकनीशियनों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- डिप्लोमा एवं डिग्री इंजीनियरिंग छात्रों को ग्रीष्मकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण कराना।
- स्थानीय नवयुवकों/नवयुवतियों को 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करना।
- समय-समय पर तकनीकी सेमिनार एवं गोष्ठियों का आयोजन कराना।

भारतीय रेल वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान

रेल इंजनों के उत्पादन में फेब्रिकेशन एवं वेल्डिंग एक महत्त्वपूर्ण विधा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र में वर्ष 2002 में क्षेत्रीय वेल्डिंग संस्थान की स्थापना की गई। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत उच्च अश्वशक्ति के रेल इंजन निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए इस संस्थान में 13 अप्रैल, 2016 को भारतीय रेल वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया गया। यह संस्थान रेलवे के क्षेत्रीय वेल्डिंग संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए वेल्डिंग प्रशिक्षण हेतु भारतीय रेल की सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करता है। इस संस्थान में वेल्डिंग क्षेत्र की आधुनिक तकनीक की विभिन्न मशीनरी एवं प्लांट तथा प्रायोगिक, निरीक्षण एवं टेस्टिंग उपकरण उपलब्ध है। इस संस्था द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंतर्गत डीरेका, क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और वेल्डर तकनीशियनों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

डीरेका की वेल्डिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने हेतु भारतीय रेल वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान ने आईएसओ 3834-2:2015 (अंतरराष्ट्रीय मानक) का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान, डीरेका, वाराणसी आईएसओ 9606-1 मानक के अनुसार वेल्डर क्वॉलिफिकेशन टेस्ट आयोजित कर सफल कर्मचारियों को प्रमाणपत्र प्रदान करता है। यह प्रमाणपत्र विशेष योग्यता प्राप्त (अंतरराष्ट्रीय वेल्डिंग इंजीनियर) अधिकारी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रोबेशनर्स/अधिकारियों एवं क्षेत्रीय रेल के पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों के ठहरने हेतु अधिकारी एवं अधीनस्थ विश्राम गृह का संचालन भी प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है।

विशेष कार्य

डीरेका में विद्युत रेल इंजनों के निर्माण का कार्य वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया। डीजल रेल इंजन निर्माण में निपुण कर्मचारियों को विद्युत रेल इंजनों के निर्माण में निपुणता प्रदान करने के लिए प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा विशेष प्रशिक्षण अभियान के द्वारा लगभग 359 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान



प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र



वेल्ड लैब



वेल्डिंग वर्कशॉप



विद्युत रेलइंजन (डब्ल्यूएपी-7) का रनिंग मॉडल

किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा एक नवनिर्मित विद्युत रेल इंजन (डब्ल्यूएपी-7) के रनिंग मॉडल का भी निर्माण किया गया। इस मॉडल को रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया एवं सराहा गया।

डीरेका ने विश्व में प्रथम बार डीजल लोको को उच्च शक्ति वाले विद्युत लोको में बदलकर अपने स्वर्णिम इतिहास में एक और नया अध्याय लिखा है। प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र ने पर्यवेक्षकों एवं तकनीशियनों को एक अभियान चलाकर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर इस साहसिक अवधारणा को साकार करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षुओं को प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र में फिटर, मशीनिष्ट, वेल्डर एवं इलेक्ट्रीशियन/इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में 265 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 'स्वच्छ भारत अभियान' के अंतर्गत प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 से निरंतर स्वच्छता अभियान प्रत्येक शनिवार को चलाया जाता है, जिसके अन्तर्गत स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण के क्षेत्र में कर्मचारियों में जागरुकता बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है। ■

FOR YOUR UTMOST SAFETY & COMFORT



WE BELIEVE TRUST TO BE THE ONLY FACTOR BEHIND LONG TERM RELATIONSHIP AND GROWTH. AND TRUST COMES BY DELIVERING QUALITY AND A GREAT CUSTOMER EXPERIENCE.

KAY KAY INDUSTRIES
IN SERVICE SINCE 1962
A MANUFACTURER OF INDUSTRIAL SAFETY SHOES & BOOTS

CONTACT US AT:
EMAIL: KKISAFETYSHOE1962@YAHOO.COM
M: +91 8707489967
O: 0512 2212984
F: 0512 2220023

WWW.KAYKAYINDUSTRIES1962.COM


"Growth is never a mere chance,
It is the result of forces
working together"
- James Cash Penny
RADIO ADs
AIR BIG
FEVER
RED
BRANDINGS
SHOP
WALL
PRINT MEDIA
NEWSPAPERS
MAGAZINES
FLEX
ECO SOLVENT
PRINTINGs
DIGITAL
OFFSET
OOH MEDIA
BILLBOARDS
RAILWAYS
SHELTERS
CNC
LASER
CUTTING
VINYL
RETRO
CINEMA ADs
PVR
UFO
QUBE
LED
SHOP
BOARDS
DIGITAL ADs
GOOGLE
FACEBOOK
TWITTER
AN ISO 9001:2015 CERTIFIED
R D ADVERTISING
PRIVATE LIMITED
Regd. Office :
257 Chak, Zero Road, (Infront of Bus Station), Prayagraj 211 003
Ph : 532 - 2564149, 2564542 | M. : +91-9935597073 / 74 / 75
rdadvertising.09@gmail.com
www.rdadvertising.org
Branches : New Delhi | Lucknow | Varanasi | Gorakhpur | Jabalpur
Bhopal | Jaipur | Nagpur | Bhubaneswar

हीरक जयंती वर्ष

रेल, पर्यटन व साहित्य को एक साथ संजोये
रेल मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक मात्र हिन्दी मासिक पत्रिका



भारतीय रेल

आज ही सदस्य बनें



सदस्यता फॉर्म

नाम .....

पता .....

पोस्ट..... जिला.....

राज्य..... पिन कोड .....

मोबाइल ..... ई-मेल .....

वार्षिक सदस्यता	सर्व साधारण	रेलकर्मी	विशेषांक	एक प्रति
एक वर्ष	₹100*	₹90*	₹40	₹10
दो वर्ष	₹200*	₹180*	₹40	₹10
तीन वर्ष	₹300*	₹270*	₹40	₹10

* विशेषांक के साथ

रेल कर्मचारी ..... हाँ/नहीं वर्तमान सदस्यता (हो तो) संख्या ..... तारीख .....

देय राशि : डी.डी. ..... चेक ..... मनी ऑर्डर ..... पोस्टल ऑर्डर .....

डीडी/चेक/म.ओ./पो.ओ. नंबर ..... स्थान ..... रुपये ..... दिनांक .....

(डी.डी./चेक/म.ओ./पो.ओ. देय - 'व्यापार प्रबंधक, भारतीय रेल, नई दिल्ली')

संपर्क

337-बी, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली - 110001
(011) 23382531/23303665/23304456 (रेलवे नं. 43665, 44456)
ई-मेल : editorbhartiyarailrb@gmail.com

सदस्यता-फॉर्म की फोटोकॉपी मान्य है

चेक भी स्वीकार्य हैं

आप सब का

भारतीय रेल

के साथ अटूट रिश्ता है

भारतीय रेल के साथ आप अपने
संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, गीत, आदि लेख
हिन्दी में हमें भेजें। पसंद आने पर
रचनाओं को हम रेल मंत्रालय की
आधिकारिक मासिक पत्रिका
'भारतीय रेल'
में प्रकाशित करेंगे।

ई-मेल: editorbhartiyarail1@gmail.com

पसंद किये गये लेख की जानकारी ई-मेल से दी जाएगी।
प्रकाशित होने पर मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदेय भी दिया जाएगा।

शर्तें लागू

पंजीयन संख्या : दिल्ली पोस्टल नं. डी.एल. (एन.डी.)-11/6031/2018-19-20
आर.एन.आई. रजिस्टर्ड नं. 14427/1960
आई.एस.एस.एन. 2457-0001
दिनांक 08 को प्रकाशित तथा दिनांक 10-11 को प्रेषित



Coaches & Trainsets

Air Conditioners with Micro-processors

Bio Vacuum Toilet Systems

FRP Toilet Cubical

Side Panels and Roof Panels for Coach Interiors

Seats and other Accessories for Coach Interiors

Diesel Locomotives

Traction Alternators

Traction Motors

Radiator Cooling Fans

Dynamic Brake Grids

Dynamic Brake Blower Motors

Auxiliary Generators

Dustbin Blower & Motor

Driver Cab Air Conditioners

Electric Locomotives

Traction Motors

Traction Transformers

Pantographs

Harmonic Filters

Driver Cab Air Conditioners

Daulat Ram ENGINEERING

10/2, NH-12, Simrai, Post Obedullahganj, Dist. Raisen, Near Bhopal 464 993 INDIA
Tel.: +91 7480 231400 / 252 / 253, 8889000732 / 34 / 35 / 36. Fax: +91 7480 231250
e-mail: info@daulatram.org • web: daulatram.com

मुद्रक व प्रकाशक : **प्रशान्त कुमार पट्टनायक** द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के लिए मैसर्स जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.ली., बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-20 में मुद्रित व 310, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली से प्रकाशित। संपादक : **योगेश अवस्थी**